3 राजधानी
आस्पताल से लापता होने पर एफआईआर

6 अभिमत
श्रम कानूनों में व्यापक परिवर्तन

10 स्पोर्ट्स
द. अफ्रीका के दावे को बीसीसीआई ने नकारा

11 विदेश
कोरोना को लेकर विरोधियों पर बरस रहे ट्रंप

RNI NO. DELHI/2012/48369
वर्ष 8 अंक 198
नई दिल्ली, शनिवार, 23 मई, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

श्रेष्ठ कंटेंट पर ही रहता है हमारा पूरा जोरः अनुष्का
विविध-12

www.dailypioneer.com

पहली दफा लामबंद विपक्ष ने तरेरी आंख

एक मंच पर इकट्ठा हुए 22 दलों के नेता, आर्थिक पैकेज को खारिज किया, राज्यों को पर्याप्त अधिकार देने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- मानवीय संकट और महामारी से निपटने के मोदी सरकार के तौर तरीके पर उठाए सवाल
- 11 सूत्रीय प्रस्ताव किया पेश, बसपा, सपा और आप नेताओं ने बैठक में नहीं लिया भाग

'लॉकडाउन' मोड से निकलने का संकेत देते हुए शुक्रवार को 22 विपक्षी दल एक मंच पर इकट्ठा हुए और मोदी सरकार से मानवीय संकट समेत कोविड-19 महामारी से निपटने के उसके तौर तरीके पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने कहा कि सभी शक्तियां अब पीएमओ में केंद्रित हो गई है तथा संघवाद की भावना जो हमारे संविधान का अभिन्न अंग है उसे भुला दिया गया है।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिये विपक्षी नेताओं से संवाद करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर देश में मौजूदा हालात से सही ढंग से न निपटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'संघवाद' की मूल भावना को भुला दिया गया क्योंकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय में निहित हो गई हैं। विपक्षी दलों ने मांग करते हुए कहा कि केंद्र एक संशोधित और समग्र पैकेज लेकर आए जो सही मायनों आर्थिक राहत होगी जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 11 सूत्रीय प्रस्ताव पेश करते हुए विपक्षी नेताओं में जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन तथा एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत अन्य शामिल थे, ने एक संयुक्त बयान में कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के वृहत पैकेज का ऐलान किया गया लेकिन संकट का सामना कर रहे लोग खासतौर पर प्रवासी जो अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए इसमें कुछ नहीं है।

नेताओं ने यह भी मांग की कि बगैर भोजन और पानी के सड़कों पर चल रहे मजदूरों को मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि केंद्र अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को अनुमति देने के साथ राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श करे और उन्हें पर्याप्त अधिकार दे। विपक्ष ने यह भी कहा 'स्पष्ट और सार्थक आर्थिक रणनीति पेश की जाए जो प्रचार-प्रसार के लिए न होकर गरीबी दूर करने पर केंद्रित हो। 20 लाख करोड़ का पैकेज और उसके तथ्यों ने भारत की जनता को गुमराह किया है। गांधी ने कहा कि बहुत से जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने 2020-21 को नकारात्मक विकास दर के साथ समाप्त होने की आशंका जताई है। परिणाम भयावह होंगे।

बैठक में भाग लेने वाले शीर्ष विपक्षी नेताओं में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, द्रमुक के एमके स्टालिन, माकपा के सीताराम येचुरी शामिल थे। बैठक में विचार व्यक्त करने वाले अन्य नेताओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे. अहमद पटेल, एचडी देवगौड़ा (जदएस), तृणमूल से डेरेक ओ ब्रायन, प्रफुल्ल पटेल (एनसीपी), थिरू स्टालिन (द्रमुक), संजय राउत (शिवसेना), डी राजा (भाकपा), शरद यादव (एलजेडी), तेजस्वी यादव और मनोज झा (राजद), जयंत चौधरी (रालोद), उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएसपी), जतिन राम मांझी (एचएएम) शामिल थे। बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी (आप) ने बैठक में भाग नहीं लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरू में वायरस के खिलाफ जंग 21 दिन में खत्म होने की उम्मीद थी जो सही साबित नहीं हुई। इस बैठक में चर्चा की शुरुआत से पहले नेताओं ने दो मिनट का मौन रख 'अम्फान' चक्रवात के कारण मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। फिर एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा को मदद दी जाए। विपक्ष की यह वर्चअुल बैठक 25 मार्च को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के करीब दो माह बाद हुई है।

सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास कोई समाधान नहीं है यह चिंताजनक है लेकिन गरीब और हाशिये पर जी रहे लोगों के प्रति कोई भावना या चिंता न होना दिल तोड़ने वाला है।' उन्होंने आरोप लगाया, ''सरकार ने खुद के लोकतांत्रिक होने का प्रदर्शन करना भी बंद कर दिया है। सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित हो गई हैं। संघवाद की भावना जो हमारे संविधान का अभिन्न भाग है, उसे भुला दिया गया है। इसका कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों की बैठक कब बुलाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के साथ बगैर पैसे, भोजन और दवा के लाखों प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर जा रहा है, जो इस महामारी की भयावह तस्वीर को पेश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पांच दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ। बैठक में श्रमिकों के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा की (शेष पेज 9)

कोरोना संकट के तीन माह

कराची के रिहाइशी इलाके में गिरा विमान, 45 की मौत

कराची में विमान दुर्घटस्तल पर पड़ा मलवा।

- एयरपोर्ट के करीब हुआ भीषण हादसा

भाषा। कराची

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) का एक यात्री विमान शुक्रवार को यहां जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहाइशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे कम से कम 37 लोगों की मौत होने की खबर है। विमान में 107 लोग सवार थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उड़ान संख्या पीके-8303 लाहौर से आ रही थी और विमान कराची उतरने ही वाला था कि एक मिनट पहले मालिर में मॉडल कालोनी के निकट जिन्ना गार्डन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रीय विमानन कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पीआईए एयरबस ए320 में 99 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य सवार थे। विमान हवाईअड्डे के निकट जिन्ना आवासीय सोसाइटी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

सिंध के स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 37 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डान (शेष पेज 9)

मोदी ने पाक विमान दुर्घटना पर शोक जताया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति शुक्रवार को शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। समझा जाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (विमान) के एक विमान के कराची में जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई है। इस विमान में (शेष पेज 9)

मोदी ने देखी चक्रवात प्रभावित बंगाल, ओडिशा की तबाही

- दिया 15 सौ करोड़ का राहत पैकेज

भाषा। कोलकाता, भुवनेश्वर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवात अम्फान के कारण बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बाद स्थिति की समीक्षा कर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए 1,500 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की।

इस चक्रवात के कारण कम से कम 80 लोगों की जान चली गई, हजारों हेक्टेयर जमीन में तैयार फसलें बर्बाद हो गईं और अवसंरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। मोदी ने चक्रवात के दो दिन बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के साथ स्थिति की समीक्षा की। कई वर्ष के इस सबसे भयंकर चक्रवात ने उनके राज्यों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की जो प्रवासी मजदूरों की वापसी के अलावा पहले से ही कोविड-19 के मामलों और मौत का दंश झेल रहा है।

हालांकि, बनर्जी ने कहा कि राज्य को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है जिसके लिए उसे मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया जो बुधवार को अत्यधिक वर्षा (शेष पेज 9)

दिल्ली में फटा कोरोना बम एक दिन में 660 नए केस

- संक्रमित मरीज 12 हजार के पार कंटोनमेंट जोन की संख्या फिर बढ़ी
- एक दिन में 14 मरे, सीआरपीएफ के एएसआई की भी मौत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी में शुक्रवार को एक दिन में रिकार्ड 660 नए कोरोना के मरीज पॉजिटिव आए हैं।

इसके साथ ही षहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 12319 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14 कोरोना मरीजों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 208 पहुंच गया है। राजधानी में अब तक 5897 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस तरह अब 6214 एक्टिव मामले हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद जहां दिल्ली की सड़कों पर जाम और बाजारों में भीड़ की खबरें छायी हैं, वहीं कोरोना के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

इससे पहले बृहस्पतिवार को 571 नए मामले आए थे। यह एक दिन में सर्वाधिक आंकड़ा था। इससे पहले बुधवार को (शेष पेज 9)

कोरोना के 80 फीसद मामले दिल्ली समेत पांच राज्यों में

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश के कुछ ही इलाकों में ही ज्यादा दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लगभग 80 प्रतिशत केस पांच राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से हैं। सरकार ने दो स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों के मॉडल के आधार पर यह भी दावा किया है कि लॉकडाउन के कारण लगभग 68,000 मौतों को टाला गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार दोपहर एक बजे तक कोविड-19 की 27,55,714 जांच की गई है। एक दिन में 1,03,829 नमूनों की जांच हुई। एक दिन में कोविड-19 के 3,234 मरीज ठीक हुए और अब तक 48,534 मरीज ठीक हो (शेष पेज 9)

क्वॉरंटीन सुविधाएं छोड़ने का निर्देश, कोरोना वॉरियर्स नाराज

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा- सुविधा वापस लेने से परिवार, रोगियों और सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए निर्देष दिया है कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले जिन स्वास्थ्य पेषेवरों, डॉक्टरों में इस बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वे क्वॉरंटीन केंद्रों की सुविधाएं छोड़ दें। मंत्रालय के इस फरमान पर कोरोना वॉरियर्स ने कड़ा ऐतराज जताया है।

पहले के दिषानिर्देषों में कहा गया था कि कोविड-19 वार्डों में कार्यरत सभी डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को लगातार 14 दिन काम करना होगा और अगले 14 दिनों तक वे क्वॉरंटीन सेंटर में रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संक्रमण का षिकार नहीं हुए हैं। हालांकि, 15 मई को जारी नए दिषानिर्देषों में कहा गया है कि कोविड-19 ड्यूटी के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की क्वॉरंटीन केंद्र में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट या किसी अन्य में उपकरण में खामी के चलते उन्हें खतरा होने की आषंका न हो।

हालांकि, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इन नई गाइडलाइन का षुक्रवार को काला रिबन बांधकर कड़ा विरोध किया है और कोविड-19 ड्यूटी करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उचित क्वॉरंटीन (शेष पेज 9)

हर्षवर्धन ने डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

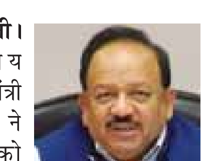

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को 34-सदस्ईय डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हर्षवर्धन कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हर्षवर्धन ने जापान के हिरोकी नकातानी का स्थान लिया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक जताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अपनी टिप्पणी में हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा संकट से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाने और साझा प्रतिक्रिया की आवश्यकता (शेष पेज 9)

बाजार

संेंसेक्स	30,672	↓	260
निफ्टी	9,038	↓	67
सोना			/10g
चांदी			/kg

क्विक न्यूज

विशेष ट्रेनों में करवा सकते हैं 30 दिन की अग्रिम बुकिंग

नई दिल्ली। भारतीय रेल द्वारा राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों मे यात्री अब 30 दिन की अग्रिम बुकिंग करा सकते है। इसकी टिकटें आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अलावा टिकट काउंटरों पर भी उपलब्ध होगी। पहले केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग अब कम्प्यूटराइज्ड पीआरएस केन्द्रों, डाकघरों, यात्री टिकट सुविधा केन्द्रों के साथ-साथ आईआरसीटीसी के मान्यता प्राप्त एजेंटों और सामान्य सेवा केन्द्रों से भी कराई जा सकती है। भारतीय रेल ने कहा है, इन ट्रेनों में अग्रिम सीटें आरक्षित कराने की अवधि सात दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है।

आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की बदरंग तस्वीर दिखाई

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई

- विकास दर नकारात्मक रहेगी महंगाई बढ़ेगी और मांग घटेगी, फिर ब्याज दर में कटौती कर्ज किस्तों पर तीन माह की और छूट

कोरोना वायरस के कारण सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने निराशाजनक तस्वीर पेश की है। आरबीआई ने विकास दर में गिरावट और उच्च मुद्रास्फीती दर का अनुमान लगाते हुए शुक्रवार को एक बार फिर प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.40 प्रतिशत की अप्रत्याशित कटौती की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में मांग में जबरदस्त गिरावट आई है।

पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू खपत घटी है। उन्होंने कहा कि मार्च में औद्योगिक उत्पादन घटकर 17 फीसदी तक आ गया तथा निर्माण गतिविधियों में 21 फीसदी तक गिरावट आई है। इसके साथ ही आरबीआई ने कर्जदारों को कर्ज की किस्त चुकाने से तीन माह की और छूट दे दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से भारत की (शेष पेज 9)

कुएं से पांच और शव बरामद, एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत

वारंगल (तेलंगाना)। तेलंगाना में एक कुएं से नौ लोगों के शव मिलने के पीछे का रहस्य गहराता जा रहा है। इनमें से छह व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य थे। चार लोगों के शव बृहस्पतिवार को और पांच लोगों के शव शुक्रवार को मिले हैं। थैले बनाने वाली इकाई में काम करने वाले 48 वर्षीय एक व्यक्ति और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों के शव गोरेकुंटा गांव के कुएं से मिला था। इसके बाद पांच अन्य शव भी कुएं से बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि घर के मुखिया के दो बेटों के शव भी शुक्रवार को मिले। वारंगल के पुलिस आयुक्त वी रविंद्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एक ही परिवार के छह लोगों और उनके एक दोस्त तथा दो अन्य व्यक्तियों के शव कुएं से मिले हैं। पुलिस ने (शेष पेज 9)

दिल्ली में भी मजदूरों पर कीटनाशक का स्प्रे

श्रमिक ट्रेन में रजिस्ट्रेशन के लिए लाजपतनगर थ्री में जुटे थे, सैनिटाइजेशन करते एसडीएमसी कर्मियों ने नहलाया

- स्टैंडिग कमेटी चेयरमैन का दावा-स्प्रे खतरनाक नहीं, स्वीमिंग पूल में होता है इस्तेमाल, तेज धार से जरूर लग सकती है चोट
- दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने स्टाफ को दिया निर्देश-आइंदा छिड़काव के दौरान न हो ऐसी लापरवाही, पहले करें घोषणा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के बरेली के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मजदूरों पर कीटनाशक दवा के छिड़काव की घटना सामने आई है। प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेन में पंजीकरण कराने के लिए लाजपतनगर में जुटे हुए थे। इलाके का सैनिटाइजेशन कर रहे दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) कर्मचारियों ने सड़कों-मकानों के साथ वहां बस का इंतजार करते मजदूरों के गुट पर भी कीटनाशक की तेज धार छोड़कर उन्हें सराबोर कर दिया।

पायनियर संवाददाता ने जब इस घटना के बारे में एसडीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें मीडिया रिपोर्ट के जरिये ही मिली है। मामले से अवगत होते ही उन्होंने निगम कर्मचारियों को तत्काल निर्देश जारी कर कहा कि आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिस किसी भी इलाके में सैनिटाइजेशन प्रक्रिया के तहत कीटनाशक का छिड़काव किया जाना है वहां पहले घोषणा कर लोगों को इसके बारे में बता दें ताकि वे बीच रास्ते से हटकर इधर-उधर हो जाएं। भूपेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि जिस कीटनाशक का छिड़काव किया गया है वह त्वचा अथवा शरीर के अन्य हिस्सों के लिए जरा भी हानिकारक नहीं है। यह सोडियम (शेष पेज 9)

कोरोना के कारण अटके भाजपा संगठन के चुनाव

जल्द शुरू होगी प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया

बराला, धनखड़ और नायब सैनी दौड़ में सबसे आगे

संगठन मंत्री पद पर बदलाव तय

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

कोरोना के कारण बीच में अटके हरियाणा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया अब दोबारा जल्द शुरू होगी। प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में शामिल भाजपा के नेताओं ने लॉकडाउन छूट मिलने के बाद जहां दिल्ली दरबार में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है वहीं जिला अध्यक्ष के लिए भी भागदौड़ शुरू हो चुकी है।

हरियाणा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस साल जनवरी माह के दौरान संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके चलते पार्टी ने सक्रिय कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तथा बूथ प्रमुखों का चुनाव किया। इसके बाद फरवरी माह के दौरान मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया भी पूरी हो गई। पार्टी नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके लिए जिला स्तर पर सभी दावेदारों के बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया और लगभग सभी जिलों से अध्यक्षों के नाम भी फाइनल हो गए।

इस बीच 17 मार्च को हरियाणा में कोरोना का पहला मामला सामने आया और 23 मार्च से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के चलते सभी नेता अपने-अपने घरों तक सीमित हो गए और पार्टी का संगठन चुनाव टल गया।

जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है लेकिन घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अब लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद प्रदेश में फिर से राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, भाजपा सांसद नायब सैनी तथा वर्तमान अध्यक्ष सुभाष बराला ने फिर लॉबिंग शुरू कर दी है।

भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष के साथ-साथ संघ के कोटे से आने वाले संगठन मंत्री पद पर भी बदलाव की तैयारी कर ली है। निवर्तमान संगठन मंत्री सुरेश भट्ट के विदा होने के बाद इस पद हरियाणा में संघ के विभाग प्रचारक के रूप में सक्रिय एक नेता तथा एक अन्य बाहरी नेता प्रबल दावेदार हैं। पार्टी नेतृत्व द्वारा दोनों में से किसी एक नाम को जल्द ही फाइनल किया जा सकता है।

टीम नड्डा में भी हरियाणा को मिलेगा प्रतिनिधित्व

एक तरफ जहां हरियाणा भाजपा के चुनाव को लेकर गतिविधियां दोबारा शुरू हो गई है वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में शामिल होने को लेकर भी नेताओं की लॉबिंग शुरू हो गई है। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे पार्टी नेता चुनाव हारने के बाद अब संगठनात्मक रूप से खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। हरियाणा से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने वालों में करनाल के सांसद संजय भाटिया का नाम सबसे उपर है। इसके अलावा अगर धनखड़ को प्रदेश में नेतृत्व नहीं मिलता है तो उन्हें तथा कैप्टन अभिमन्यु को पहले की तरह संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिल सकता है। इसके अलावा पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा भी राष्ट्रीय संगठन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

संघ चाहता है फुल टाइम अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने नए भाजपा अध्यक्ष के लिए अपने सुझाव हाईकमान तक पहुंचा दिए हैं। संघ का मानना है कि सत्ता व संगठन में तालमेल के अभाव के चलते पिछले चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से दूर रही है। जिसके चलते संघ चाहता है कि हरियाणा में भाजपा का नया अध्यक्ष ऐसा है जो पूर्णकालिक प्रवास पर रहे। संघ का प्रस्ताव है कि किसी युवा और पूर्णकालिक नेता को पार्टी की कमान सौंपी जाए।

असम व अरुणाचल प्रदेश के लिए लगभग 160 प्रवासी मजदूरों को भेजा

पायनियर समाचार सेवा। कैथल

उपमंडलाधीश कमलप्रीत कौर ने कहा कि निरंतर सरल पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में जाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन आते ही प्रशासन द्वारा समूचित व्यवस्था की जाती है और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

शुक्रवार को भी असम व अरुणाचल प्रदेश के लिए पंजीकृत 160 प्रवासी मजूदरों को फोन से संपर्क करके उन्हें राधा स्वामी सत्संग भवन में बुलाया। इस जगह पर प्रशासन द्वारा खाने-पीने और रहने की समूचित व्यवस्था की गई है। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों पर पिछले दिनों से निरंतर भेजने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर भिजवाया। उपमंडलाधीश कमलप्रीत कौर ने कहा कि असम जाने वाले सभी प्रवासी मजदूरों की पहले स्वास्थ्य चेकअप किया। इसके बाद बच्चों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गो का पूरा ध्यान रखा गया। असम के लिए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें गुरुग्राम भेजा गया, जहां से रेलवे के माध्यम से वे अपने घर पहुंच सके। कैथल प्रशासन द्वारा रेलवे प्रशासन से प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए संपर्क किया और पूरे तालमेल से कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी प्रवासी मजूदर सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। प्रवासी मजूदरों से बातचीत करने पर उन्हें उपमंडलाधीश कमलप्रीत को उनके घर भेजने पर आभार जताया।

प्रवासी मजदूरों को घर भेजते एसडीएम।

प्रवासियों के पलायन से संकट में हरियाणा के किसान

किसान इस बार धान की सीधी बिजाई को दे रहे तरजीह

सरकार के फैसले के बाद धान उत्पादकों ने अपनाई नई राह

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

एक तरफ हरियाणा से लाखों प्रवासियों का पलायन और दूसरी तरफ धान की पैदावार को लेकर हरियाणा सरकार की सख्ती। ऐसे में किसानों ने नया रास्ता निकालते हुए धान की सीधी बिजाई की तैयारी कर ली है। सीधी बिजाई से किसानों की कई समस्याओं का समाधान होगा।

हरियाणा में इस सीजन के दौरान धान की रोपाई को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हरियाणा सरकार उत्तरी हरियाणा के सात जिलों में धान की रोपाई पर रोक लगा चुकी है। सरकार इन जिलों में किसानों की निगरानी कर रही है। दूसरी तरफ इस साल कोरोना के चलते हरियाणा से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन कर चुके हैं। गेहूं की कटाई तो मशीनों से हो जाती है लेकिन धान की रोपाई अथवा पनीरी तैयार के लिए मजदूरों की जरूरत होती है। प्रवासियों के पलायन से धान का सीजन खतरे में है।

किसान भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली की तकनीक सीधी बिजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसानों ने मशीनों के जरिए सीधी बिजाई की तैयारी कर ली है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के मीडिया प्रभारी राकेश बैंस के अनुसार धान की रोपाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की जरूरत होती है। पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच श्रमिक अपने-अपने गृह राज्यों की तरफ पलायन कर चुके हैं। किसान को धान की रोपाई करने के लिए श्रमिक नहीं मिल रहे। इसलिए किसानों ने धान की रोपाई की बजाए सीधी बिजाई का निर्णय लिया है।

क्या है सीधी बिजाई की तकनीक

आईसीएआर के अनुसार सीधी बिजाई में धान की सभी किस्म कामयाब हैं। यह बिजाई शाम के समय करनी होती है। विशेषज्ञों का प्रस्ताव है कि धान की सीधी बिजाई 20 से 31 मई तक की जा सकती है। क्योंकि इसके बाद कम से कम 10 दिन सूखे मौसम की जरूरत होती है। धान की बिजाई के लिए प्रति एकड़ 7 से 8 किलो बीज लगता है। गहरी जुताई के बाद सिंचाई और नमी पर बीज ड्रिल व छींटा विधि से बिजाई की जाती है। कृषि अनुसंधान के मुताबिक अगर बिजाई के 7 दिन में बरसात हो तो जमीन की सख्त परत तोडने् के लिए सिंचाई करें। अन्यथा पौधे बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर 10 दिन बाद सिंचाई करें और तुरंत छिडक़ाव करें। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार धान की पौध लगाकर फसल लगाने में खपतवार का खतरा कम रहता है। मगर सीधी बिजाई से यह खतरा अधिक बन जाता है। पर इसे नियंत्रण में करने के लिए बिजाई के तुरंत बाद छिडक़ाव किया जाता है।

लापता व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पश्चिमी यमुना नहर से बरामद

रादौर। पश्चिमी यमुना नहर में पक्का घाट के समीप एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला। जिसकी पहचान रादौर की वाल्मिकी बस्ती निवासी वीरकरण के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और अब कई दिनों से घर से गायब था जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया।

शुक्रवार की सुबह आसपास के लोगों को एक व्यक्ति का शव नहर में पड़ा हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना रादौर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराई तो पता चला कि मृतक व्यक्ति का रादौर की बाल्मीकि बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दी और उसके बारे में जानकारी जुटाई जिसमें पता चला कि मृतक व्यक्ति वीर करण पिछले कई दिनों से घर से गायब था। जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे, लेकिन आज वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया।

कोरोना से ठीक होने की रिकवरी रेट 63 प्रतिशत से ज्यादा : सांसद

पायनियर समाचार सेवा। कैथल

सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर कार्य करते हुए प्रदेश वासियों को इस महामारी से बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में रह रहे जिन व्यक्तियों के पास कोई भी कार्ड नहीं है, डिस्ट्रेस टोकन के माध्यम से उन्हें भी मुफ्त में राशन मुहैया करवाया गया है। यहां रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह क्षेत्र में भेजने की समूचित व्यवस्था भी की गई है।

सांसद नायब सैनी ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की रिकवरी रेट 63 प्रतिशत से भी ज्यादा है। गत 18 मई से आमजन को सुविधा व व्यापारिक गतिविधियां चलाने के लिए सर्शत छूट दी गई है। सभी को मास्क, सामाजिक दूरी आदि का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज से प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जाएगी। छोटे उद्योग कर्मियों के लिए अलग से ऐसी योजनाएं बनाई जाएगी, जिनसे उन्हे भरपूर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में 600 से ज्यादा शैल्टर होम में समूचित व्यवस्था करके प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया, जहां पर उनके स्वास्थ्य जांच व खाना आदि की व्यवस्था की गई।

उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में 27 लाख परिवारों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दो करोड़ 62 लाख खाने के पैकेट वितरित किए और 12 लाख से ज्यादा सूखे राशन की किटें भी वितरित की गई। प्रवासी मजदूरों की हर संभव मदद की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क उनके गृह क्षेत्रों में भिजाया जा रहा है। दो लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अब तक घर पहुंचाया जा चुका है। व्यवस्था के तहत 53 रेल व और 4257 बसें चलाई गई। सांसद ने कहा कि शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों को 3 महीनें के ब्याज से राहत दी जाएगी, जिसके तहत लगभग 36 हजार छात्रों को 40 करोड़ के करीब राशि का लाभ मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

गुरुग्राम में कोरोना से हुई दूसरी मौत, शुक्रवार को आए 10 नए केस

गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला में शुक्रवार को कोरोना से लगातार दूसरे दिन दूसरी मौत हो गई। 11 नए केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक की मौत शामिल है। अब यहां कुल केस 250 हो गए हैं। चार केस पटौदी क्षेत्र से पॉजिटिव आए हैं। गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव की पहली मौत की बात स्वास्थ्य विभाग द्वारा कही गई। अब शुक्रवार को दूसरे दिन एक और मौत कोरोना से हो गई। मृतक राजेंद्रा पार्क का रहने वाला था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में इसकी पुष्टि की गई है। शुक्रवार को 11 पॉजिटिव केस आए, जिनमें एक की मौत हुई है। इन केसों में 4 केस पटौदी के गांव डाडावास से हैं। एक केस सेक्टर-28 चकरपुर से, एक केस पटौदी से, एक केस कादीपुर से, एक केस सरहोल से, एक केस धर्म कालोनी पालम विहार से और एक केस डूंडाहेड़ा से है। अब जिला में कुल 250 केस पॉजिटिव हो गए हैं। जिनमें से 140 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 110 उपचाराधीन हैं। गुरुग्राम में अब तक 11156 सेंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 10644 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 250 की रिपोर्ट पॉजिटिव है और 262 के सेंपल की रिपोर्ट का इंतजार है।

कैथल से पूंडरी चलेगी बस

कैथल। रोडवेज ट्रैफिक मैनेजर कंवलजीत सिंह ने बताया कि कैथल से पूंडरी मार्ग पर दो समय आवागमन के लिए बस सेवा शनिवार से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत कैथल से प्रात: 10 बजे करनाल चौक से बस चलेगी। सवारियों को मैनुअल टिकट दी जाएगी। इसी प्रकार पूंडरी बस स्टैंड के बाहर से सायं 3 बजे बस सेवा का संचालन होगा। सुरक्षा के दृष्टिगत बस को सैनेटाईज करने की समूचित व्यवस्था की गई है। केवल 30 सवारियों को ही बस में बिठाया जाएगा और सभी सवारियों की थर्मल स्कैनिंग जांच करने के बाद ही उन्हें टिकट देकर बस में बैठाया जाएगा। यह बस पूंडरी व कैथल बस स्टैंड के अंदर नहीं जाएगी।

आवर्धन नहर में डूबने से किसान की हुई मौत

इंद्री। उपमंडल के गांव करतारपुर के रहने वाले करीब 25 वर्षीय किसान मोहित की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक शादीशुदा था ओर उसकी दस महीने की एक लड़की है। मिली जानकारी के अनुसार किसान मोहित अपने बड़े भाई राहुल के साथ खेतों में काम कर रहा था। शाम करीब 7 बजे वह पानी लेने के लिए आवर्धन नहर की ओर गया। जैसे ही मोहित पानी लेने के लिए नहर में उतरा तो उसका पैर फिसल गया जिससे वह नहर में डूब गया। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने गोताखोरों की मदद से उसके शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।

पालतू जानवर भूख-प्यास से न मरे, मालिक रखे विशेष ध्यान

करनाल। पालतू जानवरों में क्रूरता की कमी लाने के लिए उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। लॉकडाउन के दौरान कुछ मामले पालतू जानवरों में क्रूरता के सामने आए हैं। इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है, पालतू जानवरों जैसे कुत्तों में क्रूरता में कमी लाने के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड और पशु क्रूरता की दिशा में काम करने वाले सामाजिक लोगों की अहम भूमिका है। जिले में इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी पालतू जानवर भूख व प्यास से न मरे। उपायुक्त ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियम के तहत पालतू जानवरों जैसे कुत्ते के प्रजनन के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड ने निर्देश दिया है कि उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ऐसा होने से पालतू जानवरों का आंकड़ा सबके समक्ष रहेगा और उनकी स्थिति पर पूरा ध्यान केन्द्रित रहेगा, ऐसा होना जनहित का कार्य भी है। उन्होंने पालतू जानवरों के सभी मालिकों से आग्रह किया है कि जिन लोगों ने अपने घरों में पालतू जानवर रखे हैं वे लोग उनका पंजीकरण अवश्य कराएं और उनके भोजन-पानी की पूरी व्यवस्था रखें। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 2017 व 2018 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संबंधित कार्यों पर अपनी निगरानी रखें।

शुक्रवार को प्रेसवार्ता में पत्रकारों जानकारी देते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला।

क्रेद्र करेगा कलस्टर लॉस की भरपाई : दुष्यंत

सरकार ने करीब 70 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं खरीद, करीब नौ हाजर करोड़ रुपये का किया भुगतान

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

अब प्रदेश के किसानों को बारिश की वजह से खराब हुए फसल के दाने (कलस्टर लॉस) का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, इस नुकसान की पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। प्रदेश सरकार के आग्रह पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसकी जानकारी प्रदेश उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला लिया है कि बरसात के कारण खराब हुए फसल के दाने का नुकसान किसानों को नहीं होगा बल्कि इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से यह मांग की थी कि लस्टर लॉस का नुकसान किसानों से न लिया जाए, जिसके बाद आज केंद्र ने लस्टर लॉस की भरपाई खुद करने का निर्णय लिया है।

किसानों की फसल खरीद, उठान व भुगतान के बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि अब तक प्रदेश में करीब 70 लाख मीट्रिक टन तक की गेहूं खरीद कर ली है तो वहीं करीब 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान कार्य भी पूरा किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं खरीद का करीब 9 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करते हुए आढ़तियों के खाते में पैसे डाल दिए है और इसमें से आगे 6270 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों के पास पहुंच गये है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई मंडियों में उठान प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर सरकार ने गेहूं उठान प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि अधिकारी खरीद एंजेसियों द्वारा अगले तीन दिनों में मंडियों में पांच दिन से पुराना जितना भी गेहूं पड़ा है उसका जल्दी से उठान करवाएं अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी। वहीं उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को वापस सुचारू करने को लेकर प्रदेश सरकार निरंतर कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी उद्योगों को पूरे स्टाफ के साथ काम करने की मंजूरी दे है और करीब 33 लाख लोग काम की ओर वापस लोट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तहत प्रदेशभर में क्षेत्रिय उद्योगों को बाढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं इसके लिए नए बनाए एमएसएमई निदेशालय द्वारा सभी जिलों से रोपोर्ट मांगी गई है। इस बारे उन्होंने बताया कि अंबाला से साइंस, रेवाड़ी व यमुनानगर से पीतल उद्योग को बढ़ावा देने की मांग आई है और इस तरह अन्य जिलों से भी क्षेत्रिय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार वहां से रिपोर्ट मांगेगी।

हरियाणा के विधायकों की मांग बुलाया जाए मानसून सत्र

बैठक में स्पीकर ने कहा कोरोना हुआ शांत तो बुलाएंगे सत्र

दूसरे दिन भी विधायकों ने अफसरशाही पर निकाली भड़ास

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि निकट भविष्य में विधासभा का मानसून सत्र बुलाया जाए और इसे लंबा चलाया जाए ताकि वह अपने-अपने क्षेत्रों की समस्या सदन में रख सकें।

हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से विधायकों के लिए आयोजित की जा रही बैठक के दूसरे दिन विधायकों ने यह मांग रखी। गुरुवार को पहले दिन आयोजित की गई बैठक में 40 में से 32 विधायक वीसी के माध्यम से जुड़े और शुक्रवार को दूसरे दिन 17 में से 15 विधायक इस बैठक का हिस्सा बने।

ज्यादातर विधायकों ने विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने तथा अफसरशाही द्वारा अनदेखी किए जाने का मुद्दा आज फिर से उठाया। विधायकों का तर्क था कि वह कोरोना काल में जनता से जुड़े मामलों पर अफसरों को फोन करते हैं लेकिन कई अधिकारी तो उनके फोन तक नहीं उठाते हैं। बैठक के दौरान कोरोना के संबंध में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े सुझाव भी दिए। विधायकों की बात सुनने के बाद स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा सुनवाई न किए जाने के मुद्दे पर लिखित में शिकायत मांगी गई है।

इस मामले को प्रीविलेज कमेटी के सामने रखा जाएगा। कमेटी कोई भी एक्शन लेने के लिए अधिकृत होगी। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। कोरोना का प्रकोप अगर कम हुआ तो इस संबंध में उचित फैसला लिया जाएगा। सत्र के आयोजन को लेकर कोई विकल्प भी तलाशा जा सकता है।

गौतम ने अभी तक नहीं दिए सबूत

हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जजपा विधायक रामकुमार गौतम के मुद्दे पर कहा कि अभी तक उन्हें सबूत मुहैया नहीं करवाया गया है। रामकुमार गौतम ने विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान अपना वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था। गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में दो बार पत्र लिखकर सबूत मांगे जा चुके हैं। सबूत मिलने पर ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

चार कैटर्स ने हड़पे 12 लाख तो कैटर्स ने लगाई फांसी

लक्ष्मण विहार फेज-2 में परिवार के साथ रहता था कैटर्स

मूलरूप से था राजस्थान का रहने वाला

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

चार कैटर्स द्वारा 12 लाख रुपए का चूना लगाए जाने पर एक कैटर्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने चारों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। कैटर्स की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को सेक्टर-9ए थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक मूलरूप से राजस्थान जयपुर निवासी सचिन शर्मा (38) अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बीते 10 वर्षों से लक्ष्मण विहार फेज-2 में रह रहा था। वह कैटरिंग का काम करता था। गुरुवार की रात को सचिन शर्मा ने उसने कमरे में दुपट्टे को फंदा बनाया और फांसी लगा ली। जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने पुलिस को फोन करके जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला। जिसमें उसने लिखा की सिक्का कैटर्स के रवि, स्वाद कैटर्स के प्रदीप, पप्पू कैटर्स व सोहना कैटर्स से उसे करीब 12 लाख रुपये लेने थे।

लॉकडाउन की वजह से काम न होने के कारण वह अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन वे दे नहीं रहे थे। उस पर खुद पर उधारी हो गई थी। इस बात से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। सेक्टर-9ए थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सचिन शर्मा की पत्नी सरोज के बयान पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

मामला अफसरों द्वारा विधायकों की अनदेखी का

विधायकों के समर्थन में गृहमंत्री, कहा नौकरी करनी है तो विधायकों की सुननी होगी

हुड्डा सरकार में खुद अनिल विज ने कई बार उठाया था विधानसभा में यह मुद्दा

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की अनदेखी किए जाने का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को अधिकारी पीड़ित विधायकों का समर्थन किया है। विज ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की सुननी पड़ेगी।

हरियाणा में अफसरशाही द्वारा विधायकों की अनदेखी करने का विवाद नया नहीं है। यह विवाद हुड्डा सरकार में ही शुरू हो गया था। इससे पहले चौटाला सरकार में इक्का-दुक्का विधायक को छोड़कर कभी किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। प्रोटोकॉल में विधायक मुख्य सचिव से उपर है। हरियाणा में पिछले करीब डेढ़ दशक से हालात यह हैं कि विधायकों द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों में एसडीओ स्तर के अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं। एसडीएम और डीएसपी तो विधायकों के फोन तक नहीं उठाते हैं। विधायकों को जिला स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात के लिए आम जनता की तरह इंतजार करना पड़ता है। हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्तमान गृहमंत्री अनिल विज विपक्ष में रहते हुए इस समस्या से सर्वाधिक पीड़ित रहे हैं।

विपक्ष में रहते हुए अनिल विज ने कई बार यह मुद्दा उठाया तो तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्रियों ने मुख्य सचिव के माध्यम से निर्देश भी जारी किए। इसके बावजूद अधिकारी कभी गंभीर नहीं हुए। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी यह मुद्दा उठता रहा है। अब पिछले दो दिन से विधानसभा स्पीकर द्वारा की जा रही वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक के दौरान विधायक यह मुद्दा उठा रहे हैं।

गृहमंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायकों का पक्ष पूरते हुए कहा कि अधिकारियों को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। विज ने आंखे तरेरते हुए कहा कि अधिकारियों पर सख्ती के और भी बहुत तरीके हैं। अगर विधायक मुख्यमंत्री को बताएंगे तो इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। विज ने कहा कि प्रोटोकॉल में विधायक मुख्य सचिव से ऊपर है ,यह अफसरों को बता दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी द्वारा इस मुद्दे पर विधानसभा में बिल लाए जाने के दावों को खारिज करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

क्वॉरंटीन सेंटर से अस्पताल गया मरीज लापता

पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्जकर एक महीने बाद शुरू की तलाश

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते उसकी कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जिले में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि जिसे जानकर सभी को आश्चर्य हो रहा है।

गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा के क्वॉरंटाइन सेंटर में भर्ती करवाया गया एक युवक गायब हो गया है। करीब एक महीने से यह युवक गायब है और अब जाकर इस युवक की तलाश शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, क्वॉरंटाइन सेंटर के प्रभारी की ओर से दनकौर कोतवाली में एफ आईआर दर्ज करवाई गई है। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है।

ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स)।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में दनकौर क्षेत्र के क्वॉरंटाइन सेंटर से ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीज को भेजा गया था। ग्रेटर नोएडा अस्पताल से यह संदिग्ध मरीज एक महीने से लापता है। अब क्वॉरंटाइन सेंटर के इंचार्ज की ओर से दनकौर कोतवाली में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने लापता संदिग्ध मरीज की तलाश भी शुरू कर दी है। झारखंड के देवघर जिले के निवासी रंजीत अपने एक साथी राजकुमार के साथ ग्रेटर नोएडा की एक ट्यूब लाइट कंपनी में काम करता था। 19 अप्रैल को 21 वर्षीय रंजीत को क्वॉरंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था।

हालत बिगड़ने पर उसे ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स में भर्ती कराया गया। देर रात फिर से वापिस क्वॉरंटाइन सेंटर में भेज दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 23 अप्रैल को रंजीत की दोबारा हालत खराब हुई थी। उसे क्वॉरंटाइन सेंटर से 2 चिकित्सकों की टीम के साथ ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में एम्बुलेंस से रेफर किया गया था। रंजीत के साथ दूसरी एम्बुलेंस में उसका साथी भी अस्पताल गया था।

रंजीत के साथ राजकुमार की 25 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। जिस कारण उसे क्वॉरंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया था। लेकिन रंजीत की रिपोर्ट राजकुमार की रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा में थी। आज तक न तो रंजीत की रिपोर्ट आई है और न ही उसका पता लग पाया है। इस मामले में दनकौर कोतवाली पुलिस ने एफ आईआर दर्ज कर ली है और जांच में जुट गई है।

अश्लील चैट नहीं करने पर छात्रा को कर रहा ब्लैकमेल, केस दर्ज

गाजियाबाद। शहर कविनगर इलाके में बीए की एक छात्रा को 14 साल के लड़के द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्यूशन के स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में छात्र जुड़ा हुआ है और वहीं से छात्रा का संपर्क लड़के से हुआ था। इसके बाद उसने सामान्य चैट शुरू कर दी। बाद में वह छात्रा पर अश्लील चैट का दबाव बनाने लगा। जिस पर छात्रा ने इनकार किया। ऐसे में छात्रा ने उससे बात करना बंद कर दिया।

आरोप है कि इसके बाद लड़के ने छात्रा को धमकी दी है कि अगर उसने उसके साथ अश्लील चैट नहीं की तो वो उसकी तस्वीर को एडिट कर वायरल कर देगा। लड़के द्वारा छात्रा से रुपये मांगे जाने की बात भी सामने आई है। कविनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी मनीष मिश्र ने बताया कि मामले में जल्द कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

रेल टिकट बुकिंग शुरू, दलाल भी एक्टिव

सात गिरफ्तार, आरपीएफ डीजी अरुण कुमार ने दी जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

रेलवे 1 जून से सौ जोड़ी ट्रेन चलाकर जगह-जगह फंसे लोगों की राह आसान करेगा। इसके लिए शुक्रवार से नई दिल्ली-कड़कड़डूमा आरक्षण केंद्र खुल गए हैं। इन केंद्रों पर सुबह से ही लोग टिकट बुक कराने के लिए लाइन में खड़े हो गए थे। जिसके चलते टिकट काउंटर के बाहर लंबी-

- **नई दिल्ली-कड़कड़डूमा आरक्षण केंद्र खुले**
- **सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन**

लंबी लाइन लग गई।

इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे पुलिस ने सात दलालों को गिरफ्तार किया है। डीजी आरपीएफ अरुण कुमार ने बताया कि टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। इस कड़ी में दलालों को धरा गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरक्षित टिकट दिखाता एक युवक। फोटो : रंजन डिमरी

इन लोगों के कब्जे से भारी संख्या में रेलवे टिकट बरामद हुआ है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि आरोपी पहले से भी पकड़े जा चुके हैं। इन सबका रिकॉर्ड खराब है। दरअसल लॉकडाउन में छूट मिलते ही रेलवे टिकट का काउंटर भी खुल गया है। इस बीच दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। दलालों पर रेलवे पुलिस की कड़ी नजर है। टिकट काउंटर पर लगे ये वो तमाम लोग हैं। जिन्हें ऑनलाइन टिकट बुक करने में दिक्कत हो रही थी।

शुक्रवार को डीएनडी पर जाम में फंसी गाड़ियां। फोटो : दीपक यादव

भीषण ट्रैफिक जाम-डीएनडी पर थमी वाहनों की रफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

- **एक किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा एक से डेढ़ घंटे का समय**

लॉक डाउन 4 में छूट मिलने के बाद से शहर में जाम लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह शुक्रवार को भी पूरे दिनभर जारी रहा। नोएडा-दिल्ली बॉर्डर समेत आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम लग गया। जिससे यहां पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। जाम के चलते लोग धूप में काफी परेशान हुए। रात के समय सूनी रहने वाली शहर की सड़कें सुबह से लेकर देर शाम तक जाम से कराह उठीं।

हालत यह हो गई कि कई जगह लोगों को एक किलोमीटर का सफर तय करने में एक से डेढ़ घंटे का समय लगा। नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर शाम के समय जाम की एक और बड़ी वजह है। दरअसल, शहर में रोजाना शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगता है। इस दौरान लोगों पर आवागमन की पाबंदी है। लिहाजा, तमाम लोग शाम 7 बजे से पहले ही घर लौटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर भीषण जाम लग जाता है। दूसरी ओर दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर रोजाना लंबा जाम लग रहा है। इसकी वजह से लोग चिलचिलाती धूप में रोजाना परेशान हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लॉक डाउन-4 में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में लोगों को काफी रियायत दी है। इसके बाद से लगातार दिल्ली की सीमा से यूपी और हरियाणा जाने वाली सड़कों पर रोजाना जाम लग रहा है।

तूफान से तबाह प. बंगाल ओडिशा को मदद की पेशकश

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अम्फान तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रति एकजुटता दिखाते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मदद की पेशकश की।

केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि आदरणीय ममता दीदी दिल्ली के लोगों की ओर से वह चक्रवात अम्फान की वजह से हुई तबाही से उबरने में पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति समर्थन एवं एकजुटता प्रकट करते है। कृपया बताएं कि इस संकट की घड़ी में क्या मदद कर सकते हैं। एक अन्य ट्वीट में केजरीवाल ने ओडिशा के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट की और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी मदद की पेशकश की।

पॉजिटिव पुलिस वालों को एक लाख नहीं, मिलेंगे 10 हजार रु

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पुलिस कर्मियों को देने वाली राशि एक लाख रुपये से घटाकर दस हजार रुपये कर दी है। इसका मुख्य कारण पुलिस बल में संक्रमण के मामले बढ़ना हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारियों ने बताया कि अब तक 250 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में 25-30 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी से कर्मियों को एक-एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया था। हाल ही में एक बैठक बुलाई गई थी और यह निर्णय लिया गया कि कर्मियों को दी जाने वाली राशि घटाई जाए। कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे मामलों में समान रूप से राशि वितरित होनी चाहिए। इसलिए राशि को एक लाख रुपये से घटाकर दस हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर पुलिसकर्मियों का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ है और विभाग दवाई और उनके इलाज में मदद कर रहा है। इसी बीच कोविड-19 से जान गंवाने वाले एक पुलिस अधिकारी को सात लाख की जगह 10 लाख रुपये दिए गए हैं। उत्तर पश्चिमी जिले के भारत नगर पुलिस थाने में तैनात एक

पीएम केयर फंड में 21 लाख का दिया योगदान

नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौतियों से निपटने में लगी केंद्र सरकार की मदद को अखिल भारतीय आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था मानव उत्थान सेवा समिति ने मदद का हाथ बढ़ाया है।

समिति ने इसके लिए जहां एक ओर 'पीएम केयर फंड' में 21 लाख रुपये की राशि का योगदान किया है वहीं संकट की इस घड़ी में देश के विभिन्न हिस्सों में निराश्रित एवं गरीबों को राशन किट भी उपलब्ध करवा रही है। ज्ञात हो कि अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली मानव उत्थान सेवा समिति एक सामाजिक व धर्मार्थ संस्था है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज इस संस्था के प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक हैं।

हाई कोर्ट-अन्य अदालतों में 31 तक कामकाज बंद

नई दिल्ली। कोविड-19 के मद्देनजन उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के कामकाज पर पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी और केवल जरूरी मामलों पर ही सुनवाई होगी। इससे पहले ये पाबंदियां 23 मई तक लागू थीं।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल के नेतृत्व में उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और आम पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया है कि पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी और वीडियो कांफ्रेंस के जरिए केवल तत्काल मामलों पर ही सुनवाई होगी। प्रशासनिक आदेश में कहा गया कि उच्च न्यायालय का कामकाज समान शर्तों पर 31 मई तक निलंबित रहेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

निविदा सूचना (निविदा आईडी: 2020_AAI_48597_1)

अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से सहायक महाप्रबंधक (इंजी.-विद्युत)-II आई.एम.यू. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 के द्वारा विशेषज्ञ एजेंसियों से "राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार के दौरान सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम के सुरक्षित प्रचालन हेतु आंतरिक वायु गुणवत्ता के उन्नयन" के कार्य हेतु मद दर निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत ₹2,20,73,425/- (दो करोड़ बीस लाख तिहत्तर हजार चार सौ पच्चीस केवल) (जीएसटी को छोड़कर) है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि: 01 (एक) महीना। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 01.06.2020 को 1800 बजे तक। विस्तृत जानकारी के लिए सी.पी.पी. ई-प्रोक्योरमेंट पार्टल: https://etenders.gov.in/eprocure/app अथवा www.aai.aero पर लॉग ऑन करें। आगे कोई भी स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सीपीपी ई-प्रोक्योरमेंट पार्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (N-07/2020-21)

ट्यूबवेल पर सो रहे थे बुजुर्ग धारदार हथियार से की हत्या

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

थाना दनकौर क्षेत्र के ईशुपुर गांव में रहने वाले 75 वर्षीय व्यक्ति की बृहस्पतिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। घटना के समय बुजुर्ग अपने खेत के ट्यूबवेल पर सो रहे थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना दनकौर क्षेत्र के ग्राम ईशुपुर निवासी राजेंद्र शर्मा (75 वर्ष) बीती रात अपने खेत के ट्यूबवेल पर सो रहे थे तभी देर रात अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना शुक्रवार सुबह पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चला है।

गाजियाबाद में आज से खुलेंगे बाजार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

रविवार को रहेंगे बंद

आज से फिर गाजियाबाद के बाजारों में चहल-पहल और खरीददारी शुरू हो जाएगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शुक्रवार का इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बाजार खोले जाने का ब्लू प्रिंट जारी कर दिया। शहर के बाजार ऑड-ईवन की तर्ज पर खोले जाएंगे। दुकानदारों को प्रशासन द्वारा बनाये गए सख्त नियमों के पालन के तहत ही बाजार खोलने की अनुमति दी गई है।

बाजारों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि के अलावा दुकान खोलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कंटेनमेंट जोन व हॉट स्पॉट क्षेत्र में लागू नहीं होगा। इसके अलावा जनपद में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों/बीमार व्यक्तियों, सुरक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।

डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण जिले में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दो माह से बंद थीं। इसके चलते दुकानों के अंदर रखे हुए सामान के खराब होने व भारी मात्रा में कचरा निकलने की संभावना बनी हुई है। इसके चलते यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि नगर निगम, पालिकाएं व पंचायत समेत सभी व्यापारिक संगठन यह सुनिश्चित करें कि इस कूड़े-कचरे का निस्तारण व सैनिटाइजेशन पूरी तरह से करा लिया जाए। शारीरिक दूरी से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं।

उन्होंने बताया कि सभी बाजार रविवार को साप्ताहिक रूप से बंद रहेंगी। रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही अपने तय समय के अनुसार खुलेंगी।

कर्ज से परेशान इंजीनियर ने पंखे से लटक दी जान

नोएडा। यहां सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के सेक्टर 75 में रहने वाले एक इंजीनियर ने शुक्रवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। सहायक पुलिस आयुक्त विमल कुमार सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर-49 पुलिस को सूचना मिली थी कि मुकेश झा (35) नामक एक व्यक्ति ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।

एसीपी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी के अनुसार वह कर्ज में डूबे हुए थे और मकान के लिए उन्होंने लाखों रुपए का कर्जा लिया था।

एम्स के डॉक्टर कर रहे शोध

शव में कब तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस!

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

एम्स के डॉक्टर यह जानने के लिए कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने पर विचार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण कितने समय तक किसी शव में रह सकता है। साथ ही क्या इससे संक्रमण फैलने की आशंका हो सकती है।

दिल्ली के अस्पताल के फोरेंसिक प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा कि इस शोध से यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि विषाणु कैसे मानव अंगों पर असर डालता है। इसके लिए मृतक के कानूनी वारिस से सहमति ली जाएगी। इस शोध में रोग विज्ञान और अणुजीव विज्ञान

जैसे कई और विभाग भी शामिल होंगे।

डॉ. गुप्ता ने कहा यह अपने आप में पहला शोध होने जा रहा है और इसलिए सावधानीपूर्वक इसकी योजना बनानी होगी। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि वायरस शरीर पर क्या असर डालता है। साथ ही इससे यह भी पता चलने में मदद मिलेगी कि कोरोना वायरस किसी मृत शरीर में कितने समय तक रह सकता है। अभी तक मौजूद वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार किसी शव में वायरस धीरे-धीरे खत्म होता है लेकिन अभी शव को संक्रमण मुक्त घोषित करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था आईसीएमआर ने मंगलवार को कहा था कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का बिना चीर-फाड़ किए पोस्टमार्टम करने की तकनीक अपनाने की सलाह दी जाती है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा था कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों में फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए चीर-फाड़ करने वाली तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मोर्चरी के कर्मचारियों के अत्यधिक एहतियात बरतने के बावजूद शव में मौजूद द्रव तथा किसी तरह के स्राव के संपर्क में आने से इस जानलेवा रोग की चपेट में आने का खतरा हो सकता है

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

पार्किंग उल्लंघन
के विरूद्ध
अब कड़ी कार्यवाही

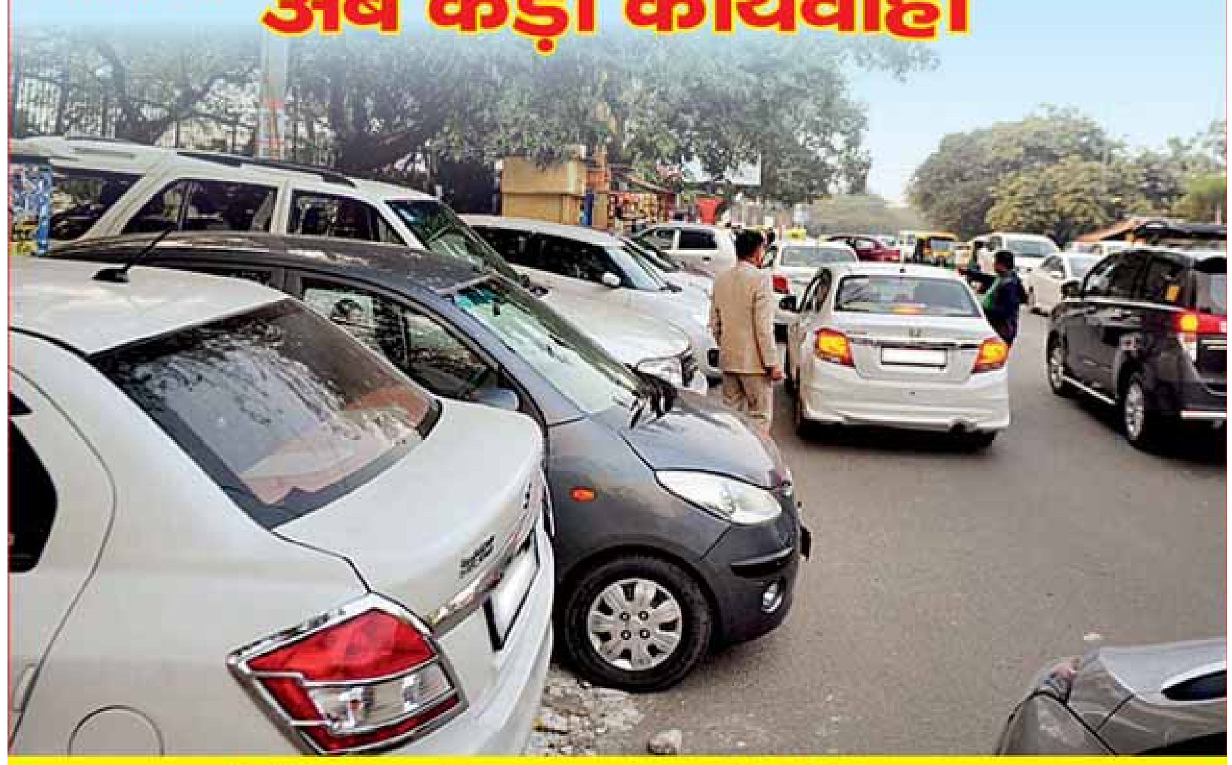

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019
यातायात पुलिस द्वारा संयोजनीय

सड़कें पार्किंग के लिए नहीं बल्कि यातायात आवागमन के लिए हैं
- सड़कों पर पार्किंग से अव्यवस्था होती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटती हैं
- कभी भी फुटपाथ पर पार्किंग न करें
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122/177 के अंतर्गत पार्किंग नियमों का उल्लंघन दंडनीय है

पार्किंग उल्लंघन के लिए जुर्माना
500/- रूपये तक पहली बार उल्लंघन करने पर
1500/- रूपये तक दूसरी बार तथा उसके उपरांत प्रत्येक उल्लंघन के लिए

यातायात नियमों का पालन करें | सुरक्षित रहें | जुर्माने से बचें

ट्रैफिक प्रहरी बनें
ऐप डाउनलोड करें
24 घंटे यातायात हेल्पलाईन 011-25844444/1095
आप हमसे जुड़ें: https://twitter.com/dtptraffic https://www.facebook.com/dtptraffic

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें: cp.snshrivastava@delhipolice.gov.in | लिखें: पुलिस आयुक्त दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर
तुरंत पुलिस सहायता के लिए 112 नम्बर पर कॉल करें | पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें-1090
DP/9237/2020

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-48799001

तब किसी ने नहीं संभाला, आज स्वागत की निभाई रस्म

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

एनएचएम के तहत लगी है नर्स पूनम

एनएचएम की शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई

नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत यहां नागरिक अस्पताल में कार्यरत नर्स पूनम को उस दिन तो किसी ने नहीं संभाला, जिस दिन वह कोरोना संक्रमित होने के बाद अपने घर से नागरिक अस्पताल पैदल ही 40 मिनट का सफर तय करके पहुंची थी। आज जब वह ठीक होकर लौटी तो उसका यहां स्वागत करने की रस्म की गई।

यहां नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में काम करते हुए एक स्टाफ नर्स पूनम सहराय और एक एनएचएम के तहत कार्यरत नर्स पूनम कोरोना संक्रमित हो गई थी। अब ठीक होने के बाद शुक्रवार को जब पूनम अपनी ड्यूटी ज्वायन करने पहुंची तो उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर एनएचएम के जिलाध्यक्ष हरिराज, एनसीडी प्रभारी डा. सुनीता राठी, डा. प्रदीप कुमार समेत काफी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा। हरिराज के मुताबिक स्टाफ पूनम ने सिविल सर्जन, पीएमओ व अन्य स्टाफ की बीमारी के समय उत्साह बढ़ाने का धन्यवाद किया।

कोरोना पॉजिटिव नर्स का मामला

सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में एनएचएम के तहत लगी कोरोना वॉरियर नर्स का स्वागत करते स्टाफ और यूनियन।

अब सवाल यह उठता है कि जिस दिन यही स्टाफ पूनम कोरोना संक्रमित हुई थी, उस दिन ये सब कहां थे।

बुखार था, फिर भी बनाया ड्यूटी का दबाव: हरिराज : एनएचएम के अध्यक्ष हरिराज से जब पूनम के स्वागत और पहले दिन के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्टाफ पूनम की समस्या का उन्हें देरी से पता चला। वे पता चलते ही सीएमओ डा. जेएस पूनिया से मिले थे। उन्होंने पूरे मामले का पता नहीं होने का बात कही थी। भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होने देने का भी आश्वासन दिया था। हरिराज ने यह भी बताया कि पूनम की तबियत खराब होने पर अस्पताल की सीनियर स्टाफ की ओर से ड्यूटी पर आने का दबाव बनाया गया था। जबकि पूनम की रिपोर्ट तब तक नहीं आई थी। हरिराज के मुताबिक एनएचएम यूनियन ने सीनियर स्टाफ से मुलाकात की थी। हालांकि इस बात का किसी के जवाब नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्बुलेंस लेने क्यों नहीं पहुंची। पहले दिन तो पीड़ित नर्स ने भी शिकायत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने चुप्पी साध ली।

था तुझे गुरूर खुद के लम्बे होने का ऐ सड़क गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया...

पैदल ही अपने प्रदेशों को रवाना हुए श्रमिकों, परिवारजनों के हौंसले को सेल्यूट

एक साल की उम्र से लेकर उम्रदराज व्यक्तियों ने भी नहीं मानी हार

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के राजीव चौक से अपने राज्यों को पैदल रवाना होते लोग।

था तुझको गुरूर खुद के लम्बे होने का ऐ सड़क, गरीब के हौंसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया...। कोई भी इन लाइन को पढ़े तो उसके सामने वह तस्वीर आ जाती है, जो दिन-रात हम मीडिया की सुर्खियों में देखते हैं। टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर आज यही सब छाया हुआ है। पांव में छाले, फिर भी चले जाते हैं लोग। चंद्रयान जैसे उपग्रहों पर इतराने वाले भारत की यह तस्वीर शर्मिंदगी भरी है।

कोरोना के खौफ के बीच अपनों के बीच जाकर जीने-मरने की बातें कहते हुए जिस तरह से श्रमिकों और उनके परिवारों ने पैदल ही रवानगी की, वह हमारे सिस्टम पर अनेक सवाल खड़े करता है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से होकर कई राज्यों का रास्ता निकलता है। यहां बात दो, चार, दस, बीस किलोमीटर, मील की नहीं, बल्कि सैंकड़ों, हजारों किलोमीटर के सफर की है।

पैदल, साइकिल पर मापने वाले इन श्रमिकों के अटूट हौंसले को देख हर कोई उन पर दया का भाव भी रखता है तो साथ में सरकारों को भी कोसता है। यहां हम देखें तो 24 घंटे ही लोगों का इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। कोई राजस्थान, एमपी जा रहा है तो कोई यूपी, बिहार। हर किसी की अपनी मंजिल है अपना ठिकाना है। भूख और बेरोजगारी से तंग होकर अपना चंद सामान समेट अपने प्रदेशों को रवाना हुए लोग सिर्फ यही कहते हैं कि यहां मरने से अच्छा है अपनों के बीच जाकर मरें। उनकी दो लाइनों की यह बात उनकी मजबूरी, उनके भय को विस्तार से बता देती है।

बसों, ट्रेनों में नंबर नहीं आया तो पैदल ही हुए रवाना

कहने को तो बसें, ट्रेनें यहां से संचालित की जा रही हैं, लेकिन उनमें भी सभी का नंबर नहीं आ रहा। 15 दिन पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी नंबर नहीं आया तो यहां गढ़ी-हरसरू से समूह में पैदल ही रवाना हुए यूपी के रमेश, जयराम, गुड्डू, फूलवती व सुमन का परिवार। उनकी शिकायत थी कि कहीं पर भी फोन मिला लें, कोई जवाब नहीं मिलता। ज्यादातर तो फोन ही नहीं मिलता। ऐसे में वे कब तक इंतजार करते। उधर से गांव से घरवालों का 24 घंटे दबाव रहता कि तुरंत रवाना हो जाएं। इसलिए उनकी मजबूरी बन गई। छोटे बच्चों, सामान को साथ लेकर वे चल पड़े। जैसे-जैसे अपने घर पहुंच ही जाएंगे, यह सोचकर उन्होंने केएमपी एक्सप्रेस-वे से पलवल की तरफ कदम बढ़ाए। महिलाओं के सिर पर सामान, गोदी में बच्चा और फिर पल्लु पकड़कर साथ में चलता थोड़ा बड़ा बच्चा बार-बार पूछता कि कितनी दूर और है। मां मासूमियत के साथ कहती कि थोड़ी दूर और है।

किसी के तन पर पूरे कपड़े नहीं, किसी के पांव में चप्पल

यहां से रवाना होने वालों में बहुत से बच्चे ऐसे थे, जिनका जन्म ही यहां पर हुआ है। वे पहली बार अपनों की जन्मभूमि में जा रहे थे। बेशक वे 21वीं सदी में पैदा हुए, लेकिन शायद ही वे अपने जीवन में आज से बुरा दौर देखें। बहुतों के पांवों में जूते, चप्पलें नहीं तो बहुतों के तन पर पूरे कपड़े तक नहीं। दिल्ली और इसके आसपास रहकर जीवन की गाड़ी को गति देने के उद्देश्य से यहां आए इन श्रमिकों में बहुत से तो अब तौबा करके जा रहे हैं कि वापस नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत बुरा दौर देखा है।

...तो क्या कोरोना को हल्के में ले रहा है स्वास्थ्य विभाग

कोरोना संक्रमित को संदिग्ध लोगों के साथ किया क्वारंटाइन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

बेशक यहां पिछले कई दिनों से रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, लेकिन यहां का स्वास्थ्य विभाग कोरोना को अब हल्के में लेने लगा है। यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि विभाग की कार्यशैली से जाहिर होती है। एक तो सेंपल लेकर रिपोर्ट में देरी तो वहीं कोरोना के पॉजिटिव केस आने पर उन्हें अन्य मरीजों से अलग रखने में लापरवाही। भविष्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं हैं।

पहला मामला तो यह कि यहां सेक्टर-9 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सी समस्याओं के लिए संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इन सबके बीच एक कोरोना पॉजिटिव को भी यहां पर भर्ती कर दिया गया। सरकारी लैब से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसका खुलासा तब हुआ, जब पॉजिटिव मरीज ने सोशल मीडिया पर क्वारंटाइन सेंटर में खामियों को उजागर किया। मूलरूप से बिहार के वैशाली के रहने वाला यह कोरोना संक्रमित गुरुग्राम के सेक्टर-18 स्थित कंपनी में इंजीनियर है। इसी क्षेत्र में वह किराए पर रहता है। कई दिनों से तेज बुखार की शिकायत के बाद उसने 16 मई को सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल से जांच कराई। उसके सेंपल लिए गए और 20 मई को रिपोर्ट आने की बात कही। 20 मई को रिपोर्ट लेने पहुंचा तो उसे रिपोर्ट पुराने नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय जाकर लेने को कहा। खैर, थोड़ी-बहुत कहासुनी के बाद उसे रिपोर्ट देखकर बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव आया है। सी समय उसे एम्बुलेंस में ईएसआईसी या अन्य अस्पताल भेजने की बजाय, कालेज में बने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया।

जेल की तरह बंद करके चले जाते हैं कर्मचारी

सेक्टर-9 कालेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था से नाखुश होकर कोरोना पॉजिटिव इंजीनियर ने सेंटर की खामियों को उजागर करते हुए डीसी से गुहार लगाई। इंजीनियर ने यह तक कहा है कि यहां पर कैदियों की तरह सभी को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता है। कोई उनकी सुध लेने नहीं आता। बुधवार को उसे तेज बुखार था, लेकिन वह चिल्लाता रहा। हेल्पलाइन पर फोन करने पर कहा कि डॉक्टर अगले दिन सुबह आएंगे। काफी देर तक परेशानी झेलने के बाद एक पुलिसकर्मी ने उसे बुखार की गोली दी। इस बारे में सीएमओ डा. जेएस पूनिया को कई बार कॉल की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

ईद की तैयारी में ग्राहकों की बाजारों में भीड़

सोहना। ईद की तैयारी को लेकर सोहना के बाजारों में ग्राहकों का भीड़ उमड़ पड़ी। कपड़ा व जूता दुकानदारों ने लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानें खोलीं। नगर परिषद की टीम ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के चालान काटे। शुक्रवार को सोहना के बाजारों में किराना, हार्डवेयर, दूध, सब्जी, फल, आदि की दुकानें खुली।

रविवार को ईद की तैयारी को लेकर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। बाजारों में कई स्थानों पर जाम का माहौल रहा। ग्राहक अपनी गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा करके सामान की खरीदारी कर रहा था। शहर के पुराना लेबर चौक, खेल चौक, पटवार घर के निकट, बिजली निगम के एसडीओ कार्यालय के सामने दुकानों पर भीड़ व

जाम रहा। दुकानदार अपना सामान बेचने के इरादे से सामाजिक दूरी को भूल रहे थे। 70 फीसदी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे सामाजिक दूरी की नियम के अनुसार न रस्सी बांधी और नहीं कोई सामान रखा हुआ था।

कपड़ा व जूता की दुकानें खुली : शुक्रवार को शहर में कपड़ा व जूते की दुकानों का खुलने का नंबर नहीं था, लेकिन इन दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खोला। नगर परिषद की टीमों ने लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में सिर्फ तीन दुकानदारों के चालान काटकर खानापूर्ति की।

बिना रुकावट के परिचालन उद्योग हों शुरू: एचपी यादव

गुरुग्राम। एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुरुग्राम के निरंतर मांग पर राज्य सरकारों ने गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन के एसओपी के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन गुरुग्राम बॉर्डर अभी भी बंद किया हुआ है। जिस कारण उद्योग तथा वाणिज्य संस्थान सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

इस बाबत एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुरुग्राम के अध्यक्ष एचपी यादव ने कहा किज्यादातर कर्मचारी तथा श्रमिक रोजाना दिल्ली से गुरुग्राम आते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को एनसीआर रीजन में परेशान किया जाता है। बॉर्डर से ही वापस कर दिया जाता है तथा अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।

कोरोना: आम आदमी के सेंपल की रिपोर्ट पर गंभीर नहीं स्वास्थ्य विभाग

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

4 दिन से अधिक समय में मिलती है रिपोर्ट

खास लोगों की रिपोर्ट में नहीं दिखती कोई लापरवाही

गुरुग्राम जिला का स्वास्थ्य विभाग के काम की गति भी आम और खास आदमी को देखकर तय होती है। क्योंकि आम आदमी के कोरोना के सेंपल लेने के बाद रिपोर्ट का कुछ अता-पता नहीं रहता और वहीं खास आदमी की रिपोर्ट बिना देरी के आ जाती है।

रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों में विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। यहां नागरिक अस्पताल में संदिग्ध आम आदमी के सेंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा जाता है। जांच रिपोर्ट कब आएगी, इसके लिए कोई तय समय नहीं बताया जाता। अगर बताया भी जाता है तो फिर उस दिन रिपोर्ट को लेकर इधर से उधर दौड़ाया जाता है। इस बीच अगर वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो तो फिर बहुतों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर पॉजिटिव आएं या नर्स। यह विभाग के अधिकारियों के लिए आम बात हो चली है। अब बात करें खास आदमी की। गत दिवस गुरुग्राम के एडीसी के ड्राइवर व गनमैन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस पर आनन-फानन में एडीसी समेत अन्य कर्मचारियों के सेंपल भी लिए गए और जांच को भेजे गए।

जांच की रिपोर्ट बिना देरी के आ गई। एडीसी भी नेगेटिव मिले व अन्य कर्मचारी भी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आम आदमी की रिपोर्ट में इतनी देरी क्यों होती है। क्या इसमें भी कोई आम और खास का कोटा तय किया गया है। इस बारे में सीएमओ को कई बार कॉल की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

संक्षिप्त समाचार

80 बसों में 2400 नागरिक यूपी के लिए रवाना

गुरुग्राम। कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन में बाहर के रहने वाले नागरिकों को उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। शुक्रवार को जिला गुरूग्राम में पांच अलग-अलग स्थानों से 80 बसों में 2400 नागरिकों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली और इटावा के लिए भेजा गया। गुरुग्राम जिला से एसडीएम चिनार चहल की देखरेख में सभी प्रवासी नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उसके बाद रोडवेज बसों से उन्हें गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। एसडीएम के मुताबिक गुरुग्राम जिला से 80 बसों मे 2400 प्रवासी नागरिकों को 80 बसों में भेजा गया है। गुरुग्राम जिला में ये बसे पांच अलग-अलग स्थानों नामत: ताऊ देवीलाल स्टेडियम, राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-14, मानेसर सेक्टर-8, गउशाला मानेसर व सिद्धरावली से रवाना हुई। जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों को भेजने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी चिनार चहल द्वारा निर्धात शेड्यूल अनुसार ही नागरिकों को मास्क, पानी की बोतल व बिस्किट पैकेट देते हुए नि:शुल्क यात्रा के साथ घर भेजा जा रहा है। एसडीएम चिनार चहल ने प्रवासी नागरिकों को धैर्य व संयम का परिचय देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन प्रवासी नागरिकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है, उन्हें भेजने की व्यवस्था की गई है।

नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे 223 पशुओं को पकड़ा

गुरुग्राम। नगर निगम के क्षेत्र में सड़कों, गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुले घूमने वाले पशुओं को नगर निगम की टीम द्वारा पकड़ा जा रहा है। लॉकडाऊन के दौरान टीम द्वारा ऐसे 223 पशुओं को पकड़ा गया है। नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के निर्देश पर सभी पशु पालकों को हिदायत दी गई है कि कोई भी पशु पालक अपने पशुओं को सार्वजनिक स्थानों, मंडियों, सड़कों आदि पर खुला ना छोड़े। ऐसा पाए जाने पर पशु को पकड़कर तुरंत ही नगर निगम गौशालाओं में भेज दिया जाएगा तथा पशु मालिक के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दो हजार रुपये का जुर्माना या 3 माह की सजा का प्रावधान है। अगर पकड़े गए पशु को पशु मालिक द्वारा वापस मांगा जाता है, तो उससे 10 हजार रुपये जुर्माना और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पशु के चारे और अन्य खर्चों के रूप में वसूल किया जाएगा।

लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों पर पढ़ें ईद की नमाज

नूंह। ईद के त्योहार पर सभी मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज घर पर ही अदा करें और कानून का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बाजार में बार-बार न जाए। जिससे कानून का पालन करते हुए महामारी से जंग जीती जा सके। यह बात पुन्हाना के नवनियुक्त डीएसपी विवेक चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि मेवात में इस महामारी से लगभग जंग जीती जा चुकी है, लेकिन इसे पूरी तरह जीतने में अभी जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जिससे कानून का पालन करते हुए लोग प्रशासन का साथ दें ताकि इस महामारी से जंग जितने प्रशासन और सरकार कामयाब हो। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन चार में सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक सम विषम के तहत बाजार में दुकान खुल रही हैं। उन्होंने दुकानदारों को बताते हुए कहा कि सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दुकानदार स्वयं और ग्राहकों को भी मास्क लगाकर ही सामान दें। डीएसपी विवेक चौधरी ने बताया कि बाजार में ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आएं इतना ही नहीं जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए बार-बार वाहनों से बाजार आ रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विवेक चौधरी ने बताया कि बूढ़े व्यक्ति, बच्चे और गर्भवती महिला बाजार में न आएं, इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि सायं सात बजे से और सुबह सात बजे तक लोग घर से बाहर न निकलें, ताकि सरकार द्वारा दिए गए निदेर्शों का पूरा पालन हो सके। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग आने वाले 2 दिन में ईद के त्योहार पर ईद की नमाज घर पर ही पढ़ कर अपनी इबादत करें और देश में और दुनिया में फैल रही महामारी से जंग जीतने की दुआ मांगें।

क्रेसर जोन में प्रतिबंध के बाद दो मशीन चलती पकड़ी, केस दर्ज

सोहना। खनन अधिकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग की टीम ने रायसीना क्रेसर जोन में औचक निरीक्षण कर प्रतिबंध के बावजूद दो क्रेसर चालू हालात में पाई गई। टीम ने दोनों क्रेसर मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुरुवार को खनन एवं भूविज्ञान विभाग के महानिर्देशक के आदेश पर गठित दक्षिण जोन की टीम ने भोंडसी थाना क्षेत्र में स्थित रायसीना क्रेसर जोन का औचक निरीक्षण किया। महानिर्देशक द्वारा गठित टीम में पुलिस निरीक्षक आनन्द सांगवान, खनन निरीक्षक अनिल कुमार व गुरूग्राम/नूंह खनन अधिकारी एवं भूविज्ञान अधिकारी वासुदेव यादव ने रायसीना क्रेसर जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां गणेश स्टोन क्रेसर व राम ग्रिट स्टोन क्रेसर चालू हालत में पाए गए। गणेश स्टोन क्रेसर पर एक डंपर माल सहित पकड़ा। मुंशी उदयसिंह ने पूछताछ के दौरान बताया मशीन को मालिक के आदेश पर चलाया जा रहा है और भवन निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री को बेचा जा रहा है। करीब दो घंटे तक चला निरीक्षण के बाद वासुदेव यादव ने भोंडसी थाना में दोनों क्रेसर मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

थाना औद्योगिक क्षेत्र के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान

कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों को दिया गया कोविड योद्धा रत्न सम्मान

पायनियर समाचार सेवा। भिवानी

यहां बैंक कालोनी स्थित एमडी पब्लिक स्कूल की तरफ से हुन्नामल प्याऊ स्थित थाना औद्योगिक क्षेत्र के कोरोना वॉरियर पुलिस अधिकारियों, कर्मियों को कोविड योद्धा रत्न सम्मान दिया गया। सम्मान स्वरूप उन्हें सर्टिफिकेट व स्मृति चिन्ह दिया गया।

थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने इस सम्मान पर स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर एमडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मास्टर रमेश कुमार ने कहा कि चाहे पुलिस कर्मी हो या स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, मीडिया कर्मी और अन्य विभागों के जिन कर्मचारियों की कोरोना काल में

भिवानी के रोहतक रोड स्थित हुन्नामल प्याऊ के पास थाना औद्योगिक क्षेत्र के कोरोना वॉरियर एसएचओ विक्रम सिंह का सम्मान करते एमडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मास्टर रमेश कुमार, पीएनबी से सेवानिवृत्त अधिकारी हरिसिंह चौहान।

जनसेवा की भूमिका रही है, वे सभी हमारे लिए कोरोना वॉरियर हैं। इन सभी ने इस दौर में कोरोना वॉरियर बनकर जनता की सेवा है। इनकी वजह से ही शहर समेत पूरे देश में लॉकडाउन कामयाब हुआ है।

हर किसी ने घर से बाहर निकलकर अपना सहयोग दिया है और इस बीमारी को फैलने से रोकने में काफी मदद मिली है। विश्व व्यापी कोरोना बीमारी के दौरान फ्रंट लाइन में रहकर इन सभी ने काम किया है। यह अपने आप में बहुत रिस्की था और है। इनके कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए इन्हें सम्मानित करना सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक लोगों का कर्तव्य है। इसलिए स्कूल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा।

हुन्नामल प्याऊ स्थित पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के स्टाफ को सम्मानित किया गया। थाना के हर अधिकारी, पुलिसकर्मी को सम्मान दिया गया। इस मौके पर उनके साथ पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत अधिकारी हरिसिंह चौहान, वुशू कोच सोमवीर शर्मा, राकेश कौशिक पालुवास, सुमन राजपूत, भावना रोहिल्ला व अन्य स्टाफ सदस्यों ने बारी-बारी से सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मियों का सम्मान किया। इस मौके पर पुलिस थाना से मनीराम, नसीब सिंह, प्रवीण, राकेश, प्रदीप, मंगतराम, अशोक कुमार, रेखा रानी, नीलम, सलोनी, सुमन, सुशीला, अनुराग, राकेश, शिवकुमार, मोहन, अनिल व राणा प्रताप का प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया।

अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होंगे : विक्रम सिंह

यहां थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा कि एमडी पब्लिक स्कूल की तरफ से इस सम्मान से स्टाफ में और भी पॉजिविटी आई है। अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति सभी और अधिक सचेत रहेंगे। पुलिसकर्मी कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आज सभी के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है कि हमारे शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ नहीं पाई। शाब्दिक रूप से वे हर किसी का इसके लिए धन्यवाद और सम्मान करते हैं।

इस्कॉन दिल्ली ने लॉन्च की हेल्पलाइन संकट की घड़ी में मिलेगा परामर्श

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

इस्कॉन दिल्ली और दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के कारण तनावग्रस्त लोगों के लिए हेल्पलाइन लॉन्च की है। हेल्पलाइन नंबर 9971766666 का उद्देश्य लोगों को उनके तनाव से लड़ने में मदद करना और काउंसिलिंग देना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया है और इसी के कारण सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन का एलान किया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीएम राहुल सिंह ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में लोगों का बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पश्चिम जिला के जिला प्रशासन ने इस्कॉन द्वारका के साथ मिलकर आध्यात्मिक परामर्श देने के लिए हेल्पलाइन लॉन्च की है। कोविड-19 के कारण बनी तनावपूर्ण स्थिति में लोगों को मन की शांति प्रदान करना इस हेल्पलाइन का उद्देश्य है। इस हेल्पलाइन नंबर पर लोगों को परामर्श देने के लिए दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में पारंगत 1000 से ज्यादा विशेषज्ञ परामर्शदाताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन पीयूष गोयल (प्रद्युम्न प्रिया दास) ने कहा, संसाधनों की कमी, अनिश्चितता और कोरोना वायरस को लेकर सूचनाओं के बाढ़ के बीच लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। युवा करियर को लेकर असुरक्षा की भावना, चिड़चिड़ेपन और निराशा से संघर्ष कर रहे हैं। काम के दबाव से गृहिणियां हताश हैं। बुजुर्ग असहाय अनुभव कर रहे हैं। माता-पिता बच्चों के अनियंत्रित व्यवहार के कारण परेशान हैं। इस तरह की समस्याओं की सूची बहुत लंबी है। सेक्टर-13, द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर सभी युवाओं, परिवारों, बुजुर्गों और अपने साथ जुड़े 50,000 से ज्यादा सदस्यों की काउंसिलिंग कर रहा है। इन दिनों में हमारे सदस्य शांति एवं सुकून का अनुभव कर रहे हैं।

प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सहायता से इस हेल्पलाइन को हफ्ते के सातों दिन चौबीसों घंटे चलाया जाएगा। फोन करने वाले की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। इस्कॉन दिल्ली एक राज्य स्तरीय एनजीओ है और लॉकडाउन के दौरान पांच लाख जरूरतमंदों को रोजाना भोजन कराया है। लॉकडाउन के दौरान अधिकतम 5,11,600 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज किया गया है।

4 पॉजिटिवों तो मिले पर 20 ने जीती कोरोना से जंग

कोरोना में आफत से राहत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में शुक्रवार को जहां एक तरफ चार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये गए हैं। वहीं देर शाम तक राहत भरी खबर यह मिली कि 20 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। इनमें एक 73 वर्षीय बुजुर्ग समेत एक वर्षीय बच्चे ने भी कोरोना को मात दी है। जिला सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि एक दिन में 20 मरीज डिस्चार्ज किए गए है। ऐसे में अब हम कोविड-19 पर विजय पा सकते है।

यहां से आए पॉजिटिव

नोडल अधिकारी डॉ. रामभगत ने बताया कि शुक्रवार को चार पॉजिटिव मरीज सामने आए है। जिसमें एनएच-चार स्थित आदर्श नगर कालोनी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह यूपी के जेवर इलाके से घर लौटा था। सेक्टर-16 निवासी 32 वर्षीय एक बैंक कर्मी भी पॉजिटिव आया है। पिछले दिनों वह दिल्ली से होकर आया था। 47 वर्षीय इंद्र नगर निवासी एक गृहणी पॉजिटिव पाई गई है। वह किडनी रोगी है और उसकी डायलिसिस चल रही है। इसके अलावा एनएच-एक के डी ब्लॉक से एक 50 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। वह पिछले दिनों मुम्बई से लौटा है। फिलहाल उसे होम आइसोलेट किया है।

यह है आंकड़े

डा. रामभगत ने बताया कि जिला में अब तक 9047 यात्रियों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 3145 लोगों का निगरानी में रखने का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 5896 लोग अंडर सर्विलांस हैं। कुल सर्विलांस में रखे गए लोगों में से 8862 होम आइसोलेशन पर हैं। अब तक 8758 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 7845 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है तथा 728 की रिपोर्ट आनी शेष है।

अब तक 185 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 63 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है तथा 4 पॉजिटिव मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है।

बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात

सीएमओ डॉ. कृष्णकुमार ने बताया कि ठीक होने वाले मरीजों में पलवली गांव की 44 वर्षीय महिला, अनखीर गांव की 41 वर्षीय महिला, एनएच दो निवासी निजी लैब की 21 वर्षीय रिस्पेसनिस्ट, सेक्टर-28 निवासी 42 वर्षीय महिला और 73 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने कोरोना को मात दी है। वह अपनी मृतक पत्नी के सम्पर्क में आने से पॉजिटिव हुए थे। सेक्टर-16 निवासी 41 वर्षीय पुरुष, मिल्हार्ड कालोनी से 30 वर्षीय व्यक्ति, भूड़ कालोनी से 42 वर्षीय व्यक्ति, फतेहपुर बिल्लौच से 35 वर्षीय व्यक्ति, ओटोपिन झुग्गी से 70 वर्षीय व्यक्ति, आदर्श कालोनी निवासी एक वर्षीय बच्चा, हरी बिहार से 34 वर्षीय व्यक्ति और 12 वर्षीय बच्चा, एनएच-एक से 50 वर्षीय ऑटो ड्राईवर, सीही गांव से 35 वर्षीय व्यक्ति, डबुआ कालोनी से 50 वर्षीय व्यक्ति मंडी के सम्पर्क में आने से हुआ था पॉजिटिव, बाढ़ मौहल्ला का 36 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी ठीक हुआ है। वहीं डबुआ मंडी के आढ़ती 47 वर्षीय और 38 वर्षीय व्यक्ति भी डिस्चार्ज किए गए है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए तैयार रहे एसओपी: डीसी

फरीदाबाद। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण जैसी गतिविधियों के लिए जो एसओपी बनाई गई है, उसके अनुसार संबंधित विभाग अपने कार्य को समय पर पूर्ण कर लें। इसके लिए कई विभागों द्वारा आवश्यक तैयारियां की जानी है, वे अपनी तैयारियां सभी जरूरी इंतजाम के साथ करें तथा इन तैयारियों के संबंध में एक मॉक ड्रिल अवश्य कर लें। उपायुक्त शुक्रवार को बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग अपने कंट्रोल रूम स्थापित कर लें तथा इसके अलावा वे ओखला व गाजियाबाद के कंट्रोल रूम से भी अपना समन्वय स्थापित कर लें, क्योंकि अधिक पानी की सूचना उन्हें इन्हीं कंट्रोल रूम के माध्यम से मिलेगी।

इसके लिए जिला में रिलीफ सेंटर बनाने के लिए गांवों व अन्य स्थानों पर जगहों व भवनों को चिन्हित कर लें। जरूरी सामान की उपलब्धता तय कर लें तथा इसकी एक सूची भी तैयार कर लें। गोताखोर, नाव, चाबुक, नाव का इंजन आदि, सभी सामान की वर्किंग व उपलब्धता को चेक कर लें। इस कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करें, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में राहत कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकें।

9 नए इलाकों के साथ जिले में 41 कंटेनमेंट जोन घोषित

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

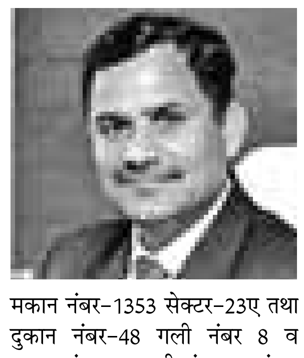

जिलाधीश यशपाल ने जिला में कंटेनमेंट जोन की सूची संशोधित की है, जिसके तहत नए क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल किए हैं। जिलाधीश ने बताया की पहले घोषित 32 कंटेनमेंट जोन के अलावा और 9 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं जिससे सम्बंधित क्षेत्रों में भी कंटेनमेंट जोन के नियम लागू होंगे।

जिलाधीश ने बताया कि कंटेनमेंट जोन की सूची में शिव दुर्गा विहार, पलवली गांव, डबुआ कॉलोनी, सेक्टर-88 स्थित एफ ब्लॉक, एनआईटी-1 स्थित ब्लॉक-ए, बी, सी, गांव बड़खल एवं अनखीर, सेक्टर-28, बाढ़ मोहल्ला ओल्ड फरीदाबाद, ब्लॉक-बी जवाहर कॉलोनी, मुजेसर, ग्रीन फील्ड कॉलोनी को शामिल किया गया है। इसी प्रकार संजय कॉलोनी, सेक्टर-23 का मकान नंबर-एमसीएफ 9470, गली नंबर 294, 295 नजदीक गौंछी ड्रेन, एमसीएफ-9491, गली नंबर 295, दुकान नंबर 8810 नजदीक गली नंबर 285 और प्लाट नंबर एफ-12 वर्कशाप एरिया को कंटेनमेंट जोन नंबर-13 बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन-14 में सेक्टर-23ए व संजय कॉलोनी में मकान नंबर-1235, मकान नंबर-1648, मकान नंबर-1353 सेक्टर-23ए तथा दुकान नंबर-48 गली नंबर 8 व दुकान नंबर 13 गली नंबर 3, संजय कॉलोनी का एरिया शामिल किया गया है। कंटेनमेंट जोन-15 में प्लाट नंबर 1136 से 1145, 1520 से 1563, 1886 से 1961, 1962 से 1965, 2028 से 2031, 2032 से 2041, 2079 से 2087, 2935 से 2937, 2980 से 2982, सेक्टर 62 का क्षेत्र शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन-16 में आदर्श कॉलोनी नजदीक मुक्ता होटल के क्षेत्र में दुकान नंबर जे-1, दुकान नंबर 370, दुकान नंबर 303 और दुकान नंबर-जे-59 का एरिया शामिल किया गया है। कंटेनमेंट जोन-17 में प्लाट नंबर 288 से 701, सेक्टर-18 हाउसिंग बोर्ड कालोनी का एरिया शामिल किया गया है। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन-18 में गांव फतेहपुर चंदीला में सुखबीर सिंह एडवोकेट का मकान से, फिरेह चंदीला, विजय चंदीला और पंचायत भवन का एरिया शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन-19 में गांव माहोला, कंटेनमेंट जोन-20 में गांव सीही, कंटेनमेंट जोन-21 में बल्लभगढ़ की शिव शारदा कॉलोनी, कंटेनमेंट जोन-22 में तिलपत सेक्टर-9 में मवाई रोड पर शिव मंदिर से महेंद्रा बिल्डिंग मैटेरियल शॉप तक का एरिया शामिल किया गया है।

कंटेनमेंट जोन-23 में सेक्टर-17 में प्लाट नंबर 666(पी) से 658(पी) व प्लाट नंबर 853(पी) से 870(पी) तक का एरिया भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन-24 में सेक्टर 10 में प्लाट नंबर 996 से 966 तक तथा प्लाट नंबर 739 से 759 तक का एरिया शामिल किया गया है। कंटेनमेंट जोन-25 में सेक्टर 5 इंदिरा कॉलोनी और कंटेनमेंट जोन-26 में रेलवे रोड व सेक्टर 22 व 24 के डिवाइडिंग रोड पर स्थित नाला के साथ आटो पिन झुग्गी का पूर्ण एरिया शामिल किया गया है।

कंटेनमेंट जोन-27 में प्लाट नंबर 8 पी से 21 पी, 75 पी से 90 पी, 91 पी से 114 पी, 161 पी से 198 पी और प्लाट नंबर 168 पी से 175, 183 से 191 पी, 215 पी से 218, 235 से 238 पी एवं 116 पी से 141 पी सेक्टर 14 कि पंक्ति को शामिल किया गया है।

फांसी लगाकर की आत्महत्या

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

बल्लभगढ़ की आईएमटी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने शुक्रवार को घरेलू कलह से परेशान होकर घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया है।

थाना सदर पुलिस के मुताबिक मूलरूप से यूपी का रहने वाला 40 वर्षीय नवरत्न पिछले कुछ समय से चंदावली गांव के निकट आईएमटी कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। यहां पर रहकर वह मेहनत मजदूरी का कार्य करता था। नवरत्न पिछले कई दिनों से घरेलू कलह से परेशान चल रहा था। इसलिए वह मानसिक तनाव में रहता था। शुक्रवार को उसकी पत्नी किसी काम से बाहर चली गई। इस बीच नवरत्न ने घर में फांसी लगा ली। महिला ने घर में पति को फांसी पर लटके देख पुलिस को सूचना दी। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

दो महीने बाद खुला रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

कोरोना महामारी और लगातार चल रहे लॉकडाउन के बाद शुक्रवार को करीब दो महीने बाद खुले रेलवे स्टेशन के आरक्षण केन्द्र पर टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू हुई। इसकी सूचना मिलने पर कुछ लोग बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर भी टिकट बुकिंग करवाने पहुंच गए। लेकिन वहां सिस्टम शुरू न होने के कारण बुकिंग नहीं हो सकी। इससे वहां आए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।

परेशान लोगों को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर आना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक एक जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा के बाद से रेल मंत्रालय ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। हालांकि 30 ट्रेन पहले से चल रही थी और उनकी बुकिंग भी हो रही थी। रेलवे ने 200 ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

इनके लिए टिकट बुकिंग का काम शुरू किया गया है। इनमें फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर भी टिकट बुकिंग के लिए खोले गए। कुल 230 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हुई है। 50 फीसदी स्टॉफ और 50 फीसदी काउंटर खोलने के नियम पर दोनों जगह काम शुरू हुआ।

संक्षिप्त समाचार

अब तक 42 हजार को भिजवाया राशन

फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित फरीदाबाद कालीबाड़ी राष्ट्र में घोषित लॉकडाउन के आरम्भ से ही समाज के जरूरतमंद लोगो के लिए अपने परिसर से प्रत्येक रोज़ बने हुए पौष्टिक भोजन रेडक्रॉस सोसाइटी, फरीदाबाद के माध्यम से भिजवाती रही है। अपने इस लगातार और निस्वार्थ प्रयास में 22 मई तक फरीदाबाद कालीबाड़ी ने लगभग 42 हज़ार बिस्थापित श्रमिकों एवं जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचने में सफल रही है। राष्ट्र व्यास शंकित की इस घड़ी में समाज के लिए फरीदाबाद कालीबाड़ी की यह अथक प्रयास और मनोभावना एक मिशाल बनती जा रही है। ईश्वर फरीदाबाद कालीबाड़ी के सदस्यों एवं शुभचिंतको को सदा स्वस्थ और खुश रखे जिनके निस्वार्थ भावना एवं सहयोग से यह संभव हो पाया है। फरीदाबाद कालीबाड़ी द्वारा मानव सेवा की इस महान कार्यक्रम को लॉक डाउन के चौथे चरण में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया और जब तक जरुरत रहेगी संगठन अपने यथा सामर्थ्य सहयोग देती रहेगी।

वेबीनार के माध्यम से दिया कोविड-19 से लड़ने का साहस

फरीदाबाद। हमेशा याद रखें कि जीवन संघर्ष भरा है। खुद के लिए नई - नई चुनौतियां पैदा करें, सकारात्मक सोचते हुए अपनी कोशिशों में सुधार करते रहिए। जीवन में फिर चाहे कितनी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो हमें डरना या घबरा कर भागना नहीं है बल्कि डटे रहना है, सीखते रहना है, कुछ नया व सर्जनात्मक करने की कोशिश करते रहना है। बस याद रहे चुनौतियां अवसर हैं इन से डरे नहीं, इन्हें पहचाने और स्वीकार करें। उसी अनुसार अपनी कार्ययोजनाओं को तैयार करें। उक्त बातें हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महत्वाकांक्षी परियोजना बाल सलाह, परामर्श व कल्याण केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत बल्लभगढ़ स्थित स्वयंसेवी संस्था बदलाव हमारी कोशिश के फेसबुक पेज और उनके साथ जुड़े हुए सभी संस्थान के सदस्यों के साथ-साथ राज्य भर के लोगों हेतु लॉकडाउन अवधि के दौरान आयोजित किए जा रहे वेबीनार के माध्यम से मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक एवं राज्य परियोजना नोडल अधिकारी, अनिल मलिक द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि कोरोना माहवारी की वजह से घोषित लॉकडाउन के दौरान लोगों में भले ही एक मायूसी का माहौल सा है लेकिन इससे निकलने के लिए उर्जा हमें अपने शरीर में कायम रखनी होगी। यह समय आत्मचिंतन और आत्ममंथन का भी है इसलिए खुद को जान लें। रोजाना का उद्देश्य निर्धारित करें और फिर उसे प्राप्त करने के लिए जुट जाएं। चिंता, तनाव, अनिद्रा जैसी मनोस्थिति के दौरान अगर कोई इंसान अकेलापन महसूस करता है, ज्यादा चिंता ग्रस्त रहता है तो अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने परिवार में ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान दें कि कोई अपने आप को दिनचर्या से या सामाजिक जीवन से दूर न रखें। तनाव से बचने के उपाय यही हो सकते हैं कि इंसान उत्साही बना रहे, खुशी से दोस्ती करें, मनपसंद कार्य जैसे बागवानी, संगीत सुनना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना जारी रखें।

समस्याओं को लेकर त्रिखा ने बुलाई बैठक

फरीदाबाद। बडखल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा ने शुक्रवार को फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त डॉ. यशपाल गर्ग अन्य निगम अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर विधानसभा क्षेत्र के सभी दस वार्डों, आठों गांवों तथा कालोनियों में पानी व सीवरेज का समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। विधायक सीमा त्रिखा ने बैठक में बताया कि उन्होंने प्रदेश के बजट सत्र के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में उठाया था तथा स्पीकर ने इनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके हल निकालने का आदेश दिया था। इसी के तहत विधायक सीमा त्रिखा ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में उनके विधानसभा क्षेत्र के सभी दस वार्डों के अंतर्गत आने वाले आठ गांवों भांखड़ी, नवादा, बडखल, अनखीर, फतेहपुर चंदीला, मेवला महाराजपुर, अनंगपुर, लकड़पुर व गांव खोरी के साथ-साथ एसजीएम नगर, नेहरू कालोनी, शिव दुर्गा विहार, साथ लगते डेरे तथा सेक्टर-21 आदि क्षेत्र के नागरिकों को पानी तथा सीवरेज की समस्या से न जूझना पड़े इसके लिए सभी जरूरी कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।

विद्यार्थी भेज सकते हैं यूएमसी संबंधी केस

फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और मुक्त विद्यालय की परीक्षा में जिन विद्यार्थियों के खिलाफ नकल संबंधी केस बनाए गए थे, वह विद्यार्थी शिक्षा बोर्ड की ई-मेल या फिर वॉट्सएप नंबर पर अपना प्रोफार्मा भरकर 27 मई तक भेज सकते हैं। कोविड 19 के कारण शिक्षा बोर्ड कार्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थी ऑनलाइन ही अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इस परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन संबंधी केस दर्ज किए गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को कोविड 19 के कारण व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय पर बुलाया जाना संभव नहीं है। ऐसे नियमित परीक्षार्थियों को उनके स्कूल के मुखिया की ई मेल पर यूएमसी प्रोफार्मा भेज दिया गया है। संबंधी विद्यालय के मुखिया अपने विद्यालय के यूएमसी परीक्षार्थियों को अवगत करवाए कि वह यह प्रोफार्मा भरकर ईमेल आईडी ई-मेल आईडी asumc@bseh.org.in या बोर्ड के वॉट्सएप नंबर 88168403349 पर 27 मई तक भेज दें।

कोरोना से निपटने को प्रशासन ने बनाई ठोस रणनीति

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

उपायुक्त यशपाल ने कहा कि कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं से लड़ने के लिए जिलास्तर पर विभिन्न समितियां व प्रशासनिक संरचनाओं का गठन किया गया है। प्रशासनिक कार्यों को दक्षतापूर्ण के साथ करने तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को एकल कमांड के साथ निपटाने के लिए यह समितियां कार्य कर रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी से काम करना बहुत जरूरी है।

उपायुक्त ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में बताया कि जिला में

जिलास्तर पर एक कमेटी, जोनल स्तर पर 8 कमेटी, मॉनीटरिंग कमेटियों की संख्या 53, सेक्टर कमेटियों की संख्या 266 तथा लोकल कमेटियों की संख्या 1327 के साथ एक प्रशासनिक संरचना बनाई गई है। एक लोकल कमेटी में करीब 10 लोग सदस्य होंगे तो करीब 13 हजार से अधिक संख्या में एक मजबूत प्रशासनिक कड़ी बन गई है। इसी प्रकार पूरे जिले में भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से एक 250 संरचनाओं की छोटी इकाई से हिसाब से बांटा जाए। उस क्षेत्र में तीन सरकारी अधिकारियों व सिविल सोसायटी के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाए।

इस प्रकार बनाई गई कड़ी में एक सदस्य के पास उसके साथ लगते 10 से 20 घर ही आएंगे तथा प्रत्येक 5 लोकल कमेटी के ऊपर एक प्रभारी होगा, जिसे सेक्टर समिति के रूप में जाना जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक 5 सेक्टर कमेटी के ऊपर एक जोनल कमेटी काम करेगी तथा पांच जोनल कमेटी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो उसके अधीन पूरे पदानुक्रम को नियंत्रित करेगा।

सादगी से मनाई सिद्धदाता आश्रम के संस्थापक की पुण्यतिथि

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय के तीर्थ क्षेत्र श्री सिद्धदाता आश्रम एवं श्री लक्ष्मीनारायण दिव्यधाम के संस्थापक वैकुंठवासी स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज की पुण्यतिथि बड़ी सादगी के साथ मनाई गई। गत 13 वर्षों में पहली बार इस अवसर पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। हालांकि विभिन्न सोशल प्लेटफार्म के जरिया इसका प्रसारण दुनिया भर में रह रहे भक्तों ने देखा। वैकुंठवासी स्वामी सुदर्शनाचार्य ने वर्ष 1989 में श्री सिद्धदाता आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद वर्ष 2007 में श्री लक्ष्मी नारायण दिव्यधाम

का लोकार्पण कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर परलोक गमन कर गए थे। तब से हर वर्ष 22 मई को आश्रम में उनकी पुण्यतिथि हजारों भक्तों की उपस्थिति में मनाई जाती है। एक विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर को भक्तों के लिए बंद किया गया है।

चोरी के प्रयास में गिरफ्तार

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ के मोहना रोड स्थित एक मकान में चोरी करने घुसे युवक को मकान मालिक ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि उसके अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना शहर में दर्ज मामले के मुताबिक मोहना अहीर हवेली निवासी राजकुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि बीती रात साढ़े दस बजे वह अपने मकान के सामने रोड पर टहल रहे थे। तभी अचानक रोड के दूसरी तरफ नीरज अस्पताल के उपर वाली बिल्डिंग पर कुछ युवक चोरी की नीयत से ग्रिल लांघकर चढ़ते हुये नजर आए। जिस पर उन्होंने शोर मचा दिया।

मजदूर यूनियनों ने किया डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन

फरीदाबाद। इंकलाबी मजदूर केंद्र और औद्योगिक ठेका मजदूर यूनियन ने मजदूरों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ डीसी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। केंद्र की मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी के बहाने मजदूरों पर हमले तेज कर दिए हैं। बिना तैयारी के किए गये लॉक डाउन से मजदूरों पर अनेक मुसीबतें आ पड़ी है। फैक्ट्री मालिक लॉकडाउन के दिनों का वेतन नहीं दे रहे हैं। सरकार वेतन दिलाने के बजाय मजदूरों को अधिकार विहीन कर रही है। काम के घंटे 8 से बढ़ा कर 12 कर रही हैं। सरकारी उद्यमों को निजी

कम्पनियों को बेचा जा रहा है। रेल व बस नहीं चलने से सैकड़ों लोग बेमौत मारे चुके हैं। कोरोना संकट में भी समाज में साम्प्रदायिक जहर फैलाने की कोशिशें की गई। इन्हीं बातों को लेकर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों 22 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था।

मास्क बांटकर किया जागरूक

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एनएच-तीन स्थित राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य रवीन्द्र कुमार मनचन्दा की अध्यक्षता में विद्यालय की जेआरसी व एसजेएबी ने डलसा अर्थात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला व सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन दीपक गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार एवं मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में विद्यालय के शेल्टर होम में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों को कोविड 19 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मास्क वितरित कर उपाय

बताए।

एनएच तीन फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में बने शेल्टर होम इंचार्ज और प्राचार्य रवीन्द्र कुमार मनचन्दा ने विद्यालय में ठहर रहे सौ से भी अधिक प्रवासी मजदूरों को बताया कि अब हमे कोरोना के साथ ही जीने की आदत विकसित करनी होगी। कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी, हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना, नाक और मुंह ढक कर रखना आदि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए है, उनके अनुसार अपने आपको तथा दूसरों को संक्रमण से बचाना होगा।

सीएम को दी निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र भेजकर हरियाणा सरकार से 5000 करोड़ का राहत पैकेज मांग रहे और फीस न आने के कारण अध्यापकों को सैलरी न देने का बहाना कर रहे स्कूलों का सीएजी के द्वारा ऑडिट कराने की मांग की है। मंच ने लिखा है कि स्कूलों के पास करोड़ों रुपए सरप्लस व रिजर्व फंड के रूप में मौजूद है। मंच ने मुख्यमंत्री को बताया है कि स्कूल प्रबंधकों ने नए दाखिलों में एडवांस में ली गई फीस से ही करोड़ों रुपए जमा कर लिए हैं। इसके अलावा दाखिला फार्म 500 से 1200 रुपए में बेचकर और 6 महीने पहले किए गए दाखिले में एडवांस के रूप में अभिभावकों से 30 हजार से 110000 लेकर बैंक ब्याज के रूप में ही लाखों रुपए कमा लिए हैं। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि मंच ने आरटीआई लगाकर फरीदाबाद के 25 स्कूलों की जानकारी मांगी थी।

जिनमें से अभी सिर्फ 5 स्कूलों की ही जानकारी मिली है। प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी कक्षा की पढ़ाई जुलाई से पहले संभव नहीं है। जबकि स्कूल वालों ने नए दाखिले के छात्रों से अप्रैल मई-जून की फीस वसूल ली है। ऐसा ही सभी स्कूल प्रबंधक कर रहे हैं। शिक्षा विभाग पंचकूला के एक

सर्कुलर में कहा गया है कि सर्विस नहीं तो फीस नहीं। तब स्कूल प्रबंधकों द्वारा बिना पढ़ाई फीस लेना वह भी 9 महीने पहले पूरी तरह से गैर कानूनी है। शिक्षा नियमावली में भी नियम है कि स्कूल प्रबंधक दाखिला देकर एडवांस में फीस नहीं ले सकते हैं। मंच ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया है कि सभी स्कूल प्रबंधकों ने शिक्षा विभाग के निर्देशों के विपरीत अभिभावकों से डरा धमका कर अप्रैल, मई की बढ़ाई गई ट्यूशन फीस व अन्य फंडों में फीस वसूल ली है। उसके बावजूद वे अपने अध्यापकों को मार्च, अप्रैल की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। मंच ने कई बार इसकी शिकायत चेयरमैन एफएफआरसी फरीदाबाद से की है लेकिन दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कैलाश शर्मा ने यह भी बताया कि मंच ने आरटीआई के द्वारा कई स्कूलों के फार्म 6 व बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें काफी घपला नजर आया है जिनमें कई फंडों में अभिभावकों से फीस ली गई है उनको फार्म 6 में दिखाया ही नहीं गया है। चेयरमैन एफएफआरसी द्वारा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में भी ऑडिटर ने कई कमियों को दर्शाया है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार स्कूल वालों के पास काफी मात्रा में सरप्लस व रिजर्व फंड है। मंच ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की सीएजी से ऑडिट कराई जाए जिससे पता चल सके कि स्कूल प्रबंधक लाभ में है या घाटे में। क्यों कि इस कार्य के लिए मंडल कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित की गई।

अनाज मंडी में लगी आग

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में बने शेड से शुक्रवार की शाम को करीब साढ़े पांच बजे अचानक धुंआ उठने लगा। धुंआ देखकर मौके पर मौजूद मजदूरों ने बाल्टियों से पानी फेंकना शुरू किया। सूचना पाकर दमकल विभाग की दो गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। हादसे में गेहूं से भरे कई बोरों का नुकसान हुआ है। पानी की बौछार से कई टन गेहूं भी गीला होकर खराब हो गया है। मार्केट कमेटी के सचिव ऋषि कुमार ने बताया कि अनाज के बोरों में एक तरह का केमिकल लगाया है जो पेट्रोलियम बेस्ड होता है कई बार अधिक तापमान होने पर यह आग पकड़ लेता है। सही कारणों का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गेंहू के केवल बोरों को ही नुकसान हुआ है प्रभावित बोरों से अनाज निकाला जा रहा है।

नेपाल पर चीनी शिकंजा

महामारी के समय सीमा विवाद

यह निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि अपने निकटस्थ पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध हाल में मुख्यत: दो कारणों से असहज हुए हैं। पहला, छोटे देशों पर चीनी आर्थिक प्रभाव है जो औपनिवेशिक ढंब से कर्ज देकर उनको बेल्ट एंड रोड पहल जैसी बढ़ी ढांचागत परियोजनाओं में फंसाता है। दूसरा, भारत ज्यादा लाभदायक व समतापूर्ण आधार पर संबंध बनाने या छोटे देशों में पैदा बेचैनी दूर करने के बजाय राजनय में ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व भौगोलिक संबंधों पर ज्यादा जोर देना है। चीन से मिलने वाली आर्थिक खैरात के कारण हर देश भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों की बातें करने के बावजूद परस्पर लाभ के लिए बीजिंग के साथ हो जाता है। इसी कारण हाल में हिंदू-बहुल नेपाल के साथ भारत के संबंधों में तनाव आया है, जबकि उम्मीद थी कि नरेन्द्र मोदी सरकार की हिंदू-समर्थक नीतियों के चलते यह भारत के निकट आएगा। हमेशा सीमा व व्यापार मुद्दों का वार्ता के माध्यम से समाधान की बात करने वाले नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सुविधा के लिए लिपुलेख दर्रे तक भारत द्वारा सड़क निर्माण पर आक्रामकता दिखाई है। नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने कहा कि भारत ने क्षेत्रीय संप्रभुता तोड़ी तथा इसे वूहान किस्म के कोविड-19 से अधिक खतरनाक वायरस भी बता दिया। हालांकि, दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र पर दावों प्रति-दावों का लंबा इतिहास है, पर उनके व चीन के बीच 1954 में हस्ताक्षरित संधि के अनुसार, लिपुलेख भारतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन नेपाल ने इस स्थिति के विपरीत राजनीतिक व प्रशासनिक मानचित्र में संशोधन कर लिंपीधुरा, लिपुलेख व कालापानी को अपने क्षेत्र में दिखाया है। शायद इन

क्षेत्रों की वापसी की मांग करने वाला प्रस्ताव पास करने के लिए नेपाल संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने वाला है। हालांकि, कुछ दिनों पहले नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा था कि भारत के साथ सीमा विवाद समाधान की राजनयिक पहल की गई है। इस सड़क पर काम काफी पहले से चल रहा था और नेपाल ने कभी आपत्ति नहीं की थी। स्पष्ट रूप से वह चीन के इशारे पर यह कदम उठा रहा है, जबकि भारत एक ओर कोविड-19 महामारी तथा दूसरी ओर लद्दाख में चीनी आक्रामकता का मुकाबला कर रहा है।

भारत को नेपाल के चीनी शिकंजे में फंसने का ध्यान रखते हुए महामारी के समय सड़क उद्घाटन की घोषणा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी-नेकपा में ओली की स्थिति कमजोर हुई है और पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' व माधव कुमार का प्रभाव बढ़ा है, पर चीन ने तीनों के बीच समझौता करा दिया। इस कारण ओली भारत को अपना विरोधी समझ रहे हैं। चीनी षडयंत्र का प्रमाण अमेरिकी प्रशासन द्वारा सीमा पर तनाव बढ़ने पर जारी बयान है जिसमें चीन के 'परेशान करने वाले व्यवहार' का आरोप लगाया गया है। चीन से कंपनियां बाहर जा रही हैं और वह वर्तमान समय में संक्रमण व उसका स्रोत छिपाने के आरोप में वैश्विक स्वतंत्र जांच का सामना करने जा रहा है। चीन पर यह आरोप भी है कि उसने दुनिया की कोविड से पीड़ित अर्थव्यवस्थाओं में अधिग्रहण की गति तेज की है और भारत ने अपनी घरेलू कंपनियां बचाने का प्रयास किया है। आस्ट्रेलिया ने वूहान संक्रमण की निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथ चीनी जौ पर भारी टैक्स लगा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की तरह नेपाल का मुहरे की तरह प्रयोग व लद्दाख में तनाव पैदा कर चीन भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह चीन-विरोधी विमर्श में न शामिल हो। ऐसे में भारत उचित ही आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। उसे नेपाल के संबंध में उचित राजनीतिक व आर्थिक कदम उठाने चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारी खुली सीमा है और हमारे श्रमिक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए काम करते हैं। नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 90 प्रतिशत से अधिक चीन से आता है तथा वह नेपाल से परिवहन व वाणिज्यिक संबंध मजबूत कर रहा है। ऐसे में नेपाल के चीन का आर्थिक गुलाम बनने की आशंका है।

श्रम कानूनों में व्यापक परिवर्तन

भारत में लंबे समय से श्रम कानूनों में परिवर्तनों की प्रतीक्षा हो रही थी। लेकिन कामगारों के लिए जरूरी संरक्षण छीन कर राज्य सरकारें उनके मूलभूत अधिकारों से छेड़छाड़ कर रही हैं।

अजय कुमार
लेखक पूर्व सांसद एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं)

पूरी दुनिया आज वैश्विक महामारी के बोझ से दबी है और यह समय किसी भी मनुष्य के लिए कठिन है। लाखों लोग संकट का शिकार हैं और जब हमें लगता है कि स्थिति सुधर रही है, वायरस प्रकोप फिर बढ़ता दिखने लगता है। यह समय इसलिए भी कठिन है क्योंकि हमारे अनेक व खासकर वृद्ध प्रियजन संकट में हैं। वायरस के कारण दुनिया में तीन लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है तथा यह संख्या और बढ़ सकती है। वायरस के कारण जान गंवाने वालों में 'अटालिस्सा ब्वायज़' के विली लेवी भी शामिल हैं जो इस वर्ष अप्रैल में 73 वर्ष के थे।

लेवी ने दुनिया को बदलने वाला कोई बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा किया था। वे कोई खोजी, एक्टिविस्ट या सेलेब्रिटी भी नहीं थे। इसके बावजूद उनका निधन मुझे झकझोर गया। वे मानसिक दिव्यांग थे और अपने जैसे ही दिव्यांग लोगों के साथ हेनरी की टर्की सर्विस में 1974 से काम करते थे। उनका वेतन प्रति माह केवल 750 डालर था, पर उनको दशकों तक चली नौकरी से केवल 65 डालर मिले। फंड का बाकी पैसा सेवायोजक द्वारा बेड, बोर्ड, कपड़ो व चिकित्सा के नाम पर काट लिया जाता था, जबकि वास्तव में उनको शायद ही ऐसी कोई सेवा मिलती थी। उनको कभी रोजगार के अन्य विकल्पों की जानकारी नहीं दी गई और उनको बंकहाउस या आश्रयगृह में बदले गए एक पुराने स्कूल में रखा गया था। उनके प्रति होने वाला यह अमानवीय क्रूर व्यवहार एक कानूनी प्राविधान से संभव हुआ था जिसमें सेवायोजकों को दिव्यांगताओं के शिकार लोगों को न्यूनतम वेतन से कम देने का अधिकार मिला था।

सालों तक निष्क्रियता दिखाने के बाद सरकारी एजेंसियों ने 2009 में यह बंकहाउस खाली कराया। लेवी के घुटने की हड्डी टूटी थी और वे विकलांग बनाने वाले अवसाद से ग्रस्त थे। 2013 में ईक्वल अपारचुनिटी कमीशन द्वारा दायर एक मुकदमे में अन्य दावेदारों के साथ लेवी को विजय मिली। अदालतों ने अंतत: दिव्यांग लोगों के बेहतर वेतन व कार्यदशाओं के पक्ष में फैसला दिया। लेवी की यह कथा आज याद करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की कुछ राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तनों का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक ऐसे अध्यादेश का प्रस्ताव किया है जो बिजनेसों को लगभग सभी श्रम कानूनों के क्रियान्वयन से अगले तीन साल के लिए बाहर कर देगा। गुजरात सरकार ने भी घोषणा की है कि वह नए औद्योगिक निवेशों के लिए श्रम कानूनों से 1,200 दिन की छूट देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी श्रम कानूनों को काफी सीमा तक कमजोर करने का प्रयास किया है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने थोड़ा अलग रास्ता अपनाया है।

अपने राज्यों में निवेश आकर्षित करने के नाम पर किए जाने वाले श्रम कानूनों में परिवर्तन उत्पीड़क व निराधार हैं। इस उत्पीड़न का एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का अध्यादेश है जिसमें फैक्ट्रीज़ एक्ट के 'सुरक्षा व संरक्षा' वाला अध्याय बनाए रखते हुए 'स्वास्थ्य' तथा 'जोखिम वाली प्रक्रियाओं' के अध्याय हटा दिए गए हैं। ये प्राविधान सेवायोजक को बाध्य करते हैं कि वह कर्मचारियों को उपयुक्त हवादार स्थान दे, भीड़ लगाने से बचे, स्वच्छ कार्य परिवेश सुनिश्चित करे तथा शौचालयों व मूत्रालयों के लिए समुचित स्थान दे। क्या हम अपने श्रमिकों को ऐसा परिवेश देना चाहते हैं जो उनकी मूलभूत आवश्यकतायें भी न पूरी कर सके?

> सरकार की भूमिका संविधान में अंतर्निहित है। मूलाधिकारों संबंधी अनुच्छेदों या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों पर सरसरी नजर डालने से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को अपने नागरिकों के हित में काम करना चाहिए। लेवी के सेवायोजक हेनरी जैसे बिजनेसों ने मौका मिलने पर श्रमिकों से अनुचित लाभ उठाया है

परंपरागत रूप से श्रम को उत्पादन के चार अंगों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य तीन में भूमि, उद्यमिता व पूंजी शामिल हैं। जब हम उत्पाद के इन चारों तत्वों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ छवियां उभरती हैं। जहां उत्पादन के अन्य अंग एक प्रकार से सैद्धान्तिक संरचना हैं, वहीं श्रमिक मनुष्य हैं। लेकिन यह परंपरागत अवधारणा मानव श्रम को केवल आंकड़ों या व्यापक रूप से सैद्धान्तिक संरचना में बदल देती है।

हमें समझना चाहिए कि जहां उत्पादन के अन्य आयाम एकआयामी तथा उत्पादन बढ़ाने के साधन हैं, वहीं श्रम का अर्थ ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य लोगों के मानव जीवन से गहराई से जुड़े हैं। जब किसी पिता को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता है या वह खराब कार्यदशाओं के कारण मर जाता है तो यह केवल उत्पादन का नुकसान ही नहीं होता है। इससे एक पूरे परिवार का जीवन बरबाद हो जाता है।

सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भारत में श्रम कानूनों में सुधार की जरूरत है। देश के नियामक परिवेश को भी सरल बनाने की जरूरत है ताकि बिजनेस व उद्यमिता फल-फूल सके। लेकिन क्या मूल श्रम संरक्षणों को हटा कर यह उद्देश्य पूरा हो सकता है? अजीम प्रेमजी व किरन मजूमदार शा जैसे भारतीय बिजनेस के अग्रणी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं।

कोई भी संगठन अपने श्रमिकों के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि ऐसा व्यवहार बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। इसके बजाय बिजनेस फलने-फूलने के लिए मजबूत ढांचागत संरचना, कुशल श्रमशक्ति तथा स्वस्थ परिवेश जरूरी होता है। इन महत्वपूर्ण सरोकारों को संबोधित करने के बजाय संबंधित राज्य सरकारें श्रमिकों पर बोझ लाद कर आसान रास्ता निकाल रही हैं, जबकि बाकी चीजों के लिए उनको काफी परिश्रम करना होगा।

सरकार की भूमिका संविधान में अंतर्निहित है। मूलाधिकारों संबंधी अनुच्छेदों या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों पर सरसरी नजर डालने से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को अपने नागरिकों के हित में काम करना चाहिए। लेवी के सेवायोजक हेनरी जैसे बिजनेसों ने मौका मिलने पर श्रमिकों से अनुचित लाभ उठाया है और ऐसे अनेक सेवायोजक हैं।

ऐसे सेवायोजकों को केवल अपने हितों की चिन्ता रहती है। इस पर नियंत्रण के लिए ही हमारे पास लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें होती हैं। सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बिजनेस श्रमिकों के साथ अन्य उत्पादन साधनों जैसा व्यवहार न करें। संविधान सभी नागरिकों को मूलभूत गरिमा का संरक्षण प्रदान करता है। अत: इन मूल्यों की रक्षा करना सरकार की नैतिक व विधिक जिम्मेदारी है।

यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तथा इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं तो यह अत्यधिक आलोचना का विषय होगा। अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या हम अपने बच्चों को इन स्थितियों में काम करने की अनुमति देंगे? ऐसे में हमें क्या अधिकार है कि किसी कामगार को समुचित हवा या शौचालयों तक पहुंच से वंचित कर काम करने को मजबूर करें? ऐसे कदम का कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा और यदि ऐसा काम किया जाता है तो भी मानवीय गरिमा को केवल बैलेंस शीट के आंकड़ों तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

जैव सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक

सुरवि शर्मा
(लेखिका पेशे से एक चिकित्सक एवं स्तम्भकार हैं)

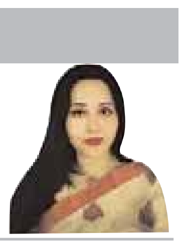

आनुवंशिक अभियांत्रिकी (जेनेटिक इंजीनियरिंग) 21वीं सदी का सीमांत विज्ञान है और चीन इस खेल का अग्रणी खिलाड़ी है। हम चीन के मकाओ में पैदा हुए आनुवंशिक रूप से संवर्धित बच्चों के बारे में पहले से ही जानते हैं। हम यह भी पता है कि अमेरिकी इंजीनियर जुआन कार्लोस ने दावा किया था कि उसने दुनिया का पहला मानव-बंदर मिश्रित भ्रूण चीन की एक प्रयोगशाला में सृजित किया था, क्योंकि उसके अपने देश में विधिक विनियमनों के कारण ऐसा विलक्षण शोध करना असंभव था। चीन विवादास्पद विज्ञानों की विश्व राजधानी बनता जा रहा है, जहां चिकित्सा शोध के क्षेत्र में नैतिकता के उल्लंघन होते हैं, जिनमें जीवन स्वरूपों का आनुवंशिक रूप से संवर्धन शामिल है। उपचार के लिए साथ ही साथ संभावित जैव युद्ध के क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान की इसी संपदा का प्रयोग बेहतर दवाएं एवं अन्य प्रोटीन बनाने हेतु सूक्ष्मसावयवों पर भी किया गया है। आधुनिक विषाणु विज्ञान का प्रमुख रूप से ध्यान इस पर रहा है कि ज़ोनोटिक वायरस किस तरह मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। हम जानते हैं कि सार्स और मेर्स चमगादड़ों से आते हैं मगर यह बात हमे यह मानने के लिए संतुष्ट नहीं करती कि कोविड-19 भी उसी मूल का है। अमेरिकी खुफिया तंत्र का कहना है कि कोरोनावायरस आनुवंशिक रूप से संवर्ध्धित नहीं है न ही कोई सावयव प्रयोगशाला से लीक होकर बाहर गया था। ओहिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शान लू लियू का कहना है कि जीन ट्वीकिंग के कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। वायरस का जीनोम अनुक्रम उपलब्ध है कि यदि इसमें बदलाव किया गया होता, तो हमें जीन फेरबदल, अंतरवेशन, विलोपन तथा न्यूक्लियोटाइड आधारों पर बदलावों के संकेत नजर आ गए होते। उन्होंने आगे बताया कि अनुक्रम में मुख्य बिंदु जो चमगादड़ में विषाणु से भिन्न हैं वे प्राकृतिक नजर प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन स्थलों पर जींस अव्यवस्थिति रूप से बिखरते हैं जैसे कि वे, प्रकृति में होते हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि वे इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि जैव तकनीकीविदों की किसी कुशल टीम द्वारा छिपाने के लिए उचित प्रयास किए जाते हों। जीनोमिक हस्तक्षेप का पता लगाने के लिए ऐसे शोध के निष्कर्षों तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता है क्योंकि वे बहुत विस्तृत होंगे।

यह देखा गया हे कि किसी वायरस में आनुवंशिक बदलाव आमतौर से क्षीण होने के रूप में परिणित होते हैं, जिसके चलते पूर्व में यह विश्वास पैदा हुआ था कि विषाणु जैव हमले बहुत निम्न होते थे। जैव आतंकवाद के सर्वाधिक संदिग्ध एजेंट एंथ्रैक्स

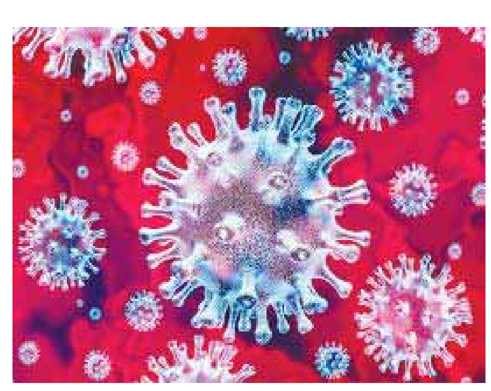

जैसे विषैले पदार्थ छोड़ने वाले जीवाणु रहे हैं। मगर वैज्ञानिकों ने अब कुछ ऐसे वायरसों की पहचान कर ली है जो पोक्स विषाणु, डेंगू के विषाणु, इबोलो विषाणु, लासा ज्वर विषाणु और अनेकअन्य सरीखे जैव आतंकवाद के संभावित अभ्यर्थी हो सकते हैं। अक्टूबर 2003 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना ने माउसपाक्स के अत्यधिक घातक स्वरूपों को जन्म दिया था जो विषाणुरोधी दवा अथवा वैक्सीन लगाने के बावजूद सभी चूहों को मार सकता है। शोध के द्वारा पॉक्स वायरस को उन लोगों के लिए भी घातक सावयव में बदले जाने की संभावनाएं उजागर की थीं जिनका टीकाकरण हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे शोध जोखिम भरे होते हें क्योंकि पाक्स वायरस को प्रजातियों को क्रास करने के लिए जाना जाता है। मगर आगे काम बंद नहीं किया गया क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका काम यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि जैव आतंकवादी क्या कर सकते हैं।

शोध में पाया गया कि संवर्धित वायरसों में से कई संक्रामक नहीं होते और यदि वे प्रयोगशाला से बाहर निकल भी जाते हैं तो भी वे किसी प्रजाति को नष्ट करके पारिस्थितिकीय उथल-पुथल का कारण नहीं बन सकते। हालांकि, ऐसी खोज का अर्थ यह भी है कि जैव आतंकवादी केवल लक्षित व्यक्तियों पर हमले हेतु किसी विषाणु को संशोधित करने के लिए इसी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो हमलावरों पर पलटकर नहीं आएगा, इस तरह जैव अस्त्र का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा।

विविध सावयवों के संपूर्ण आनुवंशिक अनुक्रम की उपलब्धता के साथ, ऐसे आंकड़ों के दुरुपयोग की चिंता बढ़ता जा रही है। कुछ नस्ली समूहों को निशाना बनाने के लिए विविध सावयवों से मिश्रण एवं मिलान एवं मानव जीनोमिक्स से प्राप्त अंतरदृष्टियों से इनके संयोजन की संभावनाएं यथार्थपूर्ण हैं। यह ज्ञात है कि कुछ नस्ली समूहों के कुछ रोगाणुओं से संक्रमित होने की संभावना अन्यों की तुलना में अधिक होती है तथा कुछ लोगों में आनुवंशिक भिन्नताएं प्रकट होती हैं क्योंकि सूक्ष्म सावयवों की चपेट में आने की संभावना व दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया भिन्न होती है। एक और तकनीक है डीएनए शफलिंग, जिसमें जैव अस्त्र विकास की संभावना होती है जिसका इस्तेमाल ईकोलाई का एक नया स्वरूप विकसित करने के लिए वैज्ञानिक स्टेमर ने किया था जिसने सेफोटैक्सिम नामक एंटबैबोयाटिक दवा के प्रति संवेदनशीलता घटा दी थी। ऐसे परिदृश्य में किसी मरीज में उपाचार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की संभावना होती है।

जीवन स्वरूपों का आनुवंशिक संवर्धन एक विवादास्पद कृत्य है। आनुवंशिक शोध कार्य के लिए कठोर विनियमन होने चाहिए जहां अनुमति केवल तभी दी जाए जब सकारात्मक परिणाम नकारात्मक परिणामों से कहीं ज्यादा हों। वर्तमान महामारी यह याद दिलाती है कि जैव अस्त्र में परिवर्तित सूक्ष्म सावयव शोध प्रयोगशालाओं के दुरुपयोग की संभावना पैदा कर सकते हैं, जहां मानव उत्तरजीविता को खतरे के उदाहरण देखने को मिलेंगें। जैव तकनीक विनियमन की प्रबल आवश्यकता है तथा एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय विनियामक संस्था बनाए जाने की भी जो कठोर नैतिक निर्देश दे सके। वर्तमान महामारी 1975 में जैव हथियार कन्वेंशन के गठन के पुनरीक्षण किए जाने एवं वर्तमान संदर्भ में नियम बनाए जाने की आवश्यकता को प्रकाश में लाई है। अब समय आ गया है कि देश अपनी जनता तथा अर्थव्यवस्थाओं को संभावित खतरों से बचाने के लिए जैव सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देना प्रारम्भ करें। हमारी पशु एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की ताकत व कमजोरी का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए एवं उपयुक्त जैव सुरक्षा प्रोटोकाल बनाए जाने चाहिए। यह ऐ ऐसा क्षेत्र है जिसकी दशकों से अनदेखी की जाती रही है और अब देशों एवं प्रजातियों की रक्षा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के लिए उसका पुनरीक्षण करना होगा।

आप की बात

भारत के बढ़ते कदम

कोराना वायरस से जूझ रहे भारत का, मोर्चा सम्भाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन अब वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी संगठन के चेयरमैन पद का दायित्व डॉ हर्षवर्धन के हाथ में होगा। बीते मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य असेम्बली के 194 देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डॉ हर्षवर्धन जापान के डॉ हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। आज पूरा विश्व कोरोना के चपेट में है जिसकी वजह दुनिया के कई देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय से गाइडलाइन जारी ना करने एवं चीन के द्वारा वायरस फैलने की खबर को छिपाने के बावजूद भी डब्लूएचओ द्वारा कोई कार्रवाई न करने को भी मानते हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत को सूझ-बूझ से काम लेना होगा। डब्लूएचओ के 34 कार्यकारी सदस्यों की वर्ष में दो बैठकें होती है जिसके सभी सदस्य स्वास्थय क्षेत्र में निपुण एवं अनुभवशील होते हैं। वह सभी पूरे विश्व में स्वास्थय से सम्बंधित प्रस्तावो पर मोहर लगाते हैं। इस समय कोरोना को लेकर चीन पर आरोप लग रहे हैं। अमेरिका भी अब जिम्मेदारी बदलने पर चीन पर कार्रवाई होने का दबाव बना सकता है।

– **अभिनव दीक्षित,** बांगरमऊ

चीन की कठपुतली डब्लूएचओ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन की कठपुतली बोल कर उसकी आलोचना की है जो आज की परिस्थितियों में प्रासंगिक लगती है। यही नहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन 30 दिनों में चीन के शिकंजे से बाहर नहीं निकला तो अमेरिका उसकी फंडिंग हमेशा के लिए रोक देगा और डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने पर भी विचार करेगा। आज जो भूमिका डब्ल्यूएचओ निभा रहा है उसको लेकर अमेरिका का गुस्सा जायज ही है.पूरी दुनिया कोरोनावायरस संक्रमण से पीड़ित है मगर डब्ल्यूएचओ केवल चीन की भलाई में ही लगा हुआ है ऐसे में अगर अमेरिका कुछ बोलता है तो सही भी है। यह यहां उल्लेखनीय है कि अमेरिका प्रति वर्ष 450 मिलियन डालर यानी करीब 35 सौ करोड़ रुपए फंडिंग करता है जबकि इसके मुकाबले चीन महज 38 मिलियन डालर यानी 290 करोड़ देता है। फिर भी डब्ल्यूएचओ चीन के इशारे पर क्यों नाचता है यह समझ से परे है? अमेरिकी प्रशासन कोरोना को लेकर तेश में है ऐसे में उसका कोई भी कदम डब्ल्यूएचओ के लिए घातक हो सकता है। इसलिए अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करने मे ही दुनिया का फायदा है।

– **अमृतलाल मारू,** धार, दसई

सतर्कता बरतना जरूरी

भारत अभी कोरोनावायरस के भीषण संकट से गुजर रहा है।इसको लेकर अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। परंतु लाक डाउन को हुए लगभग डेढ़ महीने हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मानव व्यवहार में सतर्कता लानी होगी। जैसे रहन-सहन ,खान-पान ,उठने बैठने आदि हर प्रकार के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने होंगे। केवल इसी के चलते हम आगे भी इस चुनौतीपूर्ण समस्या से बच पाएंगे।इसी बीच यह भी देखा गया है कि मानव अपनी स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हो गया, यह कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है।यह चीज भी देखने लायक थी कि, ना ही हमारे भारत में न तो चीन जैसी सख्ती है, ना अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था और ना ही कोरिया जैसी कम जनसंख्या। परंतु फिर भी समय-समय पर सरकार के द्वारा किए जा रहे सराहनीय प्रयासों से जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था पटरी में आ जाएगी। लाग डाउन में यह भी देखा गया कि लोगों ने बहुत से घरेलू उपाय अपनाए हैं।

– **सुदर्शन सोराड़ी,** नानकमता

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

फरमाया

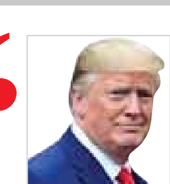

चीन की ओर से प्रवक्ता मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, और उस दर्द व मौतों को नकारने का प्रयास करते हैं जो उसने सारी दुनिया में फैलाई हैं।

– **डोनाल्ड ट्रंप**
अमेरिकी राष्ट्रपति

मैं नहीं जानता कि क्यों पहला लाकडाउन मात्र चार घंटे की नाटिस पर घोषित किया गया जिसके कारण बहुत से प्रवासी श्रमिकों को संकट का सामना करना पड़ा।

– **नौशाद फोर्ब्स**
पूर्व सीआईआई अध्यक्ष

मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि वो आकर उन जगहों का दौरा करें और व्यक्तिगत रूप से समझें कि राज्य में कैसी तबाही हुई है।

– **ममता बनर्जी**
बंगाल की मुख्यमंत्री

सस्ती राजनीति कर रही है कांग्रेस

कोटा में पढ़ रहे बच्चों को उप्र की सीमा तक छोड़ने के लिए किराया मांगना ही कांग्रेस का असली चरित्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान के कोटा में जब छात्र भूख से बिलख रहे थे, बीमार थे, तब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को उनकी याद क्यों नहीं आई। वह इन छात्रों को बसों से कम से कम बार्डर पर ही छोड़ देते, तब ये बसें कहां गई थीं। उन्होंने कहा कि तब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 630 बसें भेजकर अपने छात्र छात्राओं को वापस बुलाया और सुरक्षित तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब स्वयं योगी सरकार की इस पहल की तारीफ की थी।

उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि एक ओर कांग्रेस प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए एक हजार बसें देने का दावा कर रही है वहीं दूसरी ओर राजस्थान के कोटा से बच्चों को उप्र की सीमा तक पहुंचाने के एवज में कांग्रेस ने पूरी बेशर्मी के साथ किराया और डीजल का भी पैसा उप्र सरकार से ले लिया। उन्होंने कहा कि इस भुगतान के लिए राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले 27-28 अप्रैल को चिट्ठी भेजी और फिर 8 मई को रिमाइंडर भेजा, जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 मई को कर दिया गया है। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर कांग्रेस के बहाए जा रहे आंसू घड़ियाली हैं। इस संबंध में उसकी सारी संवेदनाएं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा हैं। एक बार फिर कांग्रेस का दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया। इसके लिए वह प्रवासी श्रमिकों और देश से माफी मांगे।

डॉ. शर्मा ने कहा कि पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि कोटा में पढने वाले उप्र के बच्चों को सरकार सुरक्षित उनको घर वापस पहुंचाएगी। अनुमान था कि बच्चों की संख्या करीब 10 हजार होगी। उसी के अनुसार वहां बसें भेजी गयीं, पर बच्चों की संख्या करीब 12 हजार थी। बच्चों की तकलीफ देखकर उप्र के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार से अतिरिक्त बसें मुहैया कराने को कहा। वहां के अधिकारियों ने कहा कि बसें तो हम दे देंगे, पर किराया लेंगे। इसलिए लिखित अनुरोध करें। लिखित अनुरोध पर उन्होंने अतिरिक्त बसों से बच्चों को फतेहपुर सिकरी तक भेजा। यही नहीं हमारी जिन बसों को डीजल दिया उसका भी भुगतान लिया। दरअसल अपने चरित्र के अनुसार प्रियंका वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस सिर्फ सस्ती राजनीति कर रही है। उसे शिगूफा छोडने के अलावा कुछ करना भी नहीं है।

परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि 36 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान हमने किया। डीजल का पेमेंट 19 लाख रुपये किया। ये लोग पैसा वसूल रहे हैं। ये लोग सेवा की नौटंकी बंद करें। कांग्रेस हिंदुस्तान के मजदूरों को गुमराह कर रही है।

वाहनों की भेजी लिस्ट में 1032 बसें हैं: आराधना मिश्रा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रवासी मजदूरों के लिए बसों को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच छिड़ा घमासान अभी शांत नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने मोर्चा संभाल लिया है। मोना ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को हमने एक हजार से अधिक वाहनों की सूची भेजी थी लेकिन सरकार की मंशा देश निर्माता श्रमिकों को लाने की नहीं थी इसलिए बहानेबाजी कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं यह बात पूरी जबाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि भेजी वाहनों की लिस्ट में 1032 बसें हैं। हमने एक-एक नम्बर दोबारा चेक किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर विधान परिषद के सभापति रमेश यादव विवेकाधीन अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि 40 लाख रुपये कोविड केयर फंड को प्रदान किए जाने हेतु अनुमति पत्र सौंपते हुए

पूर्व मंत्री के निधन पर सीएम ने दुख जताया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के पूर्व मंत्री डा. नेपाल सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपने सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डा. नेपाल सिंह एक वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनेता थे। वे एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। प्रदेश सरकार के मंत्री, लोक सभा सदस्य तथा विधान परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। डा नेपाल सिंह के निधन से जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए डॉ. नेपाल सिंह के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने डा नेपाल सिंह के आसमयिक निधन पर शोक व्यक्त किया हैं। श्री दीक्षित ने अपने शोक संदेश में कहा है कि डा नेपाल सिंह एक जनप्रिय नेता थे। विधान परिषद में मैंने उनके साथ काम किया है। वह संसदीय परंपराओं के ज्ञाता थे। विचार धारा के प्रति दृढ निश्चयी थे।

प्रवासी श्रमिकों की मौत पर सीएम दुखी, दी आर्थिक मदद

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुम्बई से गोपालगंज, बिहार जा रहे प्रवासी श्रमिकों की मीरजापुर में एक दुर्घटना में हुई मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने तथा इस हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिवंगतों के पार्थिव शरीर बिहार भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

चक्रवाती तूफान अम्फान से हुई जनहानि पर योगी ने जताया शोक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दैवीय आपदा से सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा और संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा राज्यों के पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए प्रदेश हर सम्भव सहायता व सहयोग के लिए तैयार है।

भाजपा की कथनी करनी में अंतर: त्रिवेदी

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने केन्द्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत का स्वागत करते हुए कहा है कि हमारे किसान मसीहा चौ. चरणसिंह का यही सपना था परन्तु भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर रहता है। देश के सहृदय किसानों को वर्ष 2014 में लागत मूल्य का दोगुना देने का वादा कर सत्ता में पहुँचने वाली भाजपा ने किसानों के ऊपर अपार जुल्मों की झडी लगा दी। कृषि यंत्रों पर जीएसटी से लेकर सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाले डीजल एवं बिजली मूल्यों की बढोत्तरी आदि से लेकर कर्जमाफी तक किसानों की अनदेखी ने नोटबन्दी तक किसानों की कमर टूट गई है।

यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है जिसके प्रति प्रशासन तंत्र ने उदासीनता का रवैया अपना लिया है। भाजपा सरकार की संकट से निबटने की इच्छाशक्ति भी कमजोर हो चली है। अब न तो कोई श्रमिकों की सुरक्षित और सम्मानित ढंग से वापसी में रूचि ले रहा है और नहीं नागरिकों की जिंदगी मौत के प्रति संवेदना जता रहा है। भाजपा सरकार प्रदेश की करोड़ों जनता को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर खुद निश्चिंत हो राजसुख भोगने में मग्न हो गई है।

अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच और क्वारंटाइन स्थलों के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं

लेकिन सच यह है कि इनकी हालत बेहद खराब और दयनीय है। क्वारंटाइन किए जाने वाले श्रमिकों को तालाबों, पोखरों और उजाड़ जगहों में पशुओं से भी बुरी दशा में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रशासनिक पंगुता और शिथिलता के चलते ही लोग अब निजी क्वारंटाइन सेन्टरों की ओर रूख कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्टों को लेकर भी विवाद होते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों के प्रति आवश्यक निर्देशों का पालन नहीं होने की खब्रें आती रही है। लोगों की जिंदगी के साथ यह सरकार जैसा खिलवाड़ कर रही है वह अत्यंत दु:खद और अमानवीय है।

पौधरोपण की अभी से करें तैयारी: केशव

लखनऊ। उपमुख्मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह सड़कों के किनारे व विभाग की खाली पड़ी भूमि तथा निरीक्षण भवनों आदि में बड़े पैमाने पर पौधरोपण करने की अभी से तैयारी करें व इस हेतु ठोस व प्रभावी कार्ययोजना बनायें। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के महत्व व उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके सामाजिक दायित्वों का बोध कराते हुये कहा है कि वर्षा काल आने पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाय। उन्होंने हर्बल रोड भी विकसित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि विभाग में जो बहुत पुराने शासनादेश हैं और अनुपयोगी व अनावश्यक हैं, उन्हे निरस्त करने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाय।

राजस्थान सरकार का यूपी से बसों का किराया मांगना अमानवीय: मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी मज़दूरों की परेशानियां बढ़ती नज़र आ रही हैं। इस बीच बस को लेकर शुरू हुई सियासत में योगी सरकार और कांग्रेस के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। पिछले दिनों राजस्थान सरकार की तरफ से कोटा से यूपी बॉर्डर तक भेजे गए बच्चों की बसों का किराया मांगने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे कंगाली का प्रदर्शन तक करार दे दिया है।

शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12000 युवक-युवतियों को वापस

उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो माँग की है वह उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुख:द। आगे मायावती ने लिखा कि लेकिन कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल कर रही है यह कितना उचित व कितना मानवीय है।

उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को जमानत

लखनऊ (विसं)। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को धोखाधड़ी व कूटरचना के एक मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया। याची के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी में मुकदमा पंजीकृत है। याची के वकील की दलील थी कि वो 22 नवम्बर, 2018 से जेल में है।

हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश

विधि संवाददाता। लखनऊ

सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला

सूबे में सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी में पैदा हुई आपत्तियों पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को विशेषज्ञ की राय के साथ 27 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश रिषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा सम्बंधी याचिका पर दिया है। शुक्रवार को पीठ के समक्ष इस याचिका पर जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति उठाई गई। कहा गया कि उत्तर कुंजी के विवादित चार उत्तरों को लेकर इस हलफनामे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जबकि यह इस मामले का मुख्य बिन्दू है। पीठ ने इस पर राज्य सरकार को विवादित उत्तरों के सम्बंध में एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। एकल पीठ ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर भी विचार किया जाएगा। याचिका में आठ मई, 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों पर आपत्ति जताई है। कहना है कि आपत्ति के सम्बंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर ही यह याचिका दाखिल की गई है।

हाईकोर्ट ने मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं की मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

विधि संवाददाता। लखनऊ

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लॉकडाउन में अपने घर लौटने वाले व इधर-उधर फंसे हुए मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं की स्टेटस रिपोर्ट केंद्र व राज्य सरकार से तलब की है। पीठ ने अगली सुनवाई तक यह स्टेट्स रिपोर्ट जरिए हलफनामा देने का आदेश दिया है। जस्टिस अनिल कुमार एवं जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने यह आदेश दिलीप कुमार मिश्रा की एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में मजदूरों को भोजन, पीने का पानी और मेडिकल आदि की आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई है। याचिका में यह सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है कि मजदूरों को भूखा नहीं छोड़ा जाए और उन्हें परिवहन की सुविधा भी मिले। पीठ के समक्ष इस याचिका की जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई हुई। इस दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने आश्वासन दिया कि प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में 21 अप्रैल व पांच मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पुनरीक्षण भी किया गया है। वहीं राज्य सरकार के वकील एचपी श्रीवास्तव ने दलील दी कि गृह मंत्रालय व सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन हो रहा है। पीठ ने इस पर दोनों सरकारों को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष बताए, अपना बयान दर्ज कराने के लिए कब और कैसे पेश होंगे मुल्जिम

विधि संवाददाता। लखनऊ

अयोध्या के विवादित ढांचे को ढहाए जाने का मामला

अयोध्या के विवादित ढांचा को ढ़हाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरण) ने बचाव पक्ष को एक बार फिर से यह बताने का निर्देश दिया है कि वो मुल्जिमों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान कहां और कैसे दर्ज कराएंगे। बीते 21 मई को भी विशेष अदालत ने इस मसले पर बचाव पक्ष से उनका जवाब मांगा था। शुक्रवार को विशेष जज सुरेद्र कुमार यादव ने अब यह बताने के लिए 26 मई की तारीख तय की है।

उन्होंने बचाव पक्ष से कहा है कि उस रोज प्रत्येक दशा में यह बताना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि बीते छह मार्च को इस मामले में गवाही के साथ ही जिरह की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने मुल्जिमों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए 24 मार्च की तारीख तय की थी। उस रोज से मुल्जिमों को बताया जाता कि उनके खिलाफ क्या गवाह एवं सबूत पेश किए गए हैं और इस पर उनका क्या कहना है। अदालत ने पहले दिन मुल्जिम चंपत राय बंसल, लल्लू सिंह व प्रकाश शर्मा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया था। लेकिन लॉकडाडन के चलते मुकदमे की कार्यवाही स्थगित चल रही थी। इधर, सीबीआई के एक गवाह जगत बहादुर अग्रवाल से बचाव पक्ष की जिरह नहीं हो सकी। इस गवाह ने अपने मोबाइल से बताया कि वो मथुरा में है। जो वर्तमान में रेड जोन इलाका है। लिहाजा वो अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ है। विशेष अदालत ने इस पर सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मथुरा के जिला अदालत की वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में इस गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। ताकि 26 मई को बचाव पक्ष यहां से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस गवाह से जिरह कर सके।

पंचायतों के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें: भूपेन्द्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिह चौधरी ने ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाले निर्माण कार्य समयानुसार कराये जाये और कार्यो का स्थलीय निरीक्षण नोडल अधिकारियों एवं उप निदेशकों से माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने खराब प्रगति वाले जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों से स्पष्टीकरण मॉंगे जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं। शुक्रवार को लखनऊ स्थित कैम्प कार्यालय में तीन मण्डंल लखनऊ, कानपुर व अयोध्या के उप निदेशक पंचायत एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के विभागीय कार्यो की प्रगति की समीक्षा वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर लम्बित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। साथ ही उन्होंने पंचायत भवन अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण, उपनिदेशकों द्वारा ग्राम पंचायतों का स्थलीय निरीक्षण, जिला पंचायतों में कांजी हाउस, सड़को की गडढा मुक्ति तथा जिला पंचायतों द्वारा निर्मित कराए जा रहे रिसोर्स सेंटरों की गहन समीक्षा की। उन्होने खराब प्रगति वाले जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों से स्पष्टीकरण मॉंगे जाने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि विभागीय समीक्षा बैठक का उद्देश्य कार्यपूर्ति के साथ ग्राम पंचायतों में प्रवासियों के आगमन से रोजगार सृजन की दिशा में कारगार पहल करना है।

जैव विविधता के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए: राज्यपाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अधिक से अधिक वन बगीचे, औषधीय पौधे रोपें

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को राजभवन से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर लखनऊ विश्वविद्यालय एवं जैव विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ई.संगोष्ठी हमारा समाधान प्रकृति में हैं का उद्घाटन किया। अपने सम्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि जैव विविधता से हमारी पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है, जो एक दूसरे के जीवन यापन में सहायक होते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न प्रजातियों को कहा जाता है। भारत अपनी जैव विविधता के लिए विश्व विख्यात है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत 17 उच्चकोटि के जैव विविधता वाले देशों में से एक है तथा पूरे विश्व की जैव विविधता में भारत की 7 प्रतिशत भागीदारी है। भारत की भौगोलिक स्थिति देशवासियों को विभिन्न प्रकार के मौसम प्रदान करती है। भारत में 17 कृषि जलवायु जोन हैं, जिनसे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। देश के जंगलों में विभिन्न प्रकार के नभचर, थलचर एवं उभयचर प्रवास करते हैं। इनमें रहने वाले पक्षी, कीट एवं जीव जैव विविधता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रकृति मनुष्य एवं जीव जन्तुओं के जीवन के प्रारम्भ से अंत तक के लिये खाने पीने, रहने आदि सभी की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। मनुष्य खेती कर भूमि से अपने भोजन हेतु अन्न एवं सब्जियां उगाता है तथा अस्वस्थ होने पर प्रकृति प्रदत्त औषधियों से उपचार करता है। पटेल ने कहा कि हमारा देश वैदिक काल से ही अपनी औषधीय विविधता के लिए प्रसिद्ध रहा है। अथर्ववेद में औषधीय पौधे एवं उनके प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसी तरह रामायण में भी बरगद, पीपल, अशोक, बेल एवं आंवले का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड.19 से बचाव हेतु क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग कई देशों द्वारा किया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन एवं निर्यात भारत द्वारा पूरे विश्व में किया जा रहा है। इस दवा का प्रयोग मलेरिया बीमारी के लिए होता है। यह चिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर जैव विविधता के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए और अधिक से अधिक वन, बगीचे,औषधीय पौधे एवं वृक्षों को लगाना चाहिए। इससे हमारे आस-पास के जैव विविधता में बढ़ोत्तरी होगी और पर्यावरण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इससे पहले राज्यपाल ने राजभवन से ही लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में महिला सामुदायिक प्रसाधन केन्द्र का ई.शिलान्यास किया और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर तथा लखनऊ शहर के जैव विविधता सूचकांक का लोकार्पण भी किया।

यूपी में आने वाली अमेरिकी कंपनियों को देंगे विशेष पैकेज: सिद्धार्थ नाथ

अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स, नार्थ इण्डिया काउन्सिल का सेमिनार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लघु एवं सूक्ष्म उधोग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि केरोना महामारी सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अमेरिकी मूल की जो कंपनियां चीन से बाहर जाकर अपनी उत्पादन इकाइयां भारत में और विशेष रूप से यूपी में इकाइयां लगाना चाहती हैं, उन्हें एक विशेष पैकेज देने के लिए तैयार है।

श्री सिंह इंडो अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स, नार्थ इण्डिया काउन्सिल और क्रिएट एनर्जी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के कोविड.19 के बाद अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश हाट डेस्टिनेशन पर आधारित सेमिनार को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निवेशकर्ता निवेश करने से पूर्व सरकार की प्रवृत्ति और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए ही

निवेश करता है। प्रदेश में निवेश और निवेशक दोनों ही सुरक्षित हैं। केंद्र और राज्य में एक स्थिर एवं निर्णायक नेतृत्व होने के कारण यूपी एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार द्वारा कई नीतिगत सुधार किए गए हैं जिसमें श्रम सुधार, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सुधार और खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा उपकरण, औद्योगिक यंत्र, चमड़ा और कपड़ा उद्योग। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी श्रमिकों को मानव पूंजी के रूप में उपयोग किया जाएगा। सरकार उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेमिनार मे वक्ताओ ने कहा कि जैसे.जैसे हम आगे बढ़ते हैं और कोविड.19 के साथ रहना सीख रहे हैं। हम यह भी प्रयास शुरू कर रहे हैं कि रूकी हुई अर्थव्यवस्था को लाकडाउन के बाद कैसे गति प्रदान की जाय। संभावित विकल्पों में चीन से भारत की ओर आने वाली विनिर्माण कम्पनियों को प्रोत्साहित करने तथा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए चर्चा की गई और भारत में अमेरिकी मूल की कंपनियों को प्रदेश में कैसे सर्वाधिक निवेश के लिए लाया जा सके।

डा. ललित भसीन संस्थापक एसईपीसी तथा प्रेसीडेन्ट इंडो अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स नार्थ इंडिया काउंसिल ने भाषण से सेमिनार की शुरूआत की। श्री भसीन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इण्डस्ट्री को इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों, अमेरिकी मूल की कंपनियों को आमंत्रित किये जाने हेतु संशोधित नीति बनाये जाने की प्रशंसा की।

इसे पहले आलोक कुमार, आईआईडीडी सार्वजनिक उद्यम, महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, प्रमुख सचिवए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने प्रदेश सरकार की ओर से एक प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया जिसमें यूपी में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया और उत्तर प्रदेश को भारत के उभरते आर्थिक पावर हाउस के बारे में बात की।

सेमिनार को नीलू खत्री प्रबंध निदेशक ब्लू ऑरेंज सिनर्जीज, तबरेज अहमद समूह निदेशक डेल टेक्नोलॉजीज और मनोज व्यास हेड रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट एनर्जी ने सम्बोधित किया। अंत में सत्र का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुकेश सिंह, चेयरमैन लखनऊ चैप्टर इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एनआईसी के प्रेसीडेंट ललित भसीन के नेतृत्व में चैंबर प्रदेश सरकार को अमेरिकी मूल की कंपनियों को प्रदेश में लाने के लिए पूरी तरीके से अपना सहयोग देगी।

ममता व प्रियंका कोरोना पर बंद करें राजनीतिक नाटक : चौहान

भाषा। नई दिल्ली

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोविड-19 को लेकर राजनीतिक नाटक नहीं करने की सलाह देते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें ऐसा करने के बजाए वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एकजुट ताकत के रूप में भारत की टीम का हिस्सा बनना चाहिए। चौहान ने एक साक्षात्कार में कहा, इन लोगों (विपक्षी दल) को हर बात के लिए केवल केंद्र पर दोष लगाना होता है। उन्हें सिर्फ नाटक करना है। कम से कम कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जैसी स्थितियों में तो कोई राजनीतिक नाटक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रियंका पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रवासियों के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन को बसों की पेशकश कर नाटक किया।

कांग्रेस और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच उस समय राजनीतिक जंग शुरू हो गई थी, जब प्रियंका ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया था कि उनकी पार्टी ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए 1,000 बसों का प्रबंध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि जिन 1,000 बसों की सूची सौंपी गई है, उनके पंजीकरण नंबर ऑटोरिक्शा, कार और ट्रकों के हैं।

चौहान ने कहा कि ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों को लेकर कथित रूप से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार इस देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी कर रही है। मेरे राज्य को भी परामर्श मिले हैं, लेकिन वे (ममता और प्रियंका) केवल नाटक करना चाहती हैं। चौहान ने कहा, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ही भारत की टीम का हिस्सा नहीं है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल इस टीम का हिस्सा है। उन्हें (विपक्षी दलों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों) स्वयं को इस टीम का हिस्सा समझना चाहिए और कोरोना वारयस से लड़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संघीय ढांचे का सदा सम्मान किया है, लेकिन इससे विपक्षी दलों को समस्या होती है। चौहान ने कहा, हम जब कभी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, वह हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। क्या आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है? केवल मैं ही नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री यदि उन्हें फोन करता है, तो वह उनके फोन का तत्काल जवाब देते हैं। वह हमेशा हमसे बात करते हैं, चीजों पर चर्चा करते हैं और हमें सुझाव देते हैं।

ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 शवों से भी फैलता है : अदालत

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई नगर निकाय के पास कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के शवों का निस्तारण करने के लिए किसी भी कब्रिस्तान को नामित करने का अधिकार है और ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ जो यह दिखाता हो कि कोरोना वायरस मुर्दों से भी फैलता है। याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें बीएमसी द्वारा जारी नौ अप्रैल के परिपत्र को चुनौती दी गई थी। वायरस के कारण मरने वाले लोगों के शवों के निस्तारण के लिए 20 कब्रिस्तानों को चिह्नित किया था। बीएमसी द्वारा जारी किया गया परिपत्र कानून के अनुरूप है और नगर निकाय के पास ऐसे मरीजों के शवों के निस्तारण के लिए कब्रिस्तानों को चिह्नित करने का पूरा अधिकार है। नगर निकाय और अन्य संबंधित प्राधिकरण कोविड-19 के मरीजों के शवों का सुरक्षित निस्तारण करने के लिए भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।

भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन के दौरान मणिपुर के प्रवासी अपने मूल स्थान जाने की प्रतीक्षा करते हुए।

भाजपा ने किया सरकार विरोधी प्रदर्शन, राकांपा का पलटवार

मुंबई। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की नाकामी के खिलाफ विपक्षी दल के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का शुक्रवार को नेतृत्व किया। फडणवीस ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विनोद तावड़े और मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के साथ मिलकर नरीमन प्वाइंट पर पार्टी की राज्य इकाई के मुख्यालय में काले मास्क पहनकर, काले फीते बांधकर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किए।

भाजपा के एक अन्य नेता आशीष शेलार ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के एक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है वे कोरोना वारयस को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बीच सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों के बाहर खड़े होकर सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र बचाओ प्रदर्शन में हिस्सा लें।

भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यालयों के बाहर एकत्र होकर एक घंटे विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दोपहर में समाप्त हुआ। कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा ने भाजपा पर सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। राज्य कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि जब चिकित्सक, नर्सें, पुलिस और प्रशासन कोरोना वायरस नामक शत्रु से लड़ रहे हैं, तब ऐसे समय में भाजपा राजनीति के बारे में कैसे सोच सकती है? शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि भाजपा का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उसे ही भारी पड़ेगा। राकांपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्रद्रोहीभाजपा हैशटैग चलाकर विपक्षी दल का विरोध किया और सवाल किया कि क्या वह कोविड-19 योद्धाओं का अपमान कर रही है और महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात कर रही है?

महामारी के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शन भाजपा पर ही भारी पड़ेगा: शिवसेना

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन पार्टी पर ही उल्टा पड़ेगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के महामारी से निपटने के तरीके की तुलना केरल के मॉडल से करने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की आलोचना की। संपादकीय में कहा गया है, ऐसा लगता है कि पाटिल ने केरल मॉडल का अध्ययन नहीं किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंस में भाग लेना समय की बर्बादी है। मराठी दैनिक अखबार ने भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में प्रदर्शन करने के बजाय पाटिल और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को केरल में प्रदर्शन करना चाहिए। उसने सवाल किया, अगर विपक्ष को राज्य की चिंता है और उसके पास महामारी से लड़ने के लिए कोई सुझाव है तो उन्हें मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या विपक्षी दल को ऐसा करने में शर्म है या वह अपना आत्म विश्वास खो चुका है। संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य में हर दिन भले ही कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादातर मरीज संक्रमण से स्वस्थ भी हो रहे हैं।

कोविड-19 : कर्फ्यू में शादी की सालगिरह की पार्टी करने के आरोप में अधिकारी निलंबित

भाषा। इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लागू कर्फ्यू के दौरान बिना अनुमति के अपनी शादी की सालगिरह की कथित पार्टी मनाना एक सरकारी अधिकारी को महंगा पड़ा है। पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद इस अधिकारी को सरकारी सेवा के नियम-कायदों और सामाजिक दूरी बनाने की हिदायतों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आईएमसी आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस मामले में अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए निगम के जोनल अधिकारी चेतन पाटिल को निलंबित कर दिया है।

अधिकारी ने बताया कि आईएमसी प्रशासन तक एक वीडियो पहुंचने के बाद इस आरोप का संज्ञान लिया गया है कि पाटिल ने कर्फ्यू के दौरान विजय नगर क्षेत्र के एक सभागृह में अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी आयोजित की जबकि इस आयोजन के लिए उन्हें कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस पार्टी में सामाजिक दूरी की हिदायतों का भी कथित तौर पर उल्लंघन किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में आईएमसी आयुक्त द्वारा जोनल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इसका संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय ट्रेंचिंग ग्राउंड रहेगा।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दावा किया गया है कि पाटिल की शादी की सालगिरह के मौके पर पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें शामिल लोग कराओके (संगीत की धुन के साथ गीत गाना) सिस्टम पर गाते, नाचते और ताली बजाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्टी में शामिल कुछ मेहमानों ने मास्क पहन रखे हैं, जबकि कुछ लोग कोविड-19 से बचाव के इस जरूरी उपाय को अपनाए बगैर ही महफिल का मजा ले रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रशासन ने इंदौर की शहरी सीमा में 25 मार्च से कर्फ्यू लगा रखा है। इंदौर जिले में इस महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,850 पर पहुंच गई है। इनमें से 109 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 1,280 लोग महामारी से स्वस्थ चुके हैं।

कर्नाटक सरकार 31 मई तक श्रमिक ट्रेनों का खर्च उठाएगी

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह 31 मई तक श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों की संबंधित राज्यों की यात्रा का खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा ने ट्वीट किया कि सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों की याचिका पर विचार किया है जो अपने घर जाने के लिए यात्रा का खर्च उठाने मे सक्षम नही है। सरकार देश के दूर-दराज के इलाकों से यहां आने वाले प्रवासी मजदूरों को अपना ही मानती है और मेरा पुरजोर विश्वास है कि राज्य को उनकी भी मदद करनी चाहिए। श्रमिक ट्रेनों का परिचालन रेलवे और राज्य सरकारों के बीच किराया 85:15 के अनुपात मे वहन करने के साथ किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए के अपने हिस्से को देने से इनकार कर दिया है जिसके कारण श्रमिकों को यात्रा का भुगतान करना पड़ा है।

अधिकत्तर लोगों ने अलविदा की नमाज घर में ही की

श्रीनगर। कश्मीर मे सरकारी आदेश के मुताबिक शुक्रवार को अधिकत्तर लोगों ने अलविदा जुमा (रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार) की नमाज अपने-अपने घर के अंदर ही अदा की जबकि घाटी के कुछ अंदरूनी हिस्सो की मस्जिदो मे जमात के साथ नमाज अदा की गई। श्रीनगर के निचले इलाके मे स्थित जामिया मस्जिद मे हर साल करीब एक लाख लोग नमाज के लिए एकत्र होते थे लेकिन इस अलविदा जुमा को यह बिल्कुल सुनसान दिखाई दी। कोरोना के रोकथाम के मद्देनजर सरकार ने धार्मिक स्थलो पर भीड़ एकत्र करने से रोक लगाई हुई है। हजरतबल समेत किसी भी बड़ी मस्जिद मे अलविदा जुमा की नमाज अदा नही की गई। मुख्य सड़कों पर मौजूद सभी मस्जिदें बंद रही।

पुलवामा से आतंकवादियों के दो समर्थक गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले मे प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन और अंसार गज़वात-उल-हिंद के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान त्राल निवासी एस अहमद शाह और अवंतीपुरा के तनसीम उर्फ तनवीर अहमद शेख के तौर पर हुई है। हिज्बुल मुजाहिदीन और अंसार गज़वात-उल-हिंद के दो सदस्यों को पुलवामा के त्राल और अवंतीपुरा से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उन पर आतंकवादियों को पनाह देने और अन्य मदद करने का आरोप है। इसके अलावा उनको संवेदनशील जानकारी भी देने का आरोप है।

कोरोना को रोकने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए: खांडू

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को प्रदेश मे कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पूरा प्रयास करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त है और राज्य के लोहित जिले मे मिला एकमात्र कोविड-19 मरीज को भी 17 अप्रैल को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अपने गृह जिले तवांग मे कोविड-19 को लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हुए खांडू ने कहा कि देश मे बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठक के दौरान खांडू ने कहा, इस स्तर की तैयारियां प्रदेश मे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से शत प्रतिशत रोकने के लिए होनी चाहिए। अगर संक्रमण को नियंत्रित नही किया गया तो राज्य सरकार की नाकामी होगी।

नवजात जुड़वा भाई-बहन कोरोना वायरस से संक्रमित

मेहसाणा (गुजरात)। गुजरात के मेहसाणा मे नवजात जुड़वां भाई-बहन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ ही दोनो शिशु राज्य मे सबसे कम उम्र के कोविड-19 मरीज बन गए है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दोनो बच्चों का जन्म 16 मई को वडनगर के सदर अस्पताल मे हुआ। जिला विकास अधिकारी मनोज दक्षिणी ने बताया कि इन बच्चों की मां भी कोरोना वायरस से संक्रमित है और संक्रमण के दौरान ही दोनो का जन्म हुआ है। गुजरात मे यह पहला मामला है जहां नवजात, वे भी जुड़वां, मे कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। भाई-बहन मे भाई की रिपोर्ट 18 मई को आई जबकि बहन की रिपोर्ट शुक्रवार को आई। बच्चों की हालत स्थिर है। दक्षिणी ने बताया कि महिला जिस गांव की रहने वाली है, वहां कोविड-19 के कई मामले आए है। वहां मुंबई से लौटे तीन लोगों मे संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कई मामले सामने आए। मेहसाणा जिले मे अभी तक कम से कम 93 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

वीपी दुरईसामी भाजपा में हुए शामिल

चेन्नई। द्रविड़ नेता एवं तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर पी. दुरईसामी शुक्रवार को भाजपा मे शामिल हो गए। उन्हें बृहस्पतिवार को द्रमुक के उप महासचिव पद से हटा दिया गया था। दुरईसामी कमलालयम स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय मे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरूगन और वरिष्ठ नेता एल गणेशन की मौजूदगी मे भारतीय जनता पार्टी मे शामिल हुए। भारत के भाजपा के हाथों मे सुरक्षित होने का संकेत देते हुए उन्होंने कहा, यदि आप भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करते है तो आप देश की रक्षा कर सकते हैं। द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टालिन ने दुरईसामी को बृहस्पतिवार को पार्टी के उप महासचिव पद से हटा दिया था। इसके कुछ ही दिन पहले दुरईसामी ने एक शिष्टाचार भेंट के तहत मुरूगन से मुलाकात की थी।

कोलकाता में अम्फान तूफान में उखड़े पेड़ के बाद राहत कार्य में जुटे स्थानीय लोग।

जेपी नड्डा ने आरबीआई की घोषणाओं का किया स्वागत

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ब्याज दरों में कटौती, कर्ज अदायगी पर ऋण स्थगन को बढ़ाने और अधिक कर्ज देने के लिए बैंकों को इजाजत देने के फैसले का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि इन घोषणाओं से कोविड-19 महामारी के दौरान और बाद में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को मदद मिलेगी। नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, आरबीआई के गर्वनर की आज की घोषणाएं प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप है जो कारोबार और लोकोन्मुखी है। इन घोषणाओं से कोविड-19 महामारी के दौरान और बाद में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को काफी मदद मिलेगी। एक्जिम बैंक को 90 दिनों के लिए 15000 हजार करोड़ रूपए की कर्ज सुविधा देने और अधिक कर्ज देने के लिए बैंकों को इजाजत देने के आरबीआई के प्रभावी कदमों से कोविड-19 के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभावों के बावजूद अर्थव्यवस्था को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई प्रशंसा का हकदार है। कई सकारात्मक समाचार हैं, जैसे 2020-21 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 9.2 अरब डालर की वृद्धि हुई है। तीसरी और चौथी तिमाही में मुद्रा स्फीति की दर आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से भी नीचे रहने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कोविड-19 संकट के प्रभाव को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती, कर्ज अदायगी पर स्थगन को बढ़ाने और कॉरपोरेट को अधिक कर्ज देने के लिए बैंकों को इजाजत देने का फैसला किया। आरबीआई ने प्रमुख उधारी दर को 0.40 प्रतिशत घटा दिया। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अचानक हुई बैठक में रेपो दर में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस कटौती के बाद रेपो दर घटकर चार प्रतिशत हो गई है।

रिजर्व बैंक के फैसलों से मिल रहे भयानक मंदी के संकेत: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कमी किए जाने, विकास दर के नकारात्मक रहने का अनुमान लगाए जाने और कर्ज पर ब्याज के भुगतान में मोहलत तीन महीने बढ़ााए जाने के फैसलों से देश में भयानक मंदी के संकेत मिलते हैं। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक बयान में कहा, रेपो दर में कमी का फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि कर्ज की मांग नहीं है। हां, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सस्ता कर्ज लेने का फायदा हो सकता है। हमारे ऊपर इसका बड़ा दुष्प्रभाव रहेगा कि एफडी और बचत खाते पर ब्याज कम हो जाएगा। उन्होंने कहा, रिजर्व बैंक ने पहली बार यह माना कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर नकारात्मक रहेगी। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने कहा था कि भारत की विकास दर -5 प्रतिशत तक गिर सकती है। इसका मतलब यह कि देश में भयानक मंदी के संकेत हैं।

वल्लभ के मुताबिक कर्ज पर ब्याज के भुगतान में मोहलत को तीन महीने बढ़ा दिया गया। इससे सरकार कथनी और करनी में एक विरोधाभास साबित होता है। एक तरफ तो सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से कर्ज की खुराक दे रही है। दूसरी तरफ, इस कदम से यह संदेश दे रही है कि कर्ज की मांग नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कोविड-19 संकट के प्रभाव को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती, कर्ज अदायगी पर ऋण स्थगन को बढ़ाने और कॉरपोरेट को अधिक कर्ज देने के लिए बैंकों को इजाजत देने का फैसला किया। आरबीआई ने प्रमुख उधारी दर को 0.40 प्रतिशत घटा दिया। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अचानक हुई बैठक में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस कटौती के बाद रेपो दर घटकर चार प्रतिशत हो गई है।

चारों धाम के गर्भगृह को छोड़ बाकी मंदिरों के होंगे ऑनलाइन दर्शन

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड से कहा कि चारों हिमालई धामों के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यहां चारधाम देवस्थानम प्रबंध बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि विश्वभर में उत्तराखण्ड अध्यात्म का केन्द्र है और यहां के मन्दिरों की प्राचीन शैली इसकी विशिष्टता है जिसे बनाए रखना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग मन्दिरों के ऑनलाइन दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें गर्भगृह को छोड़कर मन्दिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन एवं ऑडियो के माध्यम से पूजा-अर्चना करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें धार्मिक मान्यताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए। गढवाल हिमालय के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं लेकिन कोविड-19 के कारण अभी तीर्थयात्रियों को उनके दर्शन के लिए आने की अनुमति नहीं है।

कोविड-19 के मददेनजर चारधाम यात्रा का सुचारू ढंग से चलाने तथा मंदिरों से जुड़ी प्रमुख पाण्डुलिपियों एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व के सामग्री संग्रहण के लिए संग्रहालय बनाने पर भी चर्चा की गई। रावत ने कहा कि कुछ अन्य मंदिर समितियों ने भी देवस्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है जिसके बारे में विचार कर भविष्य में कुछ अन्य मंदिरों को भी इससे जोड़ा जा सकता है। बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के समुचित संचालन के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने तथा बोर्ड का एक अलग लोगो बनाने का भी निर्णय लिया।

मन्दिरों की सम्पत्ति, निधि, बहुमूल्य वस्तुओं को बोर्ड के प्रबंधन में लाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया इसके अलावा यह भी फैसला किया गया कि बोर्ड का अलग बैंक खाता होगा जिसके लिए बैठक में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी गई। बद्री-केदार मंदिर समिति की अवशेष धनराशि भी उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में स्थानांतरित की जाएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न न्यायिक मामलों के लिए न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष सतपाल महाराज, बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भटट, गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अगरतला में एनजीओ वालंटियर्स विभिन्न प्रकार की ड्रेस पहनकर लोगों को मास्क वितरित कर जागरूक करते हुए।

विपक्ष चाहता है कि कोविड-19 पर पीएम सभी पार्टियों से बातचीत करें: पवार

भाषा। मुंबई

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि प्रधानमंत्री कोरोना वायरस महामारी से निपटने के उपायों के बारे में सभी पार्टियों के साथ बातचीत करें और संसदीय स्थाई समतियों का भी कामकाज बहाल करें।

पवार ने 22 विपक्षी दलों के नेताओं की वीडियो कांफ्रेंस के बाद सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि उनका (विपक्षी दलों का) मानना है कि यह दिखावा करने का, या खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का वक्त नहीं है। पवार ने कहा, हमने एक व्यवस्थित तरीके से सभी राजनीतिक दलों से फौरन ही संपर्क करने और बातचीत करने का, हमारे सुझावों को गंभीरता से सुनने...(कोविड-19) संकट का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं करने, स्थाई समिति जैसी संस्थाओं का कामकाज बहाल करने और राज्यों की वित्तीय एवं अन्य रूप से मदद करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अपील करने का फैसला किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख ने कहा, समान विचारधारा वाले दल केंद्र सरकार से 10 सूत्री मांगों को फौरन लागू करने की सामूहिक रूप से मांग करने जा रहे हैं। बैठक में, उन्होंने आयात, निर्यात एवं अंतर्देशीय जल परिवहन बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की अपील की। उन्होंने कहा, राज्यों में नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियां अपनाई जानी चाहिए। आयात, निर्यात एवं अंतर्देशीय जल परिवहन बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों, उद्यमियों तथा विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के नियमों में छूट दे रही हैं, लेकिन फैक्टरियां आसानी से उत्पादन बहाल नहीं कर सकती क्योंकि कामगार अपने घर लौट गए हैं। उन्होंने इन कामगारों को वापस लाने के लिए एक रणनीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने परिवहन सेवाओं को बाधित कर दिया है और राज्यों के अंदर क्रमिक रूप से सड़क परिवहन बहाल कने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चलते अगले अकादमिक वर्ष में छात्रों की संख्या घटेगी। वित्तीय नुकसान के चलते कुछ शैक्षणिक संस्थानों के बंद हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा, समय रहते उपाय करने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए।

लॉकडाउनः अदालत ने पेरोल बढ़ाने की अरुण गवली की याचिक खारिज की

भाषा। नागपुर

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने सजायाफ्ता गैंगस्टर अरुण गवली की पेरोल बढ़ाने संबंधी याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उसे तालुजा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

गवली, 2008 के हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है और नागपुर केंद्रीय कारागर में बंद था। उसे अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 13 मार्च को पेरोल दी गई थी और उसे 27 अप्रैल को आत्मसमर्पण करना था। हालांकि, कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते पेरोल पर मिली छुट्टी को सात दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। आठ मई को, यह अवधि सात और दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। गवली ने फिर 31 मई तक इसे बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उसके वकील, मीर नगमां अली ने तर्क दिया कि लॉकडाउन के चलते और मुंबई के रेड जोन घोषित होने की वजह से गवली आत्मसमर्पण के लिए मुंबई से नागपुर सफर करने में सक्षम नहीं है।

इस याचिका का अतिरिक्त लोक अभियोजक ए एम बालपंदे ने विरोध किया जिसने अदालत को बताया कि गवली को मुंबई के अपने घर से नवी मुंबई के तालोजा जेल तक सफर की अनुमति दी जा सकती है जहां वह आत्मसमर्पण कर सके और जहां उसे अगले आदेश तक कैद में रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंड पीठ ने गौर किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करे और पेरोल की अवधि बढ़ाए खासकर तब तब राज्य सरकार ने याचिका का जबर्दस्त विरोध किया है।

जिज्ञासा से हुआ भारतीय ज्ञान पद्धति का विकास: प्रो. चंदन

● शिक्षा केंद्रों में तकनीकी की उपस्थिति ने अनुशासन व्यवस्था कायम की

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली/प्रयागराज

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, प्रयाग जिला द्वारा 'कोरोना संकट और शिक्षा का नवाचार' विषय पर आयोजित वेबिनार व्याख्यान में प्रो. चन्दन कुमार ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय गुरुकुल पद्धति के साथ-साथ हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति भी परंपरा से मिली। औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था ने हमारी प्रश्नानुकूलता की प्रवृत्ति का क्षय किया। प्रश्नानुकूलता और जिज्ञासा ही भारतीय मनीषा के विकास का कारण रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने ज्ञान की जागतिक भूमिका तैयार की। लुटेरों और आक्रांताओं ने अपनी पांथिक मान्यताओं के चलते इस भूमिका को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने हमारे ज्ञान केंद्रों को नष्ट किया। विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय मस्तिष्क पर शासन करने के लिए हमारी तर्क एवं ज्ञान पद्धति को क्षीण करने की पूरी कोशिश की। प्रो. चन्दन ने कहा कि गुरु, वैद्य और पुरोहितों को निशाने पर रखते हुए औपनिवेशिक ताकतों ने हमें हमारी ज्ञान परंपरा से विरत से किया। औपनिवेशिक खतरे को भांपते हुए उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के अनेक भारतीय नायकों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना भारतीय प्रतिश्रुति के निर्माण के लिए किया। लेकिन दुर्भाग्य से मार्क्सवादी शिक्षण पद्धतियों के चलते आज भी भारतीय मनीषा की फॉल्ट लाइन्स को पढ़ा जा रहा है। आज कोरोना ने अपनी सामाजिक वास्तविकता से शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी को केंद्र में लाने और उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए मजबूर कर दिया है। शिक्षा केंद्रों में तकनीकी की उपस्थिति ने अनुशासन व्यवस्था कायम की है। उन्होंने आगे कहा कि अब सूचनाएं ज्ञान नहीं हैं बल्कि व्याख्याएं ज्ञान हैं। कोरोना ने इसकी सुनिश्चितता तय की है। नोआ हरारी की पुस्तक 'इक्कीसवीं सदी के इक्कीस सबक' की चर्चा करते हुए उन्होंने सूचना और ताकत की तार्किक व्याख्या की। आज कोरोना ने वामपंथी शब्दावलियों को अप्रासंगिक कर दिया है। आज तकनीकी अपना दायरा बढ़ाती जा रही है।

शीर्ष न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में कैट स्थापित करने की याचिका पर केंद्र व अन्य से जवाब मांगा

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की एक स्थाई पीठ स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और प्रदेश के प्रशासन से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और गृह मंत्रालय सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। याचिका के जरिए 29 अप्रैल की एक अधिसूचना भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़े विवाद की सुनवाई चंडीगढ़ स्थित कैट करेगा। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में पीठ ने केंद्र और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया।

क्या निजी पक्ष द्वारा अधिनियमों का प्रकाशन सरकार के कापीराइट का अतिक्रमण है?: न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से जानना चाहा कि क्या किसी निजी पक्ष द्वारा किसी कानून का शब्दश: प्रकाशन सरकार के कापीराइट का हनन है? प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र को नोटिस जारी किया।

पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसा करने वाले प्रकाशकों के खिलाफ सरकार कापीराइट कानून और संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन होने की स्थिति में कार्वाई करेगी। याचिकाकर्ता अर्पित भार्गव ने अपील में दावा किया है कि उच्च न्यायालय ने सरकार की इस घोर लापरवाही की ओर ध्यान नहीं दिया कि वह स्वयं ही इन अधिनियमों का प्रकाशन नहीं करके संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) में प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर अमल नहीं कर रही है। अपील के अनुसार सरकार स्वत: ही केन्द्रीय कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं, विनियमन आदि का प्रमाणित और सही संस्करण उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं करा रही है।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस अपील में आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि ऊंची कीमतों पर इसकी उपलब्धता की वजह से ही नहीं बल्कि कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं और विनियमनों के गैर प्रमाणित पुन:प्रकाशन से जनता को नुकसान होता है।अपील में कहा गया है कि संबंधित सरकारी विभाग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से संबंधित जानकारी के प्रकाशन के बारे में कोई नीति या दिशानिर्देश बनाने में विफल रहा है।

कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले 21-28 जून के बीच आएंगे : अध्ययन

भाषा। कोलकाता

शोधकर्ताओं की एक टीम के अध्ययन में कहा गया है कि 21 से 28 जून के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के हर दिन सर्वाधिक करीब 7,000-7,500 मामले सामने आने की आशंका है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि जून के अंत तक कोविड-19 के मामलों में इजाफा होते रहेगा। शोध में शामिल यादवपुर विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर नंदादुलाल बैरागी ने बताया, जुलाई के दूसरे सप्ताह से संक्रमण के मामले हर दिन घटने लगेंगे। संक्रमण रोकने के उपायों, जांच बढ़ाने से अक्टूबर तक मामले कम हो जाने का अनुमान है। यादवपुर विश्वविद्यालय में गणितीय जीवविज्ञान और पारिस्थितिकी (बीएमबीई) केंद्र के प्रोफेसर और संयोजक बैरागी और पांच अन्य अध्ययनकर्ताओं ने यह शोध किया है। भारत सरकार के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा मंजूर गणितीय प्रारूप पर अध्ययन में कोविड-19 के मामले से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

ठाणे में पेपर बैग बनाते समतोल फाउंडेशन द्वारा पुनर्वासित किए गए जा रहे बच्चें जो कोविड-19 लॉकडाउन से पहले सड़कों और रेलवे स्टेशन पर रहते थे।

पेज एक का शेष

पहली दफा...

गई। कुछ प्रदेशों में श्रम कानूनों में किए गए हालिया बदलावों को लेकर भी चर्चा हुई। सोनिया के मुताबिक, हममें से कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी हैं कि गरीबों के खातों में पैसे डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए। हमने यह मांग भी की थी कि कर्मचारियों एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए 'वेतन सहायता कोष' बनाया जाए। लेकिन हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया।

कराची के...

अखबार की खबर में कहा गया कि अभी हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मारे गए सभी लोग विमान में सवार यात्री थे या उस रिहायशी इलाके के लोग थे जहां यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सिंध की स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अजरा पेचुहो ने कहा कि हादसे में तीन लोग बचे हैं। बैंक ऑफ पंजाब के अध्यक्ष जफर मसूद इस हादसे में बच गए। उन्होंने अपनी मां को फोन कर अपने कुशल होने की जानकारी दी। ईधी कल्याण ट्रस्ट के प्रवक्ता साद ईधी ने कहा कि ऐसे 25-30 रहवासियों को भी अस्पताल ले जाया गया है जिनके घरों को इस विमान हादसे में नुकसान पहुंचा है। उनमें से अधिकतर जलने से झुलस गए थे। मंत्री ने कहा, पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। मुख्य बाधा संकरी गलियां और आम लोगों की भारी मौजदगी थी जो वहां दुर्घटना के बाद इकट्ठा हो गए थे। उन्हें हटा दिया गया। पीआईए के अधिकारियों के मुताबिक, कैप्टन ने हवाई यातायात टावर को सूचित किया कि उसे विमान के लैंडिंग गियर में कुछ गड़बड़ी लग रही है और इसके बाद विमान रडार से गायब हो गया।राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने विमान हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची में पीआईए के यात्री विमान हादसे में लोगों की जान जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इस मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हादसे में लोगों की जान जाने पर अफसोस जताते हुए सेना को राहत व बचाव कार्य में नागरिक प्रशासन की हरसंभव मदद का निर्देश दिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विमान हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। यह विमान लाहौर से कराची आ रहा था और नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) ने पिछले शनिवार को कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद सीमित संख्या में उड़ानों के संचालन की इजाजत दी थी। टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है कि जिस जगह यह दुर्घटना हुई वहां कुछ घरों और कारों को नुकसान पहुंचा है। बचावकर्मी व पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बर्बाद हुए घरों से अब तक कम से कम चार शव मिल चुके हैं जबकि कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।विमान में यात्रियों की सटीक संख्या को लेकर हालांकि विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। वरिष्ठ संयुक्त सचिव, विमानन, सत्तार खोखर ने पाकिस्तान टीवी को बताया कि विमान में 99 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य थे लेकिन पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने कहा कि विमान में 91 यात्री और चालक दल के सात सदस्य थे। हफीज ने कहा कि विमान का स्थानीय समय के मुताबिक अपराह्न दो बजकर 37 मिनट पर हवाईअड्डे से संपर्क टूट गया था और अभी विमान में आई किसी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगा।

मोदी ने...

107 लोग सवार थे। मोदी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में विमान हादसे में लोगों के मारे जाने की खबर से आहत हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

मोदी ने...

होने के बाद जलमग्न हो गए। यहां तेज हवाओं के चलते घर तबाह हो गए, विशाल पेड़ उखड़ गए और बिजली गुल हो गई। धनखड़ और बनर्जी के साथ हवाई सर्वेक्षण करने और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की अंतिरम राहत की घोषणा की। यहां चक्रवात के कारण अब तक 80 लोगों की जान चली गई। हालांकि, बनर्जी ने कहा कि चक्रवात के कारण हुआ नुकसान राष्ट्रीय आपदा से बहुत बड़ा है और कहा कि राज्य को एक लाख करोड़ रुपए से कम का नुकसान नहीं हुआ है। मोदी ने प्रत्एक मृतक के परिवार को दो लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। बाद में प्रधानमंत्री ओडिशा पहुंचे जहां उन्होंने राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद दीर्घकालिक पुनर्वास उपायों के लिए आगे की सहायता दी जाएगी। इन नेताओं ने करीब डेढ़ घंटे तक जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों का हवाई सर्वे किया। यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परिसर में हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी भी उपस्थित थे। मोदी ने चक्रवात के कारण हुई तबाही से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार और ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) शासन की सराहना की। कोलकाता का बड़ा हिस्सा अब भी अंधकारमय है जहां मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बार-बार प्रभावित हो रही हैं। चक्रवात के कारण उत्पन्न अशांति ने दोनों राज्यों के लिए चिंता बढ़ा दी है जहां कोरोना वायरस महामारी अपने पैर तेजी से पसार रही है। लाखों प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के कारण संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत है जबकि चक्रवात से लड़ने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की। उन्होंने इस बात को माना कि चक्रवात के बाद राहत शिविरों में लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने के सरकार के प्रयासों को विफल कर सकती है।

दिल्ली में...

534 और मंगलवार को 500 मामले सामने आए थे। केस बढ़ने के साथ दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन पर काबू किया था। एक बार कंटेनमेंट जोन की संख्या 90 से ऊपर पहुंच गई थी लेकिन धीरे-धीरे घटकर यह 70 के आसपास आ गई। अब षुक्रवार को फिर इस सूची में बढ़ोतरी होकर कंटेनमेंट जोन की संख्या 79 हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक 50 वर्षीय सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) की कोरोना से मौत हो गई। जम्मू में सीआरपीएफकी 84 वीं बटालियन में तैनात एएसआई पंचदेव राम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वह बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे और लिवर कैंसर से पीड़ित थे। उनका परिवार लखनऊ में रहता है। **भीषण गर्मी में भी बढ़ रहे केस:** दो महीने पहले कोरोना वायरस के फैलने के साथ ऐसी चर्चाएं आम थीं कि कोरोना वायरस गर्मी से मर जाएगा या इसका असर कम होगा, लेकिन सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। राजधानी का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और बीते चार दिन से तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। लेकिन लगातार चौथे दिन गुरुवार को 500 से ज्यादा केस मिले और शुक्रवार को यह आंकड़ा 600 के भी पार हो गया जबकि गुरुवार को सीजन का सबसे गर्म दिन था।

कोरोना के...

चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 21 मई तक कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ राज्यों और शहरों/जिलों में केंद्रित हो चुका है। डॉ वीके पॉल ने बताया कि पांच राज्यों में लगभग 80 प्रतिषत केस और पांच शहरों में 60 प्रतिषत से अधिक, 10 राज्यों में 90 प्रतिषत से अधिक और 10 शहरों में 70 प्रतिषत से अधिक मामले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में शुक्रवार को 2940 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 44,582 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से राज्य में 63 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ यहां मरने वालों का आंकड़ा 1517 हो गया। सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुम्बई में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1751 नए मामले सामने आए जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात में अभी तक 12,910 केस आए हैं और यहां 773 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 13,967 कोरोना मामले मिले और यहां 94 लोगों की जान गई। राजधानी दिल्ली में 12319 केस षुक्रवार तक आए जबकि 208 लोगों की मौत हुई। इसी तरह मध्य प्रदेष में 5,981 केस दर्ज किए गए और 270 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा राजस्थान में 6,227 मरीज मिल चुके हैं और इनमें से 157 की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,18,447 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,088 नए मामले सामने आए हैं और 148 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 48,534 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफ्ल भी हुए हैं. रिकवरी रेट सुधरकर 40.97 प्रतिशत पर पहुंच गया है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक सवा तीन लाख से ज्यादा जानें ले चुका है और 50 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है।

क्वॉरंटीन सुविधाएं...

व्यवस्था की मांग की है। उनका मानना है कि कोरोना वायरस दो से 14 दिनों के भीतर अपना प्रभाव दिखा सकता है। कई मामलों में पीपीपी किट पहनने के बावजूद गैर लक्षण वाले स्वास्थ्य पेषेवर बाद में कोरोनो वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए अस्पताल में ड्यूटी के बाद कर्मचारियों को क्वॉरंटीन केंद्र में रखा जाना चाहिए और उनका कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। भले ही उनमें लक्षण दिखाई न दें। यदि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाता है तो इससे न केवल डॉक्टरों, बल्कि उनके परिवारों, रोगियों और सामुदायिक संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के संघ के अध्यक्ष डॉ. सुनील धुचानिया ने कहा कि इन्हीं वजहों से हम नए जारी दिषानिर्देषों में संषोधन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि कोरोना ड्यूटी करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य पेषेवर अब और होटल की सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। यह सुविधा वापस ले ली गई है। यहां रहने वालों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने कमरों को तुरंत खाली कर दें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कमरे का किराया उनके वेतन से काट लिया जाएगा। आरएमएल अस्पताल में आरडीए की अध्यक्ष डॉ. एकता यादव ने हालांकि कहा कि वे उम्मीद कर रही हैं कि अगली पाली समाप्त होने तक स्वास्थ्य मंत्रालय अपने नए दिशानिर्देशों को वापस ले लेगा। सफ्दरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने कोविद-19 वार्डों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए पांच-दिवसीय क्वॉरंटीन की बात कही है, ताकि घर वापस जाने से पहले एक बार उनका कोरोना टेस्ट किया जा सके।

हर्षवर्धन ने...

है। कार्यकारी बोर्ड में भारत द्वारा नामित व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर 194 देशों के विश्व स्वास्थ्य निकाय ने मंगलवार को हस्ताक्षर किया। पिछले साल, डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया समूह ने कार्यकारी बोर्ड में तीन साल के लिए भारत के प्रतिनिधि का सर्वसम्मति से चुनाव करने का फैसला किया था। अध्यक्ष का पद क्षेत्रीय समूहों के पास एक वर्ष के लिए क्रमिक आधार पर रहता है। पिछले साल यह तय किया गया था कि शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए भारतीय उम्मीदवार कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि यह पूर्णकालिक कार्य नहीं है और मंत्री को कार्यकारी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करनी होगी।

आरबीआई ने...

जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि वित्त वर्ष 2020-21 में नकारात्मक रहेगी। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तय समय से पहले हुई बैठक में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। समिति की पिछली बैठक मार्च अंत में हुई थी। तब भी रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.75 प्रतिशत की बड़ी कटौती की थी। तब पहली बार कर्ज किस्त के भुगतान पर तीन माह (मार्च- मई 2020) की छूट दी गई थी जिसे अब तीन माह और बढ़ाकर अगस्त 2020 तक कर दिया है। इस बीच, आरबीआई द्वारा कर्ज किस्त के भुगतान पर छूट तीन महीने बढ़ाने की घोषणा से बैंकों का डूबा कर्ज बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में एक समय 450 अंक तक नीचे चला गया था। हालांकि, बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ। अंत में सेंसेक्स 260.31 अंक या 0.84 प्रतिशत के नुकसान से 30,672.59 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी भी 67 अंक या 0.74 प्रतिशत के नुकसान से 9,039.25 अंक पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स 425.14 अंक या 1.36 प्रतिशत तथा निफ्टी 97.6 अंक या 1.06 प्रतिशत नीचे आया है। आरबीआई ने निर्यात के लिए लदान से पहले और बाद में दिए जाने वाले कर्ज की समयसीमा को एक साल से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अपनी निवेश जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय दिया गया है। रेपो दर में 0.40 प्रतिशत कटौती के बाद यह घटकर चार प्रतिशत रह गई है, जबकि रिवर्स रेपो दर भी इतनी ही घटकर 3.35 प्रतिशत रह गई है। रेपो दर वर्ष 2000 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है और मुद्रास्फीति के अनुमान बेहद अनिश्चित हैं। उन्होंने कहा, "दो महीनों के लॉकडाउन से घरेलू आर्थिक गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष छह औद्योगिक राज्य, जिनका भारत के औद्योगिक उत्पादन में 60 प्रतिशत योगदान है, वे मोटे तौर पर लाल या नारंगी क्षेत्र में हैं। आर्थिक वृद्धि के अपने पहले आधिकारिक पूर्वानुमान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्त वर्ष 2020-21 में घट सकती है। कोरोना वायरस महामारी और इसके चलते लागू लॉकडाउन के कारण ऐसा होगा। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही थी और तब 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान था। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि मांग में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं और बिजली तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग घटी है। गवर्नर ने कहा कि सबसे अधिक झटका निजी खपत में लगा है, जिसकी घरेलू मांग में 60 फीसदी हिस्सेदारी है।

कुएं से...

प्राथमिक जांच का हवाला देते हुए कहा था कि यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि शवों पर चोट के कोई निशान नहीं हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही असली वजह की जानकारी मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि घर के प्रमुख ने अपने एक दोस्त को थैले बनाने वाली इकाई में यह कहते हुए बुलाया था कि कुछ ज्यादा काम आ गया है। वह किसी अन्य स्थान पर काम करता था। उन्होंने बताया कि फिलहाल आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है जिसे आगे जांच के अनुसार बदला जा सकता है। 48 वर्षीय व्यक्ति करीब 20 साल पहले पश्चिम बंगाल से यहां आया था और यहीं बस गया था।

दिल्ली में...

हाइपो क्लोराइड सोल्यूशन (क्लोरीन) है जिसका इस्तेमाल स्वीमिंग पूल आदि में भी किया जाता है। इसे डाइल्यूट (एक लीटर पानी में पांच एमएल) करने के बाद ही स्प्रे किया जाता है जिससे इंसान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। अलबत्ता छिड़काव के दौरान सोल्यूशन मिश्रित पानी की धार बहुत तेज होती है जिससे चेहरे या कहीं और चोट जरूर लग सकती है। डीएम साउथ ईस्ट हरलीन कौर से संपर्क नहीं हो सका। एसडीएमसी ने बयान जारी कर कहा कि श्रमिक ट्रेन के लिए पंजीकरण व स्क्रीनिंग कराने को प्रवासी मजदूर लाल साईं मार्केट के सामने लाजपतनगर थ्री स्थित हेमू कलानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जा रहे थे। यह स्कूल आवासीय कॉलोनी में है जिसके चलते वहां के निवासियों और उनके प्रतिनिधियों की तरफ से पूरी कॉलोनी परिसर, मैदानों और सड़कों को कीटनाशक मुक्त किए जाने की जबर्दस्त मांग की गई थी। इसके मद्देनजर प्रोटोकोल और दिशानिर्देशों के मुताबिक शुक्रवार की शाम को कीटनाशक का छिड़काव किया गया। घटना के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि स्पे कर रहे कर्मचारी कुछ समय के लिए जेटिंग मशीन का दबाव कम बनाए रखने से चूक गए थे। स्टाफ को भविष्य में ड्यूटी निभाते समय ज्यादा सावधान रहने का निर्देश दे दिया गया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जनता से माफी भी मांग ली है और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसडीएमसी की ओर से स्क्रीनिंग के लिए आए मजदूरों को भोजन-पानी भी मुहैया कराया गया।

हॉकी की वापसी सदस्य देशों की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर हॉकी प्रतियोगिता की वापसी पूरी तरह से स्थानीय परिस्थितियो पर निर्भर करेगी। एफआईएच ने कहा कि हॉकी में किसी भी तरह की प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा की वापसी से पहले संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाए जाने चाहिए। एफआईएच के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार सामान्य प्रतियोगिता वाली स्थिति मे लौटने के लिए इस बीमारी की टीके जरूरत होगी।

एआईटीए ने अभी अभ्यास शुरू नहीं करने का सुझाव दिया

नई दिल्ली। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ (एआईटीए) ने अपने अधीन आने वाले निकायो से युगल मुकाबलो के आयोजन से बचने के अलावा अकादमियों में अभ्यास शुरू नही करने का सुझाव दिया है। एआईटीए ने 14 पन्नो का मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को गुरुवार को राज्य संघो को सौपा। इसमे राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने प्रशिक्षण से पहले और बाद मे उठाए जाने वाले कदमो के बारे मे बताया है।

अगले साल भी ओलंपिक के आयोजन में कई कठिन चुनौतियां

सिडनी। एक सीनियर ओलंपिक अधिकारी ने चेताया है कि स्थगित हो चुके तोक्यो ओलंपिक को अगले साल भी कराने मे कई कठिन चुनौतियां है खासकर जब कोरेना वायरस का वैक्सीन भी नही आया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वरिष्ठ अधिकारी जॉन कोट्स ने कहा कि अधिकारी अक्टूबर में यह तय करना शुरू करेंगे कि जुलाई 2021 में ओलंपिक कैसे होगा। उन्होंने आस्ट्रेलियाई मीडिया समूह न्यूज कोर की एक परिचर्चा मे कहा कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साफ तौर पर कहा है कि तोक्यो ओलंपिक दूसरी बार टाले नही जा सकते।

चार बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन एशले का निधन

ब्रिसबेन। चार बार के एकल ग्रैंडस्लैम टेनिस चैम्पियन एशले कूपर का निधन हो गया, वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह 83 वर्ष के थे। टेनिस आस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व नंबर एक रैंकिंग के खिलाड़ी और लंबे समय तक प्रशासक रहे कूपर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। एशले कूपर ने 1958 मे अमेरिकी चैम्पियनशिप सहित आस्ट्रेलियाई और विम्बलडन मे ग्रैंडस्लैम ट्राफी अपने नाम की थी। कूपर की अगुआई मे आस्ट्रेलिया की डेविस कप टीम ने 1957 मे अमेरिका पर जीत से अपना खिताब बरकरार रखा था और 1959 मे पीठ की चोट के कारण उनका पेशेवर करियर खत्म हो गया था। आस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी रॉड लीवर ने सोशल मीडिया पर कूपर को श्रद्धांजलि दी।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के दावे को बीसीसीआई ने नकारा

● हमने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है : धूमल

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के कोषाध्यक्ष अरूण धूमल ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के दावे को नकारते हुए कहा कि बोर्ड ने अगस्त में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है, सिर्फ इसकी संभावनाओं पर चर्चा हुई है।

सीएसए के निदेशक ग्रीम स्मिथ और कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी जॉक फॉल ने गुरूवार को कहा था बीसीसीआई ने तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए हामी भर दी है। लेकिन धूमल ने उनकी बातों को नकार दिया। धूमल ने पीटीआई-भाषा से कहा, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जब दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा रद्द हो गया, तो हमने कहा था कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने का प्रयास करेगी। हमने हालांकि कभी भी अगस्त में दौरा करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई थी। बीसीसीआई के इस वरिष्ठ पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा को मंजूरी नहीं देती, बीसीसीआई किसी भी देश से प्रतिबद्धता करने की स्थिति में नहीं होगा। धूमल ने कहा, अभी, हम यह भी नहीं कर सकते हैं कि हम जुलाई में श्रीलंका और फिर जिम्बाब्वे (टी 20 श्रृंखला) के लिए टीम भेज सकते है या नहीं। यह दोनों दौरे हमारे एफटीपी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हमें अभी यह भी नहीं पता है कि दो महीने बाद स्थिति क्या होगी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर कैसे प्रतिबद्ध हो सकते हैं? धूमल से जब सीएसए के क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली के आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए समर्थन के बारे मे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय इस पद पर होगा तो यह वैश्विक क्रिकेट के लिए अच्छा होगा उन्होंने कहा, आईसीसी अध्यक्ष पद को लेकर बीसीसीआई में कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। ग्रीम स्मिथ ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बात की थी जो सीएसए का रुख नहीं है। सीएसए के अध्यक्ष क्रिस नानजानी ने शुक्रवार को जारी बयान में स्मिथ के को गांगुली के साथ देने का समर्थन करने से इनकार कर दिया।धूमल ने कहा, जहां तक बीसीसीआई का संबंध है, हम निश्चित रूप से एक भारतीय को वैश्विक निकाय का नेतृत्व करता देखना चाहेंगे और हमारे अध्यक्ष के पास साफ तौर पर इसकी काबिलियत है। लेकिन हमने इस पर चर्चा नहीं की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू हाने की घोषणा कर दी है। धूमल ने कहा कि बोर्ड राष्ट्रीय शिविर के लिए सुरक्षित स्थान का विकल्प तलाश सकता है। अगर बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में इसे आयोजित नहीं किया जा सकता तो धर्मशाला अच्छा विकल्प हो सकता है। धर्मशाला में इंडोर स्टेडियम की भी सुविधा है। उन्होंने कहा, चूकिं यह मेरा राज्य संघ है, ऐसे में मैं इसकी पैरवी नहीं कर सकता।

स्मिथ के बयान से सीएसए ने किया किनारा

जोहानिसबर्ग। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने शुक्रवार को आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के अध्यक्ष पद के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का समर्थन करने वाले अपने क्रिकेट निदेशक ग्रीम स्मिथ के बयान से अलग रूख अपनाते हुए कहा कि किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देने से पहले प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सीएसए के क्रिकेट निदेशक और पूर्व कप्तान स्मिथ ने आईसीसी के शीर्ष पद के लिए गुरुवार को गांगुली का समर्थन किया था। उन्होने कहा था मौजूदा परिस्थितियो मे गांगुली की तरह का व्यक्ति आईसीसी के नेतृत्व के लिए आदर्श होगा। इसके एक दिन बाद ही हालांकि सीएसए ने स्मिथ के बयान से अलग रूख अपनाया। सीएसए के अध्यक्ष क्रिस नेनजानी की ओर से जारी बयान मे कहा गया, किस उम्मीदवार का समर्थन करना है, यह तय करने से पहले हमे आईसीसी और अपने स्वयं के प्रोटोकॉल का सम्मान करना चाहिए।

आईसीसी ने 14 दिन के अलग अभ्यास शिविर और सीएमओ की नियुक्ति की सिफारिश की

दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को कोरेना वायरस सकट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली के लिए अपने दिशानिर्देशों मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की नियुक्ति और 14 दिन तक अलग थलग अभ्यास शिविर आयोजित करने की सिफारिश की। आईसीसी ने दुनिया भर मे क्रिकेट की बहाली के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए और साथ ही उच्च सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखने पर भी ध्यान दिया। आईसीसी ने कहा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जैव सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर विचार करे जो सरकारी दिशानिर्देशो तथा अभ्यास और प्रतियोगिता की बहाली के लिए जैव सुरक्षा योजना लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके दिशानिर्देशो मे कहा गया है, मैच से पूर्व अलग थलग अभ्यास शिविर के आयोजन, स्वास्थ्य, तापमान जांच और कोविड-19 परीक्षण की जरूरत पर विचार करे।

मुक्केबाजों के अभ्यास शिविर पर संशय

● जल्द शुरू होने की संभावना नही

भाषा। नई दिल्ली

मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है और मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार है लेकिन भारतीय मुक्केबाजों के शिविर में अभ्यास शुरू करने की संभावना बहुत कम है क्योंकि राष्ट्रीय महासंघ कोविड-19 महामारी के चलते साजो सामान से जुड़ी कुछ चिंताओं से घिरा हुआ है। गृह मंत्रालय ने खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी है और भारतीय खिलाड़ी भी फिर से अभ्यास पर लौटने के लिए बेताब है जिनमें मुक्केबाज भी शामिल हैं जो पिछले दो महीनों से अपने घरों में ही फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के कार्यकाकारी निदेशक आर के साचेती ने पीटीआई-भाषा से कहा कि , भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) टीम विभाग के पास हमारा प्रस्ताव लंबित है। एक बार हमें स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है तो फिर अभ्यास शुरू करने पर आगे चर्चा करेंगे। साचेती ने इस तरह से तुरंत शिविर शुरू नहीं होने के स्पष्ट संकेत दे दिए। मुक्केबाजों और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और महामारी के बीच अभ्यास शुरू करने के जोखिमों को स्वीकार करना होगा। इसके बाद ही उन्हें अभ्यास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) केंद्रों में वापस लौटने की अनुमति मिलेगी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, साइ की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आप रिंग में नहीं जा सकते। आप अभ्यास के लिए साथी को नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में संक्रमण के जोखिम के बीच उन्हें (मुक्केबाजों) एकत्रित करने का कोई मतलब नहीं होगा। खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने इससे पहले कहा था कि कम से कम ओलंपिक में जगह बना चुके खिलाड़ियों के लिए इस महीने के आखिर तक अभ्यास शिविर खोलने की योजना है।

भारतीय टीम के आस्ट्रेलिया दौरे की संभावना 90 प्रतिशत : क्रिकेट आस्ट्रेलिया सीईओ

मेलबर्न। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन राबर्ट्स ने कहा है कि भारतीय टीम के इस साल के आखिर मे चार टेस्ट की श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलिया का दौरा करने की 90 प्रतिशत संभावना है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया इस समय काफी आर्थिक दबाव मे है और उसे हर हालत मे इस श्रृंखला की जरूरत है। इसके जरिए उसे प्रसारण अधिकार के 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। कोरेना वायरस महामारी के कारण उसे अपने 80 प्रतिशत स्टाफ को जून तक 20 प्रतिशत वेतन पर रखना पड़ रहा है। यह श्रृंखला अक्टूबर से जनवरी 2021 के बीच खेली जाएगी। राबर्ट्स ने न्यूज कोर से कहा , आजकल कुछ भी निश्चित नही है। मै यह नही कहूंगा कि दौरे की संभावना दस मे से दस है लेकिन दस मे से नौ जरूर है। अभी कुछ कह नही सकते कि दर्शक होगे या नही। अगर भारत का दौरा नही होता है तो मुझे हैरानी होगी। लेकिन मै इतना जरूर कहूंगा कि दौरे की शुरूआत से ही स्टेडियम मे दर्शक नही होगे। उसके बाद देखते है कि क्या होता है। आस्ट्रेलियाई टीम को सीमित ओवरो की श्रृखला के लिए इंग्लैड जाना है लेकिन इससे पहले क्रिकेट आस्ट्रेलिया पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के इंग्लैड दौरे का इंतजार करेगा। हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नही करेंगे। हम देखते है कि वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का इंग्लैड दौरा कैसा रहता है। उम्मीद है कि कोई परेशानी नही आएगी।

इंडिया ओपन दिसंबर में आयोजित होगा

● बीडब्ल्यूएफ ने सुधार के साथ कैलेंडर घोषित किया

भाषा। नई दिल्ली

कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हुआ ओलंपिक क्वालीफाइंग इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अब आठ से 13 दिसंबर तक यहां आयोजित किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने महामारी से प्रभावित सत्र को बचाने के लिए संशोधित कैलेंडर घोषित किया है। बीडबल्यूएफ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विश्व टूर सुपर 500 टूर्नामेंट पहले 24 से 29 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होना था लेकिन अब इसका आयोजन आठ से 13 दिसंबर को कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता से पहले 11 से 16 अगस्त तक हैदराबाद ओपन और 17 से 22 नवंबर तक सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला जाएगा। बीडब्ल्यूएफ की घोषणा भारत के एकल खिलाड़ियों को इंडोर कोर्ट में जाने की अनुमति देने के एक दिन बाद हुई है। बैडमिंटन उन 11 खेलों की सूची मे शामिल है जिन्हें ट्रेनिंग बहाल करने की अनुमति दी गई है। आठ टूर्नामेंट को अपने पूर्व कार्यक्रम से हटाकर नई तारीखों में कराया जाएगा जिसमें न्यूजीलैंड ओपन सुपर 300 (20 से 25 अक्टूबर) , इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 (17 से 22 नवंबर), मलेशिया ओपन सुपर 750 (24 से 29 नवंबर), थाईलैंड ओपन सुपर 500 (एक से छह दिसंबर) और चीन में विश्व टूर फाइनल्स (16 से 20 दिसंबर) शामिल है। चार टूर्नामेंट-जर्मन ओपन, स्विस ओपन, यूरोपीय चैम्पियनशिप और आस्ट्रेलियाई ओपन निलंबित रहेंगे और बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि इनके लिए उचित तारीखों की योजना बनाई जा रही है। सिंगापुर ओपन सुपर 500 (सात से 12 अप्रैल) और बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप (21 से 26 अप्रैल) सहित 10 टूनामेंट रद्द हो गए हैं जो 28 अप्रैल की ओलंपिक क्वालीफिकेशन समयसीमा के अंदर थे।

टेस्ट क्रिकेट में पिछले पांच साल में 15 सलामी जोड़ियां आजमाई हैं भारत ने

आस्ट्रेलिया दौरे पर मयंक के साथ रोहित ही पारी का आगाज कर सकते हैं

नई दिल्ली। रोहित शर्मा के सीमित ओवरो मे सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाने से पिछले सात वर्षो मे भारत को दोनों छोटे प्रारूपो में ओपनिंग को लेकर ज्यादा माथापच्ची नही करनी पड़ी लेकिन टेस्ट क्रिकेट मे उसकी एक अदद सलामी जोड़ी की तलाश अब भी जारी है। रोहित को पिछले साल अक्टूबर मे टेस्ट मैचो मे भी सलामी बल्लेबाज की भूमिका मे उतारा गया था और वह इसमे सफल भी रहे लेकिन उनकी असली परीक्षा विदेशी पिचो पर होनी थी और न्यूजीलैंड दौरे से पहले उनके चोटिल होने के कारण भारत को 2020 मे खेले गए दो टेस्ट मैचों मे नई सलामी जोड़ी के साथ उतरना पड़ा था। भारत अगर इस साल के आखिर मे आस्ट्रेलिया दौरे पर जाता है तो फिर पूरी संभावना है कि मयंक अग्रवाल के साथ रोहित ही पारी का आगाज करेंगे लेकिन अन्य बल्लेबाजों विशेषकर युवा पृथ्वी साव की दावेदारी को भी कम करके नही आंका जा सकता है जबकि केएल राहुल एकदिवसीय प्रारूप मे अच्छे प्रदर्शन के कारण लंबे प्रारूप मे खेलने का दावा मजबूत करते जा रहे है। इनके अलावा मुरली विजय और शिखर धवन की दावेदारी को भी नही नकारा जा सकता है। पिछले पांच वर्षो मे भारत ने धवन, राहुल, विजय, अग्रवाल, रोहित, पार्थिव पटेल, सॉव, गौतम गंभीर, हनुमा विहारी, अभिनव मकुंद और यहां तक कि तीसरे नंबर पर खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा को भी पारी का आगाज करने के लिए भेजा। इस बीच भारत ने इन खिलाड़ियों को मिलाकर 15 जोड़ियां आजमाई। राहुल ने सर्वाधिक 32 टेस्ट मैचो मे ओपनिंग की जबकि विजय ने 29, धवन ने 21 और अग्रवाल ने 11 मैचो मे यह जिम्मेदारी संभाली। अग्रवाल ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 मे मेलबर्न मे बाक्सिंग डे टेस्ट मैच मे पदार्पण किया और शीर्ष क्रम के पहले दो स्थानो मे से एक स्थान को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होने अब तक 11 मैचो की 17 पारियो मे 974 रन बनाए है लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ चार पारियो मे वह 102 रन ही बना पाए थे जबकि सॉव ने 98 रन बनाए थे। लेकिन इस पूरी श्रृंखला मे सभी भारतीय बल्लेबाज नाकाम रहे थे। रोहित टेस्ट मैचो मे फिर से पारी का आगाज करने के लिए बेताब होंगे। उन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम मे पहली बार यह भूमिका निभाई और दोनो पारियो मे शतक (174 और 127) ठोककर नया रिकार्ड बनाया था। इसके बाद उन्होने रांची मे 212 रन की लाजवाब पारी खेली लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ दोनो टेस्ट मैचों मे उनका बल्ला कुंद पड़ा रहा। साव ने अब तक जो चार टेस्ट मैच खेले है उनमे एक शतक की मदद से 335 रन बनाए है। अगर पिछले पांच वर्षो मे अन्य देशो की सलामी जोड़ियो की बात करे तो इंग्लैड और श्रीलंका के बाद भारत ने सर्वाधिक बल्लेबाजो से पारी की शुरुआत करवाई। इंग्लैड ने इस बीच 17, श्रीलंका ने 12, भारत ने 11, दक्षिण अफ्रीका ने 10, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने नौ-नौ खिलाड़ियो को सलामी बल्लेबाज के रूप मे आजमाया। न्यूजीलैंड ने टॉम लैथम की वजह से इस बीच स्थायित्व दिखाया और पिछले पांच वर्षों में उसने केवल चार खिलाड़ियों को ओपनिंग का दायित्व सौपा। लैथम ने पिछले पांच वर्षो मे अपनी टीम की तरफ से सभी 42 मैचो मे पारी का आगाज किया।

आईपीएल महज धन कमाने का धंधा है, टी20 विश्व कप पर तरजीह नही दी जानी चाहिए: बॉर्डर

मेलबर्न। पूर्व आस्ट्रेलियाई एलेन बॉर्डर ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) महज पैसा कमाने का धंधा है और इस साल होने वाले टी20 विश्व कप पर इसे तरजीह देने की अनुमति नही दी जा सकती। ऐसी अटकले लगाई जा रही है कि अगर आस्ट्रेलिया मे टी20 विश्व कप स्थगित हो जाता है तो कोविड-19 महामारी के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए आईपीएल का 13वां चरण अक्टूबर-नवंबर मे आयोजित किया जा सकता है। बॉर्डर ने एबीसी के ग्रैंडस्टैंड कैफे रेडियो कार्यक्रम मे कहा, मै इससे खुश नही हूं। विश्व संस्था के टूर्नामेंट को स्थानीय प्रतियोगिता पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसलिए अगर विश्व टी20 नही हो सकता तो मुझे नही लगता कि आईपीएल आयोजित हो सकता है। मै इस फैसले पर सवाल उठाऊंगा -- यह सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है, क्या ऐसा नही है? उन्होने कहा, विश्व टी20 को निश्चित रूप से तरजीह दी जानी चाहिए।

आईपीएल के बजाय घरेलू टूर्नामेंट को चुनना चाहिए: चैपल

मेलबर्न। पूर्व कप्तान इयान चैपल को लगता है कि शीर्ष आस्ट्रेलियाई क्रिकेटरो को लुभावनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बजाय देश की घरेलू प्रतियोगिता को तरजीह देनी चाहिए क्योकि क्रिकेट आस्ट्रेलिया उनकी वित्तीय जरूरतो का पूरा ख्याल रखता है। इस समय करीब 13 आस्ट्रेलियाई क्रिकेटरो के पास आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ लुभावने करार है जिसमे मुख्य तेज गेंदबाज पैट कमिंस को कोलकाता नाइटराइडर्स से 15.5 करोड़ रूपए का अनुबंध मिला था जिससे वह लीग मे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। ऐसी अटकले लगाई जा रही है कि अगर आस्ट्रेलिया मे टी20 विश्व कप स्थगित हो जाता है तो कोविड-19 महामारी के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए आईपीएल का 13वां चरण अक्टूबर-नवंबर मे आयोजित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे आईपीएल और आस्ट्रेलिया का घरेलू सत्र एक ही समय पर होगे जिसमे शेफील्ड शील्ड और वनडे कप शामिल है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने एसएसपी को सौंपे मास्क, सैनेटाइजर व ग्लब्स

कानपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम ,कानपुर मंडल द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए 1500 थ्री प्लाई मास्क, 1500 हेंड सेनेटाइजर व 1500 विनायल ग्लब्स का वितरण किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर मण्डल के वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक विनोद उनियाल के आदेशानुसार कोविड 19 के प्रसार को रोकने में लगे कोरोना वारियर्स (पुलिसकर्मी) को उनके बचाव हेतु 1500 थ्री प्लाई मास्क, 1500 हेंड सेनेटा इजर व 1500 विनायल ग्लब्स विपणन प्रबन्धक सुरेश चन्द्र गौतम द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनन्त देव तिवारी को प्रदान किये गये। इस अवसर पर विष्णु मिश्रा प्रबन्धक विक्रय, सुदेश कुमार पाण्डेय प्रबन्धक विक्रय व अन्य सहयोगी उपस्थित थे।

ब्याज दर कम होने से बढ़ेगी मांग, समर्थन के और उपायों की जरूरत: उद्योग जगत

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक के रेपो दर घटाने के कदम की सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह न सिर्फ छोटे व्यवसायो को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा बल्कि यह मांग को भी पुनर्जीवित करेगा।

हालांकि, उद्योग जगत ने कहा कि कोरेना वायरस महामारी के बीच आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार दोनो से निरंतर आधार पर अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। रिजर्व बैंक ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए शुक्रवार को रेपो दर मे 0.40 प्रतिशत की कटौती की। केंद्रीय बैंक ने कर्ज की किस्ते चुकाने मे दी गई राहत अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंको के लिए कॉरपोरेट को कर्ज देने की सीमा नेटवर्थ के मौजूदा 25 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी है।

सीपीईसी की अमेरिकी की आलोचना को चीन, पाकिस्तान ने किया खारिज

इस्लामाबाद/बीजिंग। पाकिस्तान और चीन ने अरबो डॉलर की परियोजना सीपीईसी और इससे जुड़े कर्ज को लेकर अमेरिका की आलोचना को शुक्रवार को दरकिनार कर दिया। उन्होने कहा कि यह ऐसे दो देशो के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण परियोजना है, जो सदा दोस्त रहे है।

विदेशी मुद्रा भंडार 1.73 अरब डॉलर बढ़कर 487.04 अरब डॉलर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 मई को समाप्त सप्ताह मे 1.73 अरब डॉलर बढ़कर 487.04 अरब डॉलर हो गया। यह देश के 12 महीने के आयात के बराबर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ो मुताबिक एक अप्रैल से 15 मई के बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार मे 9.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। आठ मई को समाप्त सप्ताह पर यह 485.31 अरब डॉलर था। छह मार्च को समाप्त हफ्ते मे यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 487.23 अरब डॉलर पर था।

जीडीपी में इस साल आ सकती है गिरावट : आरबीआई गवर्नर

भाषा। मुंबई

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पहले के अनुमान के मुकाबले ज्यादा रह सकता है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट आ सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति परिदृश्य भी काफी अनिश्चित बना रहेगा। मौजूदा संकट से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने मौद्रिक उपाय के तौर पर शुक्रवार को रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। पिछले दो महीने में रेपो दर में यह लगातार दूसरी बड़ी कटौती है। इससे पहले 27 मार्च को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.75 प्रतिशत की कटौती की थी। लॉकडाउन और शारीरिक दूरी से जुड़ी सभी अनिश्चिताओं को ध्यान में रखते हुए दास ने कहा, 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक रहने का अनुमान है। दूसरी छमाही से ही थोड़ी बहुत वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। आरबीआई गवर्नर ने टेलीविजन के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि वृद्धि से जुड़ा यह जोखिम सबसे अधिक गहरा है। मांग में कमी और आपूर्ति में बाधा के चलते वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों पर दबाव रहेगा। चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू किए जाने के बावजूद मौजूदा समय में उठाए जा रहे राजकोषीय, मौद्रिक और प्रशासनिक कदमों का अर्थव्यवस्था पर असर 2020-21 की दूसरी छमाही में ही दिखना शुरू होगा। यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कोविड-19 का संक्रमण कितनी तेजी से सीमित होता है। मई 2020 के अंत में जारी होने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े राष्ट्रीय आय के बारे में अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने रखेंगे।

रिजर्व बैंक के उपायों पर भारी कोविड-19 महामारी, सेंसेक्स 260 अंक टूटा

भाषा। मुंबई

बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों में गिरावट से शुक्रवार को सेंसेक्स 260 अंक टूट गया। रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए ब्याज दरों में कटौती और कर्ज चुकानों वालों को तीन माह की और राहत देने जैसे उपाय किए हैं, लेकिन कोविड-19 को लेकर बढ़ती चिंता इन सब पर भारी रही। कोविड-19 संकट के बीच रिजर्व बैंक ने कर्ज किस्त के भुगतान पर छूट को तीन महीने ओर बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 तक कर दिया है। इससे बैंकों का डूबा कर्ज बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में एक समय 450 अंक तक नीचे चला गया था। हालांकि, बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ। अंत में सेंसेक्स 260.31 अंक या 0.84 प्रतिशत के नुकसान से 30,672.59 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी भी 67 अंक या 0.74 प्रतिशत के नुकसान से 9,039.25 अंक पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स 425.14 अंक या 1.36 प्रतिशत तथा निफ्टी 97.6 अंक या 1.06 प्रतिशत नीचे आया है। सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर सबसे अधिक 5.65 प्रतिशत से नीचे आ गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में आ सकती है गिरावट: मूडीज

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस का अनुमान है कि 2020-21 मे भारतीय अर्थव्यवस्था मे गिरावट देखने को मिल सकती है। यह चार दशक मे पहली बार होगा जब कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन (बंद) की वजह से खपत कम होने और करोबारी गतिविधियां थमने से चुनौतियो का सामना कर रही घरेलू अर्थव्यवस्था मे गिरावट आएगी। मूडीज के मुताबिक कोरोना वायरस संकट से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी पड़ गई थी और यह छह वर्ष की सबसे निचली दर पर पहुंच गई थी।

PUBLIC NOTICE

To, be known to all that my client, **Smt. Manju Mohan Gupta W/o Late Sh. Dinesh Mohan** R/o Flat No.242-B, Pocket-J&K, Dilshad Garden, Delhi-110095, is the owner of DDA MIG Flat No.242-B. First Floor, Pocket-J&K, Situated At Dilshad Garden, Delhi-110095, Vide Dda File No.F.22(602)85/DG/NP, have applied for Certified Copies of lost document of the said flat. The original documents i.e. Demand/allotment letter, possession letter, site possession slip, NOC for water & electricity connection of the above said property have been lost or misplaced by my clients and are not traceable inspite of their best efforts. An F.I.R./NCR to this effect has been lodged in the Police Station, Crime Branch, Delhi **(LR No.3199 53/2020 dated 22.5.2020).**

Any person(s) claiming any rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No.**9810175844** within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (Housing) or Director (Housing), Vikas Sadan, New Delhi.

Naveen Aggarwal (Advocate)
Ch.No. 7, Tis Hazari Court, Delhi-110054

कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) गाजियाबाद

पत्रांकः—2062 / डूडा / 2020—21 /   दिनांकः— 22.05.2020

निविदा सूचना

विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत श्री नन्दकिशोर गुर्जर, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र लोनी की निधि से प्राप्त धनराशि से 17 कार्य कराये जाने प्रस्तावित है, जिस हेतु अनुभवी ठेकेदारों से निविदाए आमन्त्रित की जाती है। निविदा की बिक्री दिनांक 01.06.2020 से 03.06.2020 तक कार्यालय समय में डूडा कार्यालय गाजियाबाद से की जायेगी। मोहर बन्द निविदाएं दिनांक 08.06.2020 को सांय 4.00 बजे तक डूडा कार्यालय स्थित बेसमेन्ट नगर निगम गाजियाबाद में डाली जायेगी।

प्राप्त निविदाएं दिनांक 09.06.2020 को गठित समिति के सम्मुख प्रातः 11:30 बजे खोली जायेगी। निविदा के मूल्य एवं कार्यों का विस्तृत विवरण एवं निविदाओं के सम्बन्ध में सूचना डूडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा डूडा कार्यालय गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है।

(हस्ता)
परियोजना अधिकारी
डूडा गाजियाबाद

कोरोना को लेकर विरोधियों पर बरस रहे ट्रंप

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 महामारी के दौरान अपने दावों के विपरीत बात करने वाले डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर बरस रहे हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर यह बात साबित भी की है। वैज्ञानिकों के एक शोध को उन्होंने ट्रंप के दुश्मन की बात बताया तो वहीं एक अध्ययन को राजनीति से प्रेरित कह दिया।

अमेरिका में लॉकडाउन खोलने को लेकर जब डॉक्टरों ने कहा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं तो ट्रंप ने इस बात को भी अनसुना कर दिया। ट्रंप ने इस सप्ताह न केवल दो अध्यननों को नकार दिया बल्कि बिना सबूतों के यह भी कह दिया कि ए अध्ययन करने वाले लोग राजनीति से प्रेरित हैं और कोरोना वायरस पाबंदियों को खत्म करने के उनके प्रयासों पर पानी फेरना चाहते हैं। यही नहीं, जब उनकी सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के वित्तपोषण से किए गए अध्यनन में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया गया तो ट्रंप ने उसे भी खारिज कर दिया। इस अध्ययन में कहा गया था कि इस दवा के इस्तेमाल के बावजूद रोगियों की मृत्युदर में कोई कमी नहीं आई है। ट्रंप और उनके कई सहयोगियों का मानना है कि यह दवा कोविड-19 रोगियों के इलाज में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ट्रंप ने इस सप्ताह बताया कि वह खुद कोरोना वायरस से बचने के लिए इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की पिछले महीने दी गई उस चेतावनी को भी दरकिनार कर दिया कि इस दवा का इस्तेमाल केवल अस्पतालों में या नैदानिक परीक्षण के लिए ही किया जाना चाहिए क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। बिना जरूरत इसे खाने से हृदय संबंधी जानलेवा रोग का शिकार होने का खतरा पैदा हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से इस बारे में कहा, यह ट्रंप से दुश्मनी दिखाने वाली बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेलमेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अध्यनन को लेकर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी।

अध्ययन में कहा गया था कि अगर एक सप्ताह पहले सामाजिक मेलजोल से दूरी के नियमों का पालन किया गया होता तो संक्रमण के लगभग 61 प्रतिशत और मौत के 55 प्रतिशत मामले कम सामने आते। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को इस अध्ययन को नकारते हुए कहा, कोलंबिया एक बहुत उदारवादी संस्थान है। मुझे लगता है कि उनका यह अध्ययन राजनीति से प्रेरित है। आपको सच जानना चाहिए। अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ लैरी गोस्टिन का कहना है, अगर ट्रंप इसी तरह विज्ञान का राजनीतिकरण करते रहे और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बातों को नकारते रहे तो जनता से बीच डर और भ्रम बैठता चला जाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने ट्रंप के इस रवैए पर उठ रहे सवालों को खारिज किया है। उसका कहना है कि ट्रंप अपने प्रशासन के जन स्वास्थ्य अधिकारियों के सुझावों का अनुसरण करते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जुड डीरे ने कहा है, यह कहना कि राष्ट्रपति, वैज्ञानिक आंकड़ों या वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कार्यों को महत्व नहीं देते, पूरी तरह गलत है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आंकड़ों पर आधारित कई फैसले लिए हैं। इनमें अधिक संक्रमित आबादी वाले इलाकों में जल्द यात्रा प्रतिबंध लगाने जैसा फैसला शामिल है।

तीन दिन आधा झुका रहेगा अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में 95,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो जाने के शोक में अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज आगामी तीन दिन तक आधा झुका रहेगा।ट्रम्प ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, मैं कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके अमेरिकियों की याद में सभी संघीय इमारतों और राष्ट्रीय स्मारकों पर तीन दिन तक ध्वज आधे झुकाए जाने का आदेश दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि ध्वज देश के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों की याद में मनाए जाने वाले स्मृति दिवस तक आधे झुके रहेंगे। उल्लेखनीय है कि डेमोक्रेटिक नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस संक्रमण से एक लाख लोगों की मौत होने पर शोक दिवस मनाया जाए।

प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी और सीनेटर चक शूमर ने ट्रम्प को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था।

ब्रिटेन में कोविड-19 के इलाज के लिए तैयार टीके की दस हजार से अधिक लोगों पर परीक्षण की तैयारी

भाषा। लंदन

ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार प्रायोगिक टीके का परीक्षण अगले चरण में पहुंच रहा है और सफल होने पर इसे दस हजार से अधिक लोगों को लगाने की तैयारी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रायोगिक टीके का प्रभाव और सुरक्षा की जांच करने के लिए एक हजार से अधिक स्वयंसेवकों पर परीक्षण की शुरुआत की थी। वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी योजना अब पूरे ब्रिटेन में बच्चों और बुजुर्गों सहित 10,260 लोगों पर इस टीके का परीक्षण करने की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में टीका विकसित करने की काम में लगी टीम का नेतृत्व कर रहे एंड्रयू पोलार्ड ने कहा, चिकित्सीय अध्ययन बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम बुजुर्गों में भी इस टीके का परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह टीका पूरी आबादी को सुरक्षा मुहैया करा सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में दवा निर्माता एस्ट्राजिनसा ने कहा था कि उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके की 40 करोड़ खुराक के लिए करार किया है। टीके के विकास, उत्पादन और वितरण के लिए अमेरिकी सरकार की एजेंसी ने एक अरब डॉलर का निवेश किया है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए करीब एक दर्जन संभावित टीके मानव पर परीक्षण शुरू करने के लिए शुरुआती चरण में पहुंच गए हैं या शुरू होने वाले हैं। इनमें से अधिकतर चीन, अमेरिका और यूरोप के हैं एवं दर्जनों अन्य टीके विकास के शुरुआती दौर में हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में कोई टीका विकसित नहीं किया है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंततः क्या ए टीके सुरक्षित और प्रभावी साबित होंगे। ऐसी संभावना है कि शुरुआत में प्रभावी दिखने वाला टीका बड़े स्तर पर होने वाले परीक्षण में नाकाम हो जाए।

भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ उकसावे वाली सैन्य गतिविधियों में शामिल है चीनः व्हाइट हाउस

भाषा। वाशिंगटन

भारत के अपने क्षेत्र में चीन की दखलअंदाजी का कड़ा विरोध किए जाने के कदम का अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक द्वारा समर्थन करने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन भारत समेत अपने पड़ोसी देशों के साथ उकसावे वाली और बलपूर्वक सैन्य एवं अर्द्धसैन्य गतिविधियों में संलिप्त है। व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट में कहा, बीजिंग पीला सागर, पूर्व तथा दक्षिण चीन सागरों, ताइवान जलडमरूमध्य और चीन-भारत सीमा इलाकों में उकसावे वाली और बलपूर्वक सैन्य तथा अर्द्धसैन्य गतिविधियों में संलिप्त होकर अपने पड़ोसियों से की गई प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता तथा अपने बयान से विरोधाभासी रुख अपनाता है। चीन गणराज्य की ओर अमेरिका का कूटनीतिक रुख शीर्षक की यह रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपी गई।

रिपोर्ट में कहा गया है, चूंकि चीन की ताकत बढ़ी है तो अपने हितों के लिए माने जा रहे खतरों को खत्म करने तथा वैश्विक रूप से कूटनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिशों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की धमकी देने और बल का इस्तेमाल करने की इच्छा तथा क्षमता प्रबल हुई है। दरअसल चीन से लगी भारत की सीमा पर तनाव के बीच अमेरिका ने नई दिल्ली का समर्थन किया। एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने बीजिंग पर आरोप लगाया कि वह अपने अतिसक्रिय और परेशान करने वाले व्यवहार से यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है और उसका विरोध करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एवं मध्य एशिया ब्यूरो की निवर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे लगता है कि सीमा पर जो तनाव है वह इस बात को याद दिलाता है कि चीन आक्रामक रुख जारी रखे हुए है।

खशोगी के बेटों ने पिता के हत्यारों को किया माफ, पांच की मौत की सजा टली

दुबई। वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी के बेटों ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया है, जिससे सऊदी के पांच सरकारी एजेंटों की मौत की सजा पर रोक लग गई है। सलाह खशोगी ने ट्वीट किया, हम शहीद जमाल खशेगी के बेटे अपने पिता के हत्यारों को माफ करते हैं, जिसका फल हमें अल्लाह से मिलेगा। सलाह खशेगी सऊदी अरब में रहते हैं और पिता की हत्या के मामले में उन्हें शाही अदालत से वित्तीय मुआवजा भी मिल चुका है। अरब न्यूज ने खशोगी के बेटों की घोषणा पर स्पष्टता देते हुए कहा कि बेटों के माफ कर देने से हत्यारे मौत की सजा से बच सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं है कि उनकों कोई भी सजा नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि इस्तांबुल स्थित सऊदी के वाणिज्य दूतावास में जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। हत्या की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई थी और मामले में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। खशोगी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। मामले में दोषी पाए गए 11 लोगों में से पांच को मौत की सजा सुनाई गई, तीन को कुल 24 वर्ष जेल की सजा हुई और अन्य बरी हो गए।इस संबंध में आरोपी दो जानी-मानी हस्तियों को दोषमुक्त करार दिया गया था। उन्हें सलमान का करीबी बताया जाता है।

यूटा के मुरैना में इंटरमाउंटेन मेडिकल सेंटर में हेल्थकेयर वर्कर्स ने विशालकाय अमेरिकी ध्वज फहराया

चीन ने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए भारत से समर्थन मांगा

भाषा। बीजिंग

चीन ने हांगकांग के ऊपर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के अपने विवादास्पद फैसले को लेकर भारत एवं अन्य देशों का समर्थन मांगा है और कहा है कि इसका लक्ष्य इस पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में पृथकतावादी ताकतों को काबू में रखना है जिन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की धार को कुंद करने के लिए चीन ने नए मसौदा कानून के कारणों को स्पष्ट करते हुए भारत एवं अन्य देशों को पत्र लिखा है और कहा है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना विशुद्ध रूप से चीन का अंदरूनी विषय है।

चीन ने हांगकांग पर अपना नियंत्रण मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार को अपनी संसद में हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया था। इसे 1997 के बाद से हांगकांग की क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं निजी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हांगकांग 1997 में ही चीन शासन के अंतर्गत आया था। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ब्रिटेन द्वारा एक जुलाई, 1997 को हांगकांग की संप्रभुता चीन को सौंपने के बाद से वहां एक देश दो विधान रहा है। इस व्यवस्था में उसे कुछ स्वतंत्रताएं मिलीं जो बाकी चीन को प्राप्त नहीं हैं। विभिन्न देशों को सौंपे पत्र में चीन ने कहा है, आपके देश का हांगकांग के साथ घनिष्ठ आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग और दोनों की जनता के बीच आपसी संबंध रहा है। हांगकांग की समृद्धि एवं दीर्घकालिक स्थायित्व पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के साझे हितों तथा हांगकांग में आपके देश के वैध हितों के अनुरूप है। हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार इसे समझेगी और चीन की प्रासंगिक पद्धतियों का समर्थन करेगी। इस पत्र में कहा गया है कि 23 साल पहले हांगकांग चीन को लौटाए जाने के बाद से हांगकांग एसएसआर ने चीन के संवैधानिक एवं मूल कानून के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। उसमें कहा गया है, हांगकांग की कानून प्रणाली में स्पष्ट खामियां है और उसे लागू करने की प्रणाली का अभाव है। हांगकांग में विरोधी तत्वों ने चीन की मुख्य भूमि के प्रति अलगाववाद, तोड़फोड़, घुसपैठ और विध्वंसक गतिविधि चलाने के लिए बाहरी तत्वों से हाथ मिला लिया है। उसमें कहा गया है, पिछले साल हांगकांग में संशोधन विधेयक पर उथल-पुथल से एसएआर के कानून के शासन, उसके स्थायित्व को बड़ा नुकसान पहुंचा तथा अर्थव्यवस्था एवं लोगों की जीविका तहस-नहस कर दी। पिछले साल से हांगकांग में लाखों लोग अधिक सवायत्तता और चीन के कम दखल देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

हांगकांग में विपक्ष ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कदम की आलोचना की

भाषा। हांगकांग

हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने इस अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की चीन की कोशिशों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह एक देश, दो व्यवस्थाओं की रूपरेखा के खिलाफ है। चीन की संसद में शुक्रवार को वह विवादित सुरक्षा विधेयक पेश किया गया जो हांगकांग में उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।यह विधेयक पिछले वर्ष हांगकांग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लाया गया है।

चीन की राष्ट्रीय संसद के शुक्रवार को शुरू हुए सत्र के पहले दिन सौंपे गए इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अलगाववादियों और विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के साथ ही विदेशी हस्तक्षेप और आतंकवाद पर रोक लगाना है।चीन के इस कदम पर अमेरिका सरकार और मानवाधिकार समूहों ने कड़ी प्रतिक्रिया की है। पूर्व लोकतंत्र समर्थक सांसद ली च्युक-यान ने कहा, शी चिनफिंग ने एक राष्ट्र, दो व्यवस्थाओं का दिखावा खत्म कर दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं के संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह कदम दिखाता है कि बीजिंग सीधे तौर पर नियंत्रण कर रहा है। उन्होंने कहा, वे हांगकांग में हर उस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने इसे आजादी जैसे वैश्विक मूल्यों के लिए चुनौती बताया। लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक स्टीव त्सांग ने कहा, हांगकांग में कई लोगों के लिए एनपीसी द्वारा इस कानून को लागू करना एक राष्ट्र, दो व्यवस्था के मॉडल का खात्मा होगा। हांगकांग के पूर्व नेता सी वाई ल्युंग ने चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में इस कदम का बचाव करते हुए आगाह किया कि लोकतंत्र समर्थक विपक्ष को हांगकांग के मुद्दों से निपटने के चीन सरकार के दृढ़ संकल्प को कम नहीं आंकना चाहिए।

चीन में शुरू हुआ संसद सत्र

भाषा। बीजिंग

चीन में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण अटका संसद का वार्षिक सत्र शुक्रवार को शुरू हो गया और सरकार ने इस बीमारी से पैदा हुई अनिश्चितताओं, चीन तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट का हवाला देते हुए इस साल के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य तय नहीं किया।

कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में करीब 2,900 सदस्यों के साथ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) सत्र शुक्रवार सुबह शुरू हुआ। इस जानलेवा विषाणु से चीन में 4,634 लोगों की मौत हुई जिनमें से ज्यादातर मौतें वुहान में हुई। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) के मुताबिक बृहस्पतिवार तक चीन में कोविड-19 के मामले 82,971 पर पहुंच गए इनमें से 82 मरीजों का अब भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने एनपीसी को सौंपी 23 पन्नों की कार्य रिपोर्ट में कहा, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने इस साल आर्थिक वृद्धि के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य तय नहीं किया है। चीन ने देश के लगभग सभी हिस्सों को खोल दिया है और अभी संसद के वार्षिक सत्र का आयोजन कर रहा है। यह मार्च में होना था लेकिन कोरोना वायरस संकट के कारण स्थगित हो गया था। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता बिना मास्क पहने बैठक में शामिल हुए जबकि 2,897 सदस्यों ने मास्क पहन रखा था। सदस्यों ने कोविड-19 से लड़ाई में और इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों को मौन श्रद्धांजलि दी। संसद सत्र में भाग लेने वाले सभी लोगों को कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य था।

● कोविड-19 संकट के कारण तय नहीं किया वार्षिक जीडीपी लक्ष्य

हांगकांग का सुरक्षा संबंधी विधेयक चीन की संसद में पेश

बीजिंग। चीन की संसद में शुक्रवार को वह विवादित सुरक्षा विधेयक पेश किया गया जो हांगकांग में उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के शुरू होने के साथ ही यह प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव की अमेरिका समेत हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक लोगों ने आलोचना की है और इस विधेयक को हांगकांग की आजादी पर हमला बताया है। यह विधेयक पिछले वर्ष हांगकांग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लाया गया है। एनपीसी सत्र के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस विधेयक को अत्यंत आवश्यक बताया था।

उत्तरी इटली के जेनोवा के एक्वेरियम में खेलती डॉल्फिन

पाकिस्तान में कोविड-19 के मामले 50 हजार के पार

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान में रिकॉर्ड 2,603 मामले आने के बाद शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार चली गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कारण 50 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे मृतकों की संख्या 1,067 हो गई है। देश में 50,694 मामलों में से सबसे ज्यादा सिंध में 19,924 मामले हैं। इसके बाद पंजाब में 18,455, खैबर-पख्तूनख्वा में 7,155, बलूचिस्तान में 3,074, इस्लामाबाद में 1,326, गिलगित-बाल्तिस्तान में 602 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में158 मामले दर्ज हैं।

उसने बताया कि संक्रमण से अब तक 15,201 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,064 मरीज ठीक हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 16,387 नमूनों की जांच की गई है। इसके बाद देश में अब तक 445,987 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच, एमीरेट्स की एक विशेष उड़ान दुबई में फंसे हुए 251 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद हवाई अड्डे पहुंची। संघीय सरकार ने पेशावर में बाचा खान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है।

नेपाल में कोरोना वायरस के 30 नए सामने आए

भाषा। काठमांडू

नेपाल में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 487 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू है।स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 से 21 और लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इस तरह कोरोना वायरस से अब तक 70 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित हुए 30 लोगों में से नौ लोग कपिलवस्तु जिले से है जिनमें 24 से 53 वर्ष की आयु के आठ पुरुष और एक आठ वर्षीय बालिका शामिल हैं। इसी तरह सर्लाही जिले में 22 से 39 वर्ष की आयु के 14 पुरुष और 18 वर्षीय एक महिला इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। चितवन जिले में 73 वर्षीय एक महिला संक्रमित पाई गई है। इस महामारी के शेष नए मामले नवलपरासी जिले से सामने आए है जिनमें 33 से 74 वर्ष की आयु के चार पुरुष और 15 वर्षीय एक किशोरी शामिल हैं।

● संक्रमितों की कुल संख्या 487 हुई

सिंगापुर में कोरोना वायरस के 614 नए मामले, कुल संख्या 30 हजार के पार

सिंगापुर। सिंगापुर में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 614 नए मामले सामने आए जिनमें अधिकतर विदेशी श्रमिक हैं। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30,426 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने प्रारंभिक दैनिक अपडेट में कहा कि नए मामलों में चार रोगी या तो सिंगापुर के नागरिक हैं या स्थाई निवासी (विदेशी) हैं, बाकी अधिकतर विदेशी कामगार हैं। बृहस्पतिवार को यहां कोविड-19 से 73 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 23 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि यहां बड़ी संख्या में विदेशी मजदूरों के सीमित जगह में एक साथ रहने के कारण नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 20,000 के पार

रियो डी जिनेरिया। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या बृहस्पतिवार को 20,000 के पार चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 24 घंटों में सबसे अधिक मौतें हुई।

यह देश लातिन अमेरिका में कोरोना वायरस का केंद्र है और एक दिन में 1,188 लोगों की मौत के साथ संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 20,047 पर पहुंच गई। ब्राजील में संक्रमण के 3,10,000 से अधिक मामले हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जांच में कमी का मतलब है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। संक्रमण और मौत के मामले तेजी से बढ़ने के साथ ब्राजील संक्रमण के कुल मामलों के लिहाज से दुनिया का तीसरा देश है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मरने वाले लोगों की संख्या महज 11 दिनों में दोगुनी हो गई है। बीमारी के तेजी से फैलने की चिंता के बावजूद घोर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने बृहस्पतिवार को भी देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों को हटाने की बात कही।

मनुष्य के भीतर संचित असीम शांति गहन आनंद से परिचय कराता है योग

अपनी फिल्म योग फॉर हेल्थ एंड ग्लोबल हार्मनी की शूटिंग करते हुए फिल्म निर्माता, कला इतिहासकार और फोटोग्राफर बिनॉय के बहल ने अनुभव किया कि योग तो आत्मान्वेषण में भी सहायक है-

योग वास्तव में इस परिवर्तनशील भौतिक विश्व की हर अवधारणा को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। साथ ही ये हमारे भीतर संचित असीम शांति और गहन आनंद से हमारा परिचय कराता है। आज के विश्व में योग के माध्यम से भारतीय दर्शन की अवधारणाओं को लोगों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। ये ज्ञानोन्मुख पथ है जो शारीरिक आयाम के माध्यम से प्रारंभ होता है। विश्व भर में लोग भारतीयता की जड़ों तक पहुंचने के लिए योग को माध्यम के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। ये एक प्रकार से गहन ज्ञान का प्रवेश द्वार है जो विभिन्न आसनों के शारीरिक आयामों से प्रारंभ होता है। इसके माध्यम से हम अपने शरीर, श्वांस, भावों और मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर धीरे-धीरे एकत्व के बारे में हमारे ज्ञान को जागृत करता है। ज्ञातव्य है कि योग का शाब्दिक अर्थ भी एकजुट करना ही होता है।

योग के चार पथ निर्धारित हैं- कर्म योग अर्थात विश्व में निस्वार्थ कर्म का पथ, भक्ति योग, जिसके माध्यम से समर्पण और भक्ति के माध्यम से अहं के त्याग का पथ अपनाया जाता है। तीसरा है राज योग जिसमें प्राणायाम और आसनों के माध्यम से ध्यान हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा और अंतिम पथ है ज्ञानपथ जिसमें ज्ञान के माध्यम से मोक्ष का अनुभव कराया जाता है। न्यूयॉर्क में ब्लेजिंग विज़डम इंस्टीट्यूट के निदेशक टुल्कू शेरडर ने एक साक्षात्कार में बताया, 'आप तिब्बत के हों या भारतीय या फिर अमेरिकी अथवा किसी अन्य स्थान के, संसार के हर व्यक्ति का मन समान रूप से कार्य करता है। हम सभी प्रसन्नता को अंगीकार करने और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है। यही कारण है कि जो भी सार्वभौमिक है वो वास्तविक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि किये जा सकने वाले आनंद और कष्ट के स्रोतों का ज्ञान उपलब्ध उपलब्ध करा सकता है।'

यही कारण है कि बुद्ध और अन्य संतों ने स्वयं को महान वैज्ञानिक साबित किया और मानव जीवन के सार्वभौमिक भावों को इस प्रकार समझा कि दूसरों को ज्ञान देते समय सभी ने उनके भाव को एक जैसा मानते हुए आत्मसात किया। हमें आज भी आशा है कि इस पथ के अंतिम छोर पर कुछ सार्थक उपलब्धि प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए यदि हमें एक स्वादिष्ट व्यंजन मिले फिर चाहे वो पौष्टिक हो या न हो लेकिन इसे ग्रहण करने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां समस्या ये है कि हमें कहां रुकना है कब रुकना है या किसी दूसरे विकल्प को खोजना है, यही योग का लक्ष्य है। फिल्म में एक अन्य साक्षात्कार में डा. आनंदा बालयोगी जो योग विशेषज्ञ और पुडुच्चेरी के डॉक्टर हैं का कहना है, 'यदि जीवन में आपके पास जो भी है आप उससे संतुष्ट हैं' तो आपको अचानक से अनुभव होगा कि आपकी पत्नी या पति बच्चे और घर सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार आप स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन जाते हैं और आपका जीवन अद्भुत बन जाता है।' एक अन्य साक्षात्कार में पद्म विभूषण पुरस्कार से सुशोभित अमेरिका के सैंटा फे के योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ डा. डेविड फ्रॉले कहते हैं, 'योग हमें आत्मान्वेषण में सहायता करता है। ये अपने अपने आपको इस प्रकार से जानने की अपेक्षा करता है कि हम अपने बारे में दूसरों की व्याख्या या राय से प्रभावित न हों बल्कि अपनी वास्तविकता को स्वयं जानने में समर्थ हों।' हमारा वैदिक दर्शन हमें सिखाता है कि ये पूरी सृष्टि एक प्रकार के परमसुख से जन्मी है और इस परमानंद, शांति, प्रसन्नता और बोधषक्ति का अतिरेक ही स्वयं को ब्रम्हांड के रूप में प्रदर्शित करता है। योग हमें अपने भीतर संचित आनंद को जागृत अवस्था में लाना सिखाता है ताकि हम अपने भीतर और अपने चारों ओर इसे अनुभव कर सकें, और हमें वाह्य विश्व में इसे ढूंढने की आवश्यकता ही न रहे।'

श्रेष्ठ कंटेंट पर ही रहता है हमारा पूरा जोरः अनुष्का

● मैं दर्शकों और समीक्षकों द्वारा 'पाताल लोक' के निर्माण में हमारे परिश्रम के लिए दिये गए प्यार और प्रशंसा से अभिभूत हूं

बॉलिवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके शो 'पाताल लोक' की सफलता का मुख्य कारण इसकी विषय-सामग्री अर्थात कंटेंट की श्रेष्ठता ही है। उन्होंने इस सीरीज़ का निर्माण अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ मिलकर अपने प्रोडक्शन हाउस 'क्लीन स्लेट्ज़' के बैनर तले किया है।

इस शो का सृजन किया है सुदीप शर्मा ने और इसे दर्शकों और समीक्षकों की अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया निरंतर मिल रही हैं। लोगों ने इसकी सफलता का पूरा श्रेय अनुष्का को दिया है जो केवल 25 वर्ष की आयु में एनएच10 जैसी सुपर हिट फिल्म की निर्माता बनी थीं।

अनुष्का ने बताया, 'मैं दर्शकों और समीक्षकों द्वारा 'पाताल लोक' के निर्माण में हमारे परिश्रम के लिए दिये गए प्यार और प्रशंसा से अभिभूत हूं। इसकी सफलता का पूरा श्रेय इसकी कंटेंट को जाता है। उनके अनुसार आज के युग में सर्वश्रेष्ठ कंटेंट ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापदंड है और कर्णेश और मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि हम दर्शकों को देखने के लिए ऐसा कुछ रोचक और मनोरंजक दें जो उन्होंने इससे पहले न देखा हो।'

उन्होंने आगे कहा, 'एक निर्माता और अभिनेता के रूप में मैंने नवोन्मेषी और रोचक कोलाहलरहित कहानी देने का प्रयास किया है। मैंने और कर्णेश ने अनुभव किया कि शीघ्र ही कंटेंट परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि हमारा सामना वैष्विक कंटेंट से होना अवश्यंभावी हो गया है। मैंने जो भी सीखा उसे यहां देने का प्रयास किया है।'

अभिनेत्री के अनुसार इस शो की सफलता से कंपनी की कंटेंट को अधिक महत्व देने की नीति सही साबित हुई है, 'हम नए और युवा प्रोडक्शन हाउस हैं लेकिन फिर भी हमने इस दिशा में सार्थक प्रयास किये और हमारी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर निर्धारित कंटेंट सही साबित हुई। क्लीन स्लेट्ज़ में हम सभी के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है हमनें कंटेंट को सही ढंग से प्रस्तुत किया। हमारे शो पाताल लोक की सफलता ने हमारे विश्वास, योजना और प्रयासों को सही साबित किया है।' उन्होंने आगे बताया, 'हम ये क्षण अपनी पूरी टीम के साथ साझा करते हैं जिन्होंने हमारे विचारों को समझा और इस प्रक्रिया में हमें बहुत कुछ सिखाया भी।' इस दिशा में सुदीप के श्रेष्ठ नियोजन भी फलीभूत हुए हैं और हम सभी उनके कार्य की सराहना करते हैं।'

अनुष्का ने आगे कहा कि शो के निर्देशक प्रोसीत रॉय और अविनाश अरुण धवारे ने हमारी स्क्रिप्ट को परदे पर इतनी सटीकता और परिपक्वता से उतारा है और इसके अलावा जयदीप अहलावत, नीरज कबि, अभिषेक बनर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी, नीहारिका, जगजीत, गुलपनाग, ईक्ष्वाक, आसिफ बसरा जैसे प्रतिभाषाली कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से स्क्रिप्ट को परदे पर उतारकर शो को चार चांद लगाने का काम किया है।

सुनील शेट्टी ने 90 के दशक की फोटो शेयर की

भाषा। मुंबई

बॉलीवुड के माचो मैन सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर 90 के दशक की अपनी फोटो शेयर की है। सुनील शेट्टी अपने फैन्स को पर्सनल लाइफ के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। वह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनका मनोरंजन भी करते रहते हैं। सुनील शेट्टी ने 90 के दशक की अपनी एक शर्टलेस फोटो शेयर की है। इस फोटो में उन्हें कलरफुल पैंट्स पहने देखा जा सकता है और हाथों की मसल्स को वह फ्लॉन्ट करते दिखाई दे रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने लिखा यह 90 के दशक की फोटो है। सुनील ने जैसे ही अपनी यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की फैन्स उनकी बॉडी की तारीफ करने लगे। समीरा रेड्डी ने लिखा ओह माई गॉड सुपर हॉटी। वहीं, प्रतीक बब्बर ने उनके लिए किंग वाला इमोजी बनाया। इसके अलावा सनी भसह ने लिखा कि आप ही असली ही-मैन हैं। 100 फीसदी नैचुरल। सच में आप लोगों को इंस्पायर करते हैं।

फुकरे थ्री में दिखेगी कोविड-19 की दुनिया : निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा

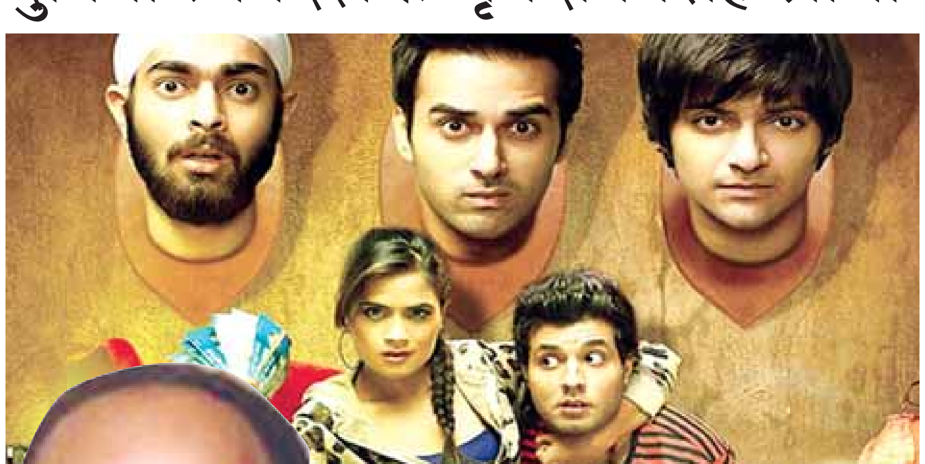

भाषा। मुंबई

फिल्मकार मृगदीप सिंह लांबा ने कहा कि वह अपनी हिट फ्रैंचाइजी फिल्म फुकरे के तीसरे भाग में कोविड-19 की स्थिति पर कुछ हिस्सा डालने पर विचार कर रहे हैं। लांबा ने कहा कि पुराने दो भाग - 2013 में आई फुकरे और 2017 में आई फुकरे रिटर्न्स की ही तरह तीसरे भाग में जबर्दस्त मनोरंजन होगा और यह फिल्म एक सामाजिक संदेश देगी। फरहान अख्तर और रीतेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट इस फ्रैंचाइजी की निर्माता है। निर्देशक ने कहा कि उनकी टीम फुकरे थ्री में वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति और लॉकडाउन पर बात करने का विचार कर रही है। लांबा ने पीटीआई-भाषा से कहा, इस हिस्से में भी एक कड़ा संदेश होगा जिसे लोग याद रखेंगे और यह मजाकिया अंदाज में परोसा जाएगा। मूल कहानी में इसका (कोविड-19 के बारे में) जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा,, लेकिन अभी हम विचार ही कर रहे हैं। हमने इस पर चर्चा की है। हमें इसे (कोविड-19 स्थिति) कैसे दिखाना है, इसे लेकर सावधानी बरतनी होगी ताकि यह जबर्दस्ती जोड़ा हुआ न लगे। उन्होंने कहा कि अगर टीम फुकरे थ्री के लिए कोरोना वायरस की स्थिति के इर्द-गिर्द विचार बुनने में कामयाब नहीं हुई तो वह पूरी फिल्म ही इस विषय पर केंद्रित रखने की योजना बना रहे हैं। लांबा ने कहा, हम कोविड-19 पर या वर्तमान स्थिति को मजाकिया अंदाज में दिखाने के बारे में विचार कर रहे हैं। हम जरूर इस बारे में कुछ करेंगे। हम कुछ न कुछ बना लेंगे। हमें सही विचार की तलाश है। निर्देशक ने बताया, हमने लॉकडाउन से पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था और अब हम फोन से जुड़े हुए हैं। हमारे पास कहानी तैयार है और लेखन 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। हम पटकथा पर काम कर रहे हैं जो लगभग पूरी हो चुकी है। स्थिति सामान्य होने के बाद हम इस पर आगे की योजना बनाएंगे।

दो महीने जॉर्डन में फंसे रहने के बाद भारत लौटे फिल्म निर्माण दल के 58 सदस्य

भाषा। कोच्चि

कोविड-19 लॉकडाउन के चलते करीब दो महीने तक जॉर्डन में फंसे रहने के बाद अभिनेता पृथ्वीराज समेत एक मलयालम फिल्म के निर्माण दल के 58 सदस्य शुक्रवार को एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए यहां पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विमान अम्मान से नई दिल्ली होते हुए यहां पहुंचा। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन सभी को पृथक-वास में भेज दिया गया है। यह दल आडुजीवितथम फिल्म की शूटिंग करते समय दक्षिण जॉर्डन के वादी-ए-रम में फंस गया था। जॉर्डन सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने के बाद 27 मार्च को फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी।

दीपिका चिखलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की बचपन की तस्वीरें

भाषा। मुंबई

सीरियल 'रामायण' में सीता का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं दीपिका चिखलिया इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने अपने बचपन की यादों को ताजा किया। दीपिका ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की ब्लैक एंड व्हाइट दो तस्वीरें शेयर की है। इस तस्वीर में दीपिका ने साड़ी पहन रखी है। उन्होंने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें साझा करते हुए लिखा-'बचपन कितना प्यारा होता है...यह मुझे जगजीत भसह जी की गजल याद दिलाता है, 'लौटा दो मुझे मेरे बचपन का सावन... वो कागज की कश्ती।' किसे पता था कि ये बच्ची बड़ी होकर एक दिन ऐतिहासिक सीरियल में काम करेगी!' दीपिका चिखलिया की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं 1988 में प्रसारित होने वाली रामानंद सागर की 'रामायण' का लॉकडाउन में दूरदर्शन पर पुन: प्रसारण किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ था। वहीं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस धारावाहिक को इन दिनों स्टार प्लस पर प्रसारित किया जा रहा है। दीपिका 'रामायण' के अलावा भी कई धारावाहिकों और फिल्मों में भी नजर आई। दीपिका चिखलिया आखिरी बार आयुष्मान खुराना की 'बाला' फिल्म में नजर आई थी और जल्द ही स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और देश की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू की बायोपिक में नजर आयेंगी।

प्रीति जिंटा ने लॉकडाउन में फिट रहने के लिए ढूंढा तरीका

मुंबई। बॉलीवुड की बबली गर्ल प्रीति भजटा ने लॉकडाउन में फिट रहने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। कोरोना वायरस के कारण सभी बॉलीवुड सितारे इन दिनों लॉकडाउन हैं और क्वारंटीन में समय बिता रहे हैं। सभी कलाकार फिट रहने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं, प्रीति जिंटा ने लॉकडाउन में एक्सरसाइज का नया तरीका ढूंढ निकाला है। प्रीति जिंटा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह लैंप के सहारे वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। प्रीति जिंटा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। प्रीति जिंटा के इस वीडियो में उनकी एनर्जी और अंदाज देखने लायक है। इसमें प्रीति येलो टी-शर्ट और ब्लैक टाइट्स में नजर आ रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए प्रीति भजटा ने लिखा, क्वारंटीन के दौरान फिट रहने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। साधारण शब्दों में, जुगाड़ ऐसा होता है। प्रीति के इस वीडियो के लिए फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं, साथ ही इसे अब तक दो लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है।

रिलीज हुआ अमिताभ व आयुष्मान की फिल्म 'गुलाबो-सिताबो' का मजेदार ट्रेलर

भाषा। मुंबई

अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' काफी समय से चर्चा में हैं। फिल्म का मजेदार ट्रेलर शुक्रवार को जारी हो चुका है और यह फिल्म 12 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। कॉमेडी-ड्रामा पर आधारित इस फिल्म की कहानी एक मकान मालिक और किराएदार के बीच चलने वाले खींचतान पर आधारित है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म के इस मजेदार ट्रेलर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा-'मिलिए मिर्ज़ा से, जिन्हें अपनी हवेली से बेइंतहा प्यार है, ट्रेलर जारी। फिल्म में अमिताभ एक खानदानी नवाब की भूमिका में हैं, जिनकी हवेली में आयुष्मान खुराना किरदार के रूप में रहने आते हैं। फिल्म के इस ट्रेलर को अभिनेता आयुष्मान खुराना ने भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा-'मिलिए बांके से, होशियारी की नदी इन्ही के यहां से बहती है। ट्रेलर आ गया। ट्रेलर की शुरुआत में आयुष्मान खुराना कहते हैं-'यार एक बात समझ नहीं आ रही यहां अलुमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहां मिर्ज़ा की चप्पले पड़ी थी, यहां दो बकरियां बांध रखी है साला हमारा ही बल्ब मिला निकलने के लिए!' इसके बाद एक बूढ़ी महिला हंसते हुए कहती है अरे बल्ब नहीं निगोड़ी कोई जायदाद चोरी हो गई। इस पर अमिताभ कहते हैं-'लेकिन जायदाद वाली सूरत कहां!' फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अमिताभ यानी मिर्ज़ा की पुरानी हवेली में आयुष्मान यानी बांके किरदार के रूप में रहने आता है। बाद में अमिताभ चाहते हैं कि आयुष्मान घर खाली कर दे। क्योंकि वह किराया नहीं बढ़ा रहे हैं और आयुष्मान घर खाली नहीं करते और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। फिल्म का ट्रेलर बहुत मजेदार है,जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देगा। इसके साथ ही आज ही निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया है। हाल ही में फिल्म का मोशन लोगो भी जारी हुआ था जिसे सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत 'गुलाबो सिताबो' का अमेजन प्राइम वीडियो पर 12 जून, 2020 को विश्व स्तर पर प्रीमियर होगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना पहली बार एक दूसरे के साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं। शूजित सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म 'गुलाबो सिताबो' को रॉनी लाहिड़ी और शील कुमार ने प्रोड्यूस किया है।